चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 27 अप्रैल-03 मई 2015 | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

कोयला खदानों की नीलामी

कालिख ही कालिख

कोयले की कालिख ही ऐसी है कि लाख चतुराई करें, तो भी एक-दो धब्बे लगने तय हैं. इस बार भी कोयले ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. कोयले की कालिख ने यूपीए सरकार का तख्त पलट दिया था. कैग ने एक लाख 86 हज़ार करोड़ रुपये के नुक़सान की बात कही थी, लेकिन चौथी दुनिया शुरू से इस घोटाले को 26 लाख करोड़ रुपये का बताता रहा है. बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने सारे आवंटन रद्द कर दिए थे. अब दोबारा से उन कोयला खदानों की नीलामी शुरू हो गई है. कोयला खदानों के आवंटन से लाखों करोड़ रुपये मिलने की बात की जा रही है. यह सही भी है. कई सारी खदानों की नीलामी सफलतापूर्वक हो चुकी है, खूब सारा पैसा भी मिल रहा है. लेकिन कोयला तो आख़िर कोयला है, सो विवाद यहां भी पैदा हो गया है. मामला गारे पाल्मा खदान के आवंटन और फिर उसे रद्द करने का है. यह आवंटन जिंदल पॉवर को हुआ था. कारण बोली कम लगना है, लेकिन यह सरकारी तर्क है. इसे दूसरे नज़रिये से देखें, तो कई तथ्य ऐसे हैं, जिन पर ग़ौर करने की ज़रूरत है. कई ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है. और, अगर जवाब मिल जाए, तो शायद भ्रष्टाचार के नए तरीके और नए पन्ने एक बार फिर देश की जनता के सामने आएंगे.

शशि शेखर

छत्तीसगढ़ की गारे पाल्मा 4/2-3 कोयला खदान की नीलामी रद्द की जा चुकी है. 19 फरवरी, 2015 को इस खदान की सबसे बड़ी बोली जिंदल पॉवर लिमिटेड ने लगाई थी. बाकायदा जिंदल पॉवर लिमिटेड को इस खदान का आवंटन भी हो गया, लेकिन इस बीच इस आवंटन को लेकर कुछ सवाल शुरू हो गए. मसलन, जहां अन्य कंपनियों ने इस तरह की कोयला खदानें 1,000 रुपये प्रति टन की बोली लगाकर ली थीं, वहीं जिंदल को गारे पाल्मा 4/2-3 खदान बेस प्राइस 100 रुपये से मात्र आठ रुपये अधिक पर मिल गई. इस तथ्य को थोड़ा और सरल तरीके से समझने की ज़रूरत है. शिड्यूल-2 में शामिल कोयला खदानों की बोली लगाने के लिए सरकार ने प्रति टन 100 रुपये का बेस प्राइस रखा था. यानी कोई भी कंपनी इससे कम की बोली नहीं लगा सकती थी. एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी ध्यान में रखने लायक है कि कोयले की यह खदान अनुसूची-दो (शिड्यूल-2) में शामिल थी. यानी इसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाना था. अब इस अनूसूची में शामिल कोयला खदानों की नीलामी जीतने वाली कंपनियों के मूल्य पर ध्यान दें. तोकीसुड उत्तरी खदान एस्सार पॉवर एमपी लिमिटेड ने 1,010 (प्लस 100 रुपये बेस प्राइस) रुपये की बोली लगाकर हासिल की. यानी कोयला का मूल्य हुआ 1,110 रुपये प्रति टन. ट्रांस दामोदर खदान दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 840 रुपये प्रति टन की बोली लगाकर हासिल की. जेपी वेंचर्स लिमिटेड ने अमेलिया उत्तरी खदान 612, जीएमआर छत्तीसगढ़ ने तालाबीरा-1 खदान 378 रुपये और सीईएससी ने सरिसाटोली खदान 370 रुपये प्रति टन की बोली लगाकर जीती. लेकिन, सबसे अहम और दिलचस्प बोली लगी गारे पाल्मा 4/2-3 खदान की. इसे मात्र आठ रुपये प्रति टन (प्लस 100 रुपये बेस प्राइस यानी मात्र 108 रुपये प्रति टन) की बोली लगाकर जिंदल पॉवर लिमिटेड ने हासिल कर लिया.

अब सवाल है कि गारे पाल्मा मामले में ऐसा क्या हुआ कि मात्र आठ रुपये प्रति टन की बोली लगाकर जिंदल पॉवर ने उक्त खदान हासिल कर ली? जाहिर है, यह एक ऐसा सवाल है, जिस पर विवाद होना तय था. सो हुआ. मीडिया में रिपोर्ट आई, तो सरकार ने इस पर क़दम उठाने की बात कही. अंत में क़दम यह उठाया गया कि तत्काल प्रभाव से सरकार ने गारे पाल्मा 4/2-3 का आवंटन रद्द कर दिया. यह अलग बात है कि जिंदल ने सरकार के इस क़दम का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. अदालत ने अभी इस मामले में स्टे भी दे दिया है. कोयला मंत्रालय ने आवंटन रद्द करने के बारे में यह कहा कि इस कोयला खदान की बोली कम थी. फिर सवाल पैदा होता है कि यह बोली कम थी या फिर बोली जानबूझ कर कम लगाई गई थी? और अगर जानबूझ कर, सोच-समझ कर बोली कम लगाई गई थी, तो इसके लिए दोषी कौन है? सवाल यह भी है कि नीलामी में शामिल अन्य कंपनियों ने बोली लगाई भी या नहीं या सिर्फ़ जिंदल ने ही बोली लगाई और बाकी कंपनियां चुपचाप बैठी रहीं? बोली न लगाने वाली कंपनियां कौन हैं? क्या सरकार ऐसी कंपनियों से भी पूछताछ करेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जिनका जवाब सामने आना चाहिए. वैसे इन सारे सवालों पर सरकार अब तक चुप है.

वैसे यह जानना दिलचस्प होगा कि 108 रुपये प्रति टन कोयले की असली कहानी क्या है? यह संभव कैसे हुआ और क्यों हुआ? पूरी कहानी कुछ यूं है. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले में गारे पाल्मा कोयला खदान है. कोयला मंत्रालय ने पावर यूज के लिए शिड्यूल-2 में छह कोयला खदानें शामिल की थीं. इनमें गारे पाल्मा 4/2-3 के अलावा तालाबीरा-1, सरिसाटोली, ट्रांस दामोदर, अमेलिया उत्तरी और तोकीसुड उत्तरी शामिल हैं. इन सभी...

(शेष पृष्ठ 2 पर)

पावर सेक्टर के लिए शिड्यूल 2 में शामिल कोयला खदान के ई ऑक्शन में किसने कितनी बोली लगाई (बेस प्राइस 100 रुपये)

क्वालिफाइड बीडर्स में एक ही समूह की तीन कंपनी

	क्वालिफाइड बीडर्स	इनीशियल ऑफर प्राइस में कोटेड प्राइस	सबसे ऊंची बोली
1.	अडानी पावर महाराष्ट्र लि.	501	नीलामी में हिस्सा नहीं लिया
2.	जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लि.	0	नीलामी में हिस्सा नहीं लिया
3.	जिंदल इंडिया थर्मल पावर लि.	505	नीलामी में हिस्सा नहीं लिया
4.	जिंदल पावर लिमिटेड (64849)	450	108 (एफ) 19.2.2015
5.	जिंदल पावर लिमिटेड(65465)	452	नीलामी में हिस्सा नहीं लिया
6.	जिंदल पावर लिमिटेड(65476)	451	नीलामी में हिस्सा नहीं लिया

बटाईदार किसानों की पुकार कब सुनेगी सरकार | P-3

ऑपरेशन राहत कामयाबी की मिसाल | P-5

ये क़ानून कोढ़ में खाज जैसे हैं | P-10

कालिख ही कालिख

पृष्ठ 1 का शेष

कोयला खदानों की ई–नीलामी समय पर हो गई. तालाबीरा खदान 478, सरिसाटोली खदान 470, ट्रांस दामोदर खदान 940, अमेलिया उत्तरी 712, तोकीसुड उत्तरी 1,110 और गारे पाल्मा 4/2–3 108 रुपये प्रति टन की अंतिम बोली पर नीलाम हो गई. अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक ही काम यानी बिजली उत्पादन के लिए एक ही शिड्यूल में शामिल खदानों के मूल्य में कितने का अंतर है. 108 रुपये बनाम 1,110 रुपये. यानी एक ही तरह का कोयला कहीं 1,110 रुपये प्रति टन बिका, तो कहीं 108 रुपये. ध्यान देने की बात है कि 108 रुपये प्रति टन कोयला गारे पाल्मा 4/2–3 का बिका, जिसे जिंदल पॉवर लिमिटेड ने खरीदा. 19 फरवरी, 2015 को गारे पाल्मा खदान की नीलामी हुई. इस खदान की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए छह कंपनियां क्वॉलीफाइड हुई थीं. इनमें भी अकेले जिंदल पॉवर लिमिटेड के तीन बिड थे. तीन अन्य कंपनियां थीं, अडानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड, जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड और जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड. लेकिन, इस खदान के लिए बोली लगाई सिर्फ़ एक कंपनी ने. वह कंपनी थी, जिंदल पॉवर लिमिटेड. अडानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड ने इनिशियल प्राइस ऑफर (आईपीओ) में 501 रुपये प्रति टन का प्राइस कोट किया था, लेकिन उसने बोली में हिस्सा नहीं लिया. जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड ने आईपीओ में कोई प्राइस कोट नहीं किया और न नीलामी में बोली लगाई. जिंदल इंडिया थर्मल पॉवर लिमिटेड ने आईपीओ में 505 रुपये का प्राइस कोट किया था, लेकिन अंत में वह भी बोली लगाने की प्रक्रिया से अलग रही.

इस तरह पूरी बोली प्रक्रिया में बचे केवल तीन बिड. यानी जिंदल पॉवर लिमिटेड (64849), जिंदल पॉवर लिमिटेड (65465) और जिंदल पॉवर लिमिटेड (65476). इनमें जिंदल पॉवर लिमिटेड (65465) ने आईपीओ में 452 रुपये का प्राइस कोट किया था, वहीं जिंदल पॉवर लिमिटेड (65476) ने आईपीओ में 451 रुपये का प्राइस कोट किया था, लेकिन अंत में इन दोनों ने भी बोली में हिस्सा नहीं लिया. अब बची जिंदल पॉवर लिमिटेड (64849). इसने आईपीओ में 450 रुपये प्रति टन का प्राइस कोट किया था. 19 फरवरी को जब नीलामी शुरू हुई, तब बाकी कंपनियों ने बोली नहीं लगाई और अकेले जिंदल पॉवर लिमिटेड (64849) ने बोली लगाते हुए 108 रुपये प्रति टन (इसमें बोली सिर्फ़ आठ रुपये की ही लगी, क्योंकि 100 रुपया बेस प्राइस था) के हिसाब से यह खदान हासिल कर ली. ग़ौरतलब है कि गारे पाल्मा 4/2–3 खदान का रिजर्व अधिक है (कोयला अधिक है). फिर भी इसके लिए इतनी कम बोली लगी और बाकी की अन्य कंपनियों ने बोली ही नहीं लगाई. एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह कि 19 फरवरी को सुबह 11 बजे इसकी नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई और 12 बजकर 21 मिनट पर ख़त्म भी हो गई. यानी यह नीलामी दो घंटे से भी कम चली. दूसरी ओर तालाबीरा–1 जैसी खदान के लिए सुबह 11 बजे से रात आठ बजे तक नीलामी प्रक्रिया चली और उसे ओजीएमआर छत्तीसगढ़ ने सौ रुपये बेस प्राइस पर 378 रुपये की बोली लगाकर कुल 478 रुपये प्रति टन के हिसाब से हासिल किया था. आख़िर गारे पाल्मा मामले में ऐसा क्या हुआ था कि नीलामी प्रक्रिया महज दो घंटे में ख़त्म हो गई. जाहिर है, इस सवाल के पीछे कोई न कोई कहानी तो ज़रूर छिपी हुई है. अब इसका जवाब कब सामने आता है, यह देखने वाली बात होगी.

ध्यान देने की बात यह है कि इस बार पॉवर सेक्टर की कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया काफी आक्रामक थी. एक–एक खदान के लिए कई–कई कंपनियों ने घंटों तक बोली लगाई. ऐसे में गारे पाल्मा 4/2–3 के लिए सिर्फ़ एक कंपनी द्वारा बोली लगाना संदेह तो पैदा करता ही है. यह समझ से परे है कि आख़िर बाकी कंपनियों ने बोली क्यों नहीं लगाई? छोटे रिजर्व वाली खदानों से जहां सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिला है, वहीं गारे पाल्मा 4/2–3 (जिसका रिजर्व बहुत अधिक है) के लिए इतना कम पैसा क्यों मिला? तालाबीरा–1 खदान जीएमआर छत्तीसगढ़ को मिली और यह खदान उसकी कोयला ज़रूरत को 5.45 फ़ीसद ही पूरा करती है, लेकिन जीएमआर ने गारे पाल्मा 4/2–3 के लिए इनिशियल प्राइस ऑफर में शून्य रुपया प्राइस कोट किया था और वह नीलामी प्रक्रिया में भी शामिल नहीं हुई. सवाल है कि क्या उसे और कोयले की ज़रूरत नहीं थी? क्या गारे पाल्मा जीएमआर छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी? अगर उसे गारे पाल्मा खदान मिल जाती, तो उसकी कोयला ज़रूरत आसानी से पूरी हो सकती थी, लेकिन फिर भी उसने नीलामी प्रक्रिया से बाहर रहना क्यों ज़रूरी समझा?

इसी तरह गारे पाल्मा 4/2–3 खदान की नीलामी में अगर अडानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड ने हिस्सा लिया होता और उसे यह खदान मिल जाती, तो उसकी कोयला ज़रूरत का 93 फ़ीसद हिस्सा पूरा हो सकता था. और, अगर जिंदल इंडिया थर्मल पॉवर लिमिटेड ने नीलामी में हिस्सा लिया होता, तो उसकी कोयला ज़रूरत का 98 फ़ीसद हिस्सा पूरा हो सकता था. अब सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि इन कंपनियों ने अपनी ज़रूरत पूरी करने के बजाय जिंदल पॉवर लिमिटेड के लिए यह कोयला खदान छोड़ दी? वह भी ऐसा तब हुआ, जब इन कंपनियों को मालूम था कि नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा न लेने पर उनकी जमानत राशि, जो करोड़ों में थी, जब्त हो जाएगी. सवाल यह भी है कि क्या इसके लिए इन कंपनियों के बीच अंदरखाने कोई समझौता हुआ था? वैसे सरकार ने अब तक यह तो नहीं कहा है कि इस सबके पीछे ऐसा कुछ हुआ है, जो कायदे से नहीं होना चाहिए था. लेकिन, सरकार ने यह ज़रूर माना कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल तो सरकार ने आवंटन रद्द कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उस राज से पर्दा उठेगा कि आख़िर जिंदल पॉवर लिमिटेड के अलावा बाकी तीन कंपनियों ने अपनी ज़रूरत को दरकिनार रखते हुए नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा क्यों नहीं लिया? जाहिर है, अगर सरकार इस मामले की पूरी जांच कराए, तो ऐसे कई राज खुल सकते हैं, जो भ्रष्टाचार के नए तरीकों को सामने लाएंगे. ऐसे तरीके, जो एक ईमानदार प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद भी भ्रष्टाचार के नए रास्ते बना देते हैं. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

1,110 बनाम 108 रुपये

जिन 45 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई है, उनमें से अब तक कई खदानों का आवंटन किया जा चुका है. छत्तीसगढ़ की गारे पाल्मा 4/2–3 खदान जिंदल पॉवर लिमिटेड (जेपीएल) ने 108 रुपये प्रति टन की सबसे कम बोली पर हासिल की. पॉवर सेक्टर के लिए सुरक्षित खदानों की बोली कम इसलिए है, क्योंकि सरकार ने उनकी अंतिम विक्रय सीमा निर्धारित कर दी थी. उसके पीछे सरकार ने यह दलील दी थी कि अगर इन सुरक्षित कोयला खदानों की अंतिम विक्रय सीमा निर्धारित नहीं की गई, तो बिजली उत्पादन का खर्च बढ़ जाएगा और बिजली महंगी हो जाएगी. लेकिन, जिंदल पॉवर लिमिटेड (जेपीएल) को आवंटित की गई खदान सरकार के इस दावे को संदेह के घेरे में ला खड़ा करती है और कई सवालों को भी जन्म देती है. पहला यह कि क्या बिजली के नाम पर राष्ट्रीय संसाधनों को औने–पौने दामों में बांटने के बावजूद जनता को सस्ती बिजली मिल रही है? दूसरा यह कि गारे पाल्मा 4/2–3 खदान केवल 108 रुपये प्रति टन की बोली पर क्यों नीलाम हुई, जबकि उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित गारे पाल्मा 4/5 खदान अब तक की सबसे महंगी बोली पर नीलाम हुई और अन्य सुरक्षित खदानों पर भी इससे काफी ऊंची बोली लगी है, जैसे तोकीसुड उत्तरी खदान 1,110 रुपये प्रति टन की बोली पर नीलाम हुई और एस्सार पॉवर लिमिटेड को मिली. जेपीएल को मिली गारे पाल्मा 4/2–3 की कुल क्षमता 155 मिलियन टन है, जो नीलामी के लिए रखी गई किसी भी खदान से अधिक है. वहीं गारे पाल्मा खदानों का कोयला सबसे उत्तम गुणवत्ता वाला है, तो उसे पॉवर सेक्टर के इस्तेमाल के लिए ही क्यों सुरक्षित रखा गया? क्या पॉवर सेक्टर के लिए कम गुणवत्ता वाली खदानों को नहीं रखा जा सकता था? साथ ही इन खदानों के दो अन्य दावेदारों अडानी पॉवर और ओजीएमआर का बोली से हट जाना भी संदेह पैदा करता है. ■

इन सवालों के जवाब ज़रूरी हैं

1. 108 रुपये की बोली से सरकार को कितना नुक़सान हो सकता था या हुआ?
2. क्वॉलिफाइड बिडर्स, जैसे अडानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड, ओजीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड, जिंदल इंडिया थर्मल पॉवर लिमिटेड ने आख़िर बोली क्यों नहीं लगाई?
3. जिंदल समूह की तीन कंपनियों को मौक़ा क्यों दिया गया?
4. क्या जिंदल और बाकी कंपनियों के बीच कोई गुपचुप समझौता हुआ?
5. क्या सरकार इस पूरे मामले की जांच कराकर सच सामने लाएगी?

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 08
दिल्ली, 27 अप्रैल–03 मई 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड, हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

राफेल सौदे पर सवाल

दिलीप चेरियन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राफेल सौदे के निर्णय पर भारत में कयासों का दौर जारी है. लोगों का कहना है कि यह निर्णय अचानक नहीं लिया गया, जैसा कि दिखाई दे रहा है. इस निर्णय तक पहुंचने से पहले भारतीय अधिकारियों और उनके फ्रांस के समकक्षों के बीच गुपचुप बैठकें भी हुईं, ताकि प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक तौर पर इस सौदे के लिए घोषणा कर सकें. यह भी साफ़ है कि इस सौदे का निर्णय मोदी का था और प्रधानमंत्री कार्यालय इस मुद्दे पर अपनी पकड़ बनाए हुए था. सूत्रों का मानना है कि जब उच्च स्तर पर इस सौदे का निर्णय हो गया, तो इसमें रुचि लेने वाले लोग धराशायी हो गए. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और रक्षा सचिव आरके माथुर ने पहले ही इस बात का संकेत दिया था कि वे राफेल समझौते का गतिरोध समाप्त होने तक रूसी सू–30 जहाज को अपग्रेड करने के विरोध में नहीं थे. राजनीतिक नेतृत्व और कुछ नए आइडिया वाले बाबुओं के कारण इस सौदे का मार्ग प्रशस्त हुआ.

सफलता के मायने

दिल्ली के बाबुओं की सूची में मुख्य आर्थिक सलाहकार काफी अच्छे और सम्मानजनक स्थान पर हैं. वह अपने सहयोगियों के साथ वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण और आर्थिक अपडेट्स तैयार कर रहे हैं, जिन्हें संसद में प्रस्तुत करना है. यह हाई प्रोफाइल और काफी ज़िम्मेदारी वाला काम है. मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम, जिन्हें मोदी अमेरिका से लाए थे, ने बैंक स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के सामने यह स्वीकार किया कि वह आईएएस परीक्षा में असफल हो गए थे. उन्होंने बताया कि सफल व्यक्तियों के लिए ज़िंदगी की राहें हमेशा आसान नहीं होतीं. उन्होंने कहा कि मध्य वर्ग के लोगों के लिए आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण करना सपने जैसा होता है, लेकिन यह सफलता का एकमात्र सूचक नहीं है.

पीएमओ सर्वोपरि!

यह दिल्ली के लिए उचित नहीं है कि मोदी सरकार में पीएमओ एकमात्र पॉवर हाउस है, लेकिन यह भी सत्य है कि पीएमओ इस बात को सुनना पसंद नहीं करता. इसके कई उदाहरण हैं कि सरकार के सभी कार्य पीएमओ द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं. बाबुओं की शिकायतों से संबंधित 6,000 से अधिक फाइलें पीएमओ की स्वीकृति के इंतज़ार में लंबित हैं, जबकि उक्त फाइलें जल्द निपटाने के लिए विभागीय मंत्रियों एवं अधिकारियों ने प्रार्थना भी की है. जब कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने पीएमओ के इस रवैये को पॉलिसी पैरालाइज कहकर ट्वीट किया, तो पीएमओ सजग हुआ. अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके मिश्रा ने ऐसे किसी मामले से इंकार कर दिया है. उनका कहना है कि फाइलों पर सुचारू रूप से काम हो रहा है और निर्णय को लेकर पीएमओ पर केंद्रीयकरण का आरोप लगाकर मोदी की आलोचना जायज नहीं है. हालांकि, मिश्रा का यह बयान लोगों के अंदर उठने वाली चिंताएं शांत नहीं कर सकता.

dilipcherian@gmail..com

फ़सल मुआवज़े को लेकर भेदभाव

बटाईदार किसानों की पुकार कब सुनेगी सरकार

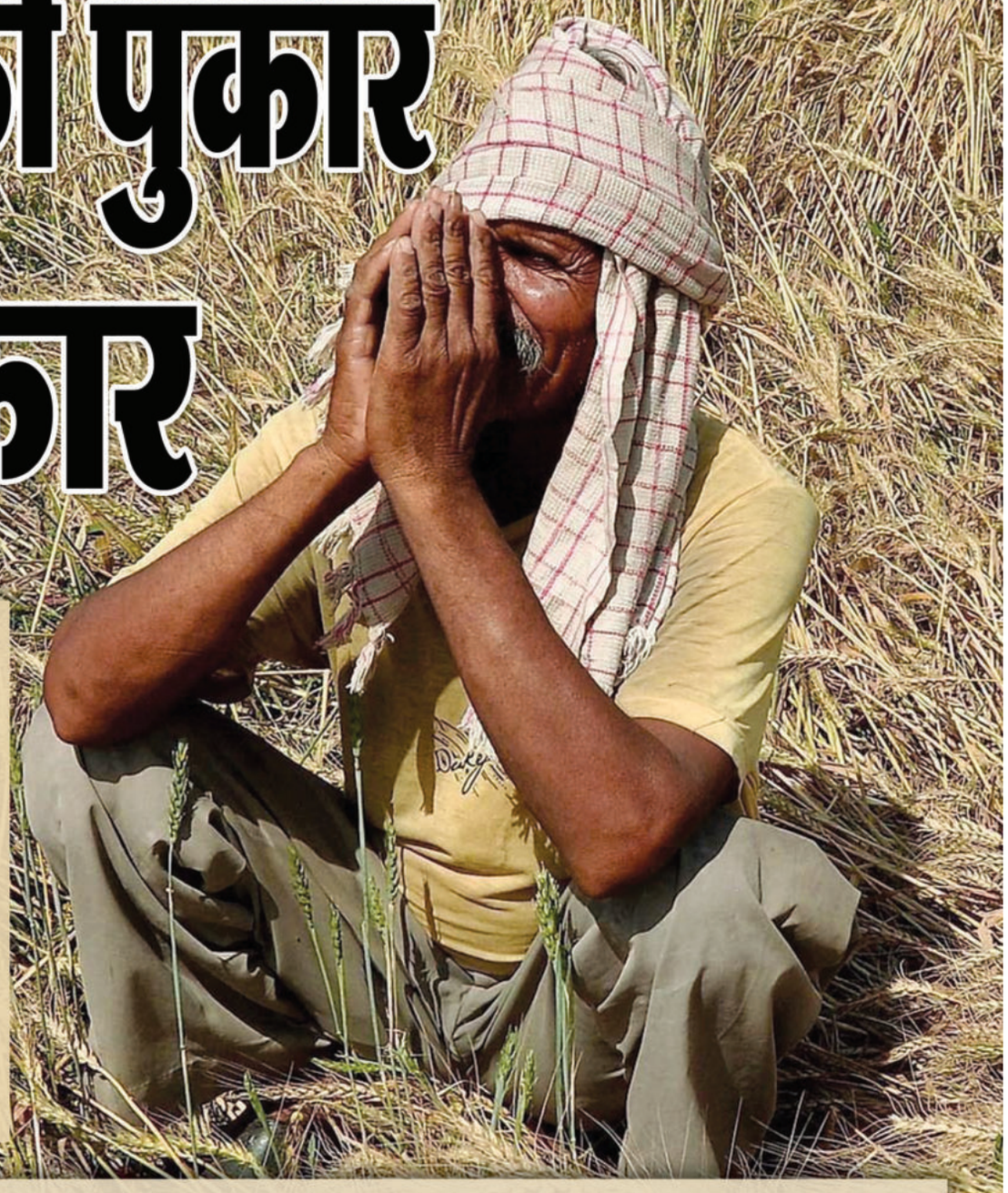

चैत्र और बैसाख के महीने में अमूमन तेज़ पछुआ हवाएं चलती हैं. इन हवाओं की रफ्तार से किसानों की खुशी का काफ़ी गहरा रिश्ता है. हालांकि, पिछले दिनों उत्तर भारत के कई राज्यों में पुरवा हवाओं के साथ तेज़ बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को निराश कर दिया. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रबी की फ़सल तैयार होने पर घरों में मांगलिक कार्य होते हैं, लेकिन इस बार उन करोड़ों किसानों की आंखों में आंसू हैं और जेब खाली है, जिन्होंने खेतों में दिन-रात मेहनत कर बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद की थी. बेमौसम बारिश के चलते उन बटाईदार किसानों को अब यह चिंता सता रही है कि वे ज़मीन मालिक को मनठीका या नगदी कहां से देंगे. केंद्र सरकार ने फौरी तौर पर भले ही किसानों के लिए राहत का ऐलान किया हो, लेकिन इसका फ़ायदा उन किसानों को मिलेगा, जिनके पास भू-स्वामित्व का दस्तावेज़ है. पेश है, देश में बटाई पर खेती करने वाले मूल किसानों की समस्याओं पर चौथी दुनिया की यह ख़ास रिपोर्ट...

अभिषेक रंजन सिंह

मार्च-अप्रैल का महीना देश के करोड़ों किसानों के लिए कहर बनकर टूटा. खेतों में खड़ी फ़सलें बेमौसम बारिश की वजह से तबाह हो गईं. अपनी महीनों की मेहनत बेकार जाते देख देश सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या भी कर ली. बारिश, ओलावृष्टि और तेज़ हवाओं ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में किसानों की रबी की फ़सलों को काफ़ी नुक़सान पहुंचाया. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पूरे देश में लाखों हेक्टेयर खड़ी फ़सल बर्बाद हो गई. यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने राज्यसभा में दी. उनके मुताबिक़, 27 लाख हेक्टेयर फ़सल का नुक़सान अकेले उत्तर प्रदेश में हुआ है. इसी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़सलों को हुए नुक़सान से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए मुआवज़ा राशि में 50 फ़ीसद इजाफ़ा करने का ऐलान किया. इसके अलावा उन्होंने मुआवज़े के मानदंडों में भी बदलाव करने का निर्णय किया है. पहले जहां 50 फ़ीसद फ़सल के नुक़सान होने पर ही कोई किसान मुआवज़े का हक़दार होता था, वहीं अब 33 फ़ीसद फ़सल के नुक़सान पर भी उसे मुआवज़ा दिया जाएगा. किसानों पर आई इस विपदा के बाद केंद्र सरकार ने भले ही उनके लिए मुआवज़े का ऐलान किया हो, लेकिन मुआवज़े के नाम पर किसानों के साथ किस तरह भेदभाव किया जाता है, यह जानना बेहद ज़रूरी है.

बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आंधी से तबाह होने वाली फ़सलों के लिए सरकारें मुआवज़े का ऐलान करती हैं, लेकिन इसका लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनके पास भू-स्वामित्व सिद्ध करने संबंधी दस्तावेज़ होते हैं. एक अध्ययन के मुताबिक़, जिन लोगों के पास ख़ुद की ज़मीन है, उनमें से ज़्यादातर लोग स्वयं खेती नहीं करते हैं. वे अपने खेत बटाई, अधबटाई और मनठीका (मनहुंडा) पर लगा देते हैं. बटाई पर अपनी ज़मीन देने वाले किसानों को कुल कृषि लागत का आधा हिस्सा देना होता है, जबकि मनठीका (मनहुंडा) पर अपनी ज़मीन देने वाले भू-स्वामियों का एक रुपया भी ख़र्च नहीं होता है. ऐसे भू-स्वामी निजी व्यस्तताओं, शहरों में प्रवास और खेती में अरुचि की वजह से अपनी ज़मीनें सालाना 15-20 हज़ार रुपये या 10 से 15 मन प्रति बीघा अनाज पर स्थानीय छोटे या भूमिहीन किसानों को दे देते हैं. वह किसान अपने पूरे परिवार के साथ उन खेतों में साल भर कड़ी मेहनत करता है, अपनी पूंजी लगाकर अनाज पैदा करता है और अपने परिवार का भरण-पोषण करता है. दुर्भाग्यवश, अगर उसकी फ़सल बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नष्ट हो जाती है, तो ऐसे किसानों की हालत काफ़ी दयनीय हो जाती है. फ़सलों के तबाह होने पर केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किसानों को मिलने वाली राहत योजनाओं का सर्वाधिक लाभ भू-स्वामियों को मिलता है, न कि बटाईदार किसानों और खेतिहर मज़दूरों को. बैंकों से मिलने वाले केसीसी ऋण का लाभ भी बटाई और मनठीका पर खेती करने वाले किसानों को नहीं मिलता. बटाईदार किसानों की यह समस्या देशव्यापी है. इसे लेकर देश में आंदोलन भी होते हैं, लेकिन सरकार किसानों की इस मांग के प्रति गंभीर नहीं दिखती है. इसका एक बड़ा कारण है, देश में किसान राजनीति का लगातार कमज़ोर होना. देश की सभी राजनीतिक पार्टियां किसानों की ताक़त से वाकिफ़ हैं, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि ख़ुद किसानों को अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, उनमें एकजुटता का अभाव है, जिसका फ़ायदा राजनीतिक दल उठाते रहे हैं. पिछले महीने चौथी दुनिया का यह संवाददाता बिहार के खगड़िया ज़िले में था. उस समय बिहार में सरकारी स्तर पर धान ख़रीद हो रही थी. जिन किसानों के पास भू-स्वामित्व के दस्तावेज़ थे, उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने में कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा. वहीं दूसरी ओर नगदी बटाई, अधबटाई और मनी बटाई (मनठीका) पर खेती करने वाले किसानों को धान बेचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. विभागीय निर्देशों के मुताबिक़, सरकारी धान क्रय केंद्रों पर उन्हीं किसानों का धान ख़रीदने का नियम है, जिनके पास मालगुजारी (लगान) की अद्यतन रसीद हो. खगड़िया ज़िले के गोगरी प्रखंड अंतर्गत राटन पंचायत के पैक्स अध्यक्ष फणिभूषण यादव ने बटाई पर खेती करने वाले किसानों की इस समस्या को गंभीर बताते हुए सरकार से उनके लिए विशेष प्रावधान करने की मांग की. चौथी दुनिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि ज़िले में बेमौसम बारिश की वजह से फ़सलों को काफ़ी नुक़सान पहुंचा है. लिहाज़ा सरकार को चाहिए कि वह बटाईदार किसानों के लिए भी राहत की घोषणा करे. भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता सह सांसद प्रतिनिधि नीतीश कुमार सिंह ने किसानों को शीघ्र राहत पहुंचाने की मांग सरकार से की. इसके अलावा, उन्होंने पांच वर्षों तक मालगुजारी (लगान) माफ़ करने की मांग ज़िला प्रशासन से की.

राटन गांव के 36 वर्षीय किसान सुजान सिंह की मानें, तो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए किसान महज़ एक चुनावी मुद्दा है. सरकार के पास किसानों की भलाई के लिए कोई दीर्घकालिक उपाय नहीं है. बेमौसम बारिश से हुए फ़सलों को नुक़सान के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ़ फ़सलों की क्षति का जायजा ले रही है, लेकिन देश के अंतिम किसान तक उसकी राहत का फ़ायदा कब पहुंचेगा, यह कोई नहीं बता सकता. किसान रामू यादव ने निराशा ज़ाहिर करते हुए कहा कि खगड़िया ज़िले में मक्के की सर्वाधिक खेती होती है. पिछले साल मक्के की क़ीमत कम रहने की वजह से किसानों को बाज़ार की मार झेलनी पड़ी. इसलिए किसानों ने काफ़ी उम्मीद के साथ गेहूं की खेती की, लेकिन इस बार उन्हें प्रकृति की मार झेलनी पड़ी. नतीजतन, ज़िले के किसान आज दोराहे पर खड़े हैं.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के पोलित ब्यूरो सदस्य सह अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मज़दूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव धीरेंद्र झा ने चौथी दुनिया से बातचीत करते हुए बताया कि बिहार में क़रीब 70 फ़ीसद किसान नगदी बटाई, मन बटाई और अधबटाई पर खेती करते हैं. ऐसे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नष्ट हुई फ़सलों पर कोई मुआवज़ा नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास ख़ुद की ज़मीन नहीं है. यह समस्या सिर्फ़ बिहार के किसानों की नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों किसानों को इससे दो-चार होना पड़ता है. उनके अनुसार, केसीसी ऋण भू-स्वामियों के अलावा, बटाईदारों को भी मिलना चाहिए. हालांकि, नाबार्ड की ओर से बटाई पर खेती करने वाले किसानों को अधिकतम 50 हज़ार रुपये केसीसी ऋण देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसकी प्रगति काफ़ी धीमी है. ऐसे में किसानों को स्थानीय महाजनों से ऊंची ब्याज़ दर पर क़र्ज़ लेना पड़ता है. बेमौसम बारिश और उससे फ़सलों को हुए नुक़सान के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार में किसान आत्महत्या की घटनाएं तो फ़िलहाल नहीं हुई हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से इस दिशा में ठोस पहल नहीं गई, तो बिहार भी किसान आत्महत्या का केंद्र बन सकता है.

बारिश और आंधी की वजह से रबी फ़सलों को हुए नुक़सान के बारे में खगड़िया के ज़िलाधिकारी राजीव रौशन ने चौथी दुनिया से ख़ास बातचीत में बताया कि ज़िले के सभी प्रखंडों में गेहूं, मक्का, दलहन और आम की फ़सलों को हुए नुक़सान का आकलन कर उसकी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी गई है. उनके अनुसार, ज़िले में गेहूं और मक्का की 45 फ़ीसद फ़सल बर्बाद हुई है. किसानों को राहत मुहैया कराने के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और ज़िला प्रशासन किसानों को हरसंभव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. कृषि ऋण माफ़ करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि क़र्ज़ माफ़ी का फ़ैसला अंतत: सरकार को करना है, लेकिन ज़िले के किसानों पर बैंकों द्वारा ऋण वसूली के लिए अनावश्यक दबाव न बनाया जाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं. ■

.....arsingh@chauthiduniya.com

केंद्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत देश के क़र्ज़दार किसानों के बाबत मांगी गई एक जानकारी के विषय में मंत्रालय ने जवाब दिया कि वर्ष 2014 तक देश के 11.69 करोड़ किसानों ने 6,44000 करोड़ रुपये का क़र्ज़ लिया. वर्ष 2009-10 में किसानों पर 3,25000 करोड़ रुपये का क़र्ज़ था, जो वर्ष 2012 तक 5,90532 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. यानी तीन वर्षों के भीतर ही किसान दो गुने क़र्ज़दार हो गए. सूचना के अधिकार के तहत मांगी जानकारी के अनुसार, देश में सर्वाधिक क़र्ज़दार किसानों की संख्या आंध्र प्रदेश में है और किसानों की आत्महत्या के मामले में भी यह पहले स्थान पर है. दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, यहां किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक किसानों की संख्या 87,09348 है. कर्नाटक में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक किसानों की कुल संख्या 57,11916 है.

इन बिंदुओं पर ग़ौर करे सरकार

- बेमौसम बारिश से तबाह हुई फ़सलों के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवज़ा दिया जाए.
- गेहूं के समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस दिया जाए.
- 50 फ़ीसद फ़सल बर्बाद होने पर ही मुआवज़ा देने का प्रावधान ख़त्म करते हुए, नई मुआवज़ा नीति घोषित की जाए.
- बटाईदार किसानों के लिए सरकार विशेष राहत पैकेज का ऐलान करे.
- फ़सल की बर्बादी के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को बीस लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए.
- खेतों का सर्वे कर फ़सलों के नुक़सान का आकलन किया जाए.
- आत्महत्या करने वाले बटाईदार किसानों के परिजनों को जोत भूमि की गारंटी दी जाए.
- तबाह हुई नगदी फ़सलों के नुक़सान की भरपाई की जाए.
- किसानों का एक साल का बिजली का बिल माफ़ किया जाए.
- पांच वर्ष तक मालगुज़ारी (लगान) की वसूली न हो.

फ़सल बीमा को लेकर किसान जागरूक नहीं

भारत जैसे विशाल देश में हर साल किसी न किसी तरह की प्राकृतिक विपदाएं आती रहती हैं, जिनसे फ़सलों को काफ़ी नुक़सान होता है. बीमा एक ऐसी योजना है, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत मिल सकती है. इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि फ़सल बीमा के प्रति किसानों में जागरूकता की काफ़ी कमी है. एसोचैम और स्कायमेट के एक अध्ययन के अनुसार, देश भर में 20 फ़ीसद से भी कम किसान बीमित हैं. नतीजतन, मौसम की अनिश्चितताओं की वजह से उन्हें काफ़ी नुक़सान झेलना पड़ता है. हैरानी की बात यह है कि देश में क़रीब 80 फ़ीसद किसानों को फ़सल बीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं है. इस अध्ययन में कहा गया है कि ग़ैर-बीमित किसानों में से 46 फ़ीसद तो ऐसे किसान हैं, जिन्हें फ़सल बीमा के बारे में जानकारी है, लेकिन उनकी रुचि इसमें नहीं है. 24 फ़ीसद किसानों का कहना है कि यह सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं है. 11 फ़ीसद किसानों का कहना है कि वे समय पर बीमा के प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकते, इसलिए उनकी दिलचस्पी बीमा कराने में नहीं है. ■

उत्तर प्रदेश

आपदा से अधिक राहत का सदमा

प्रभात रंजन दीन

बे मौसम बारिश और ओलावृष्टि से मर रहे किसानों को मुआवज़ा देने के मामले में खुद को फंसता देखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने औपचारिक रूप से प्रदेश में आपदा घोषित कर दी है और सरकारी अधिकारियों–कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करते हुए उन्हें राहत के काम में लग जाने का निर्देश दिया है. प्राकृतिक आपदा के कारण फ़सलों को पहुंचे नुक़सान से किसानों को जितना सदमा लगा है, उससे अधिक सदमा उन्हें सरकारी मुआवज़े का चेक देखकर लग रहा है. किसानों को 50 रुपये, 70 रुपये तो कहीं सौ रुपये के चेक मुआवज़े के बतौर दिए जा रहे हैं. किसान वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के इस किसान प्रेम पर जब प्रदेश और देश स्तर पर प्रबल विरोध शुरू हुआ, तब राज्य सरकार ने अपनी साख बचाने का एहतियाती काम शुरू किया. अब सरकार कह रही है कि किसानों को सौ–पचास नहीं, बल्कि डेढ़ हज़ार रुपये देंगे. जानकार कहते हैं कि सरकार की इस पैंतरेबाजी में किसान प्रेम कहीं नहीं है, यह केवल सियासी पेशबंदी है.

चौथी दुनिया के पिछले अंकों में भी किसानों के प्रति राज्य सरकार की बेरुखी और नौकरशाही की बेजा हरकतों के बारे में ख़बरें छपी हैं. प्राकृतिक आपदा के शिकार किसानों को मुआवज़ा देने में किस तरह भेदभाव बरता जा रहा है और उनकी बर्बाद फ़सलों के एवज में प्रदेश सरकार किसानों को किस तरह भीख बांट रही है, इसे भी तथ्यों के साथ प्रकाशित किया गया है. इसके बावजूद समाजवादी सरकार की खाल पर कोई असर नहीं पड़ा और ऐसे तमाम नए–नए वाकये सामने आते ही जा रहे हैं. फैज़ाबाद में तो किसानों को 50 रुपये, 63 और 84 रुपये तक के चेक बांटे गए हैं. राहत के ये चेक उन किसानों को दिए गए हैं, जिनकी फ़सल बेमौसम बारिश की वजह से तबाह हो गई है और जो ख़ुद मौत की दहलीज पर खड़े हो गए हैं. इन चेकों के वितरण का समाजवादी प्रेम उजागर होते ही सरकार ने लेखपालों को निलंबित करने की छुटभैया कार्रवाई की और उन चेकों को वापस लेकर उन्हें फिर से जारी करने का ऐलान कर अपनी झेंप मिटाई. लेकिन, सरकार के ही एक अधिकारी ने कहा कि वापस लिया हुआ चेक कभी बड़ी धनराशि के साथ वापस नहीं आएगा. शासन और प्रशासन की अराजकता का हाल यह है कि राहत राशि बांटने में भी तंत्र के बंदरों का पूरा ध्यान लगा हुआ है. इस कोशिश में कब्रिस्तानों को भी खेत घोषित कर मुआवज़े की राशि खाई–पकाई जा रही है. राहत राशि की बंदरबांट के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि हुई है, जिसमें कब्रिस्तान के नाम पर भी चेक बना दिए गए हैं.

फैज़ाबाद की रुदौली तहसील के वाजिदपुर गांव के किसान मोहम्मद साबिर प्रकृति की मार से तबाह हो चुके हैं. पांच बीघा से अधिक खेत में खड़ी फ़सल बर्बाद होने पर उन्हें मात्र 100 रुपये का मुआवज़ा दिया गया. उनके लिए राहत का यह चेक प्रकृति की मार से कहीं अधिक घातक साबित हो रहा है. रुदौली के ही एक अन्य किसान मोहम्मद शाहिद को उनकी तीन बीघा ज़मीन पर हुई बर्बादी के लिए 63 रुपये का चेक मिला है. मोहम्मद मुस्लिम को चार बीघा खेत पर हुई बर्बादी के लिए 84 रुपये का मुआवज़ा मिला है. ये नाम ख़ास तौर पर इसलिए भी दिए गए, क्योंकि इन मुस्लिम किसानों को दी गई राहत राशि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम तुष्टिकरण की असलियत है. अन्य जाति–धर्म के किसानों की तो बात ही अलग है. वाजिदपुर में हुई तबाही का जायजा लेने के लिए कभी कोई प्रशासन का आदमी, नायब तहसीलदार या लेखपाल नहीं आया, अन्य की तो बात ही छोड़ दें. इसी गांव में प्रधान का कब्रिस्तान है, जिसमें खेती नहीं होती. इस ज़मीन को भी खेत दिखाकर आठ लोगों के नाम पर चेक बनाकर बांट दिए गए. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने गांव का दौरा करने के बाद यह जानकारी दी और पुष्टि भी की.

विडंबना यह है कि फैजाबाद के ज़िलाधिकारी का कार्यभार देख रहे सीडीओ अरविंद मलप्पा बंगारी भी चेकों के ऐसे वीभत्स–वितरण को घनघोर लापरवाही का नतीजा मानते हैं, लेकिन इससे आगे वह भी कुछ नहीं कर सकते. किसानों के साथ हुए इस खिलवाड़ पर आला अधिकारी अपनी ग़लती मान रहे हैं. फैजाबाद के उप–ज़िलाधिकारी अशोक कुमार सिंह कहते हैं कि फसलों के नुक़सान के सर्वेक्षण के लिए लेखपालों की टीम लगाई गई थी, जिन्होंने ग़लती से कब्रिस्तान को भी खेत दिखा दिया और चेक काट दिए. सिंह ने कहा कि लेखपालों की बाकायदा हस्ताक्षर की हुई रिपोर्ट है. कब्रिस्तान की ज़मीन को खेती योग्य ज़मीन दिखाकर दिए गए चेकों की जांच कराई जा रही है. प्रशासनिक अराजकता का यह आलम है! उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की गाइडलाइन्स का कहीं कोई अनुपालन नहीं हो रहा है. एक–दो लेखपालों को निलंबित करने से जनता को धोखे में रखा जा सकता है, लेकिन परिदृश्य नहीं बदल सकता. यही वजह है कि राहत के नाम पर उन किसानों को भी खोज–खोज कर उनके नाम के चेक काटे गए, जो अर्सा पहले मर चुके हैं. यह प्रदेश के किसानों के साथ एक भद्दा मज़ाक है. मरहम के बजाय मज़ाक के वितरण का मज़ाकिया पहलू यह है कि प्राकृतिक आपदा के शिकार सात लाख 40 हज़ार किसानों के बीच अब तक 257.77 करोड़ रुपये की धनराशि बांट भी दी गई. यह कैसा वितरण हुआ होगा, उसकी भयावह कल्पना आप खुद–ब–खुद कर रहे होंगे. यह राशि बांटने के बाद अब प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से एक हज़ार करोड़ रुपये और मांगे हैं. जिस तरह सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं नेताओं–नौकरशाहों की लूट का रूटीन ज़रिया बनती रही हैं, उसी तरह इस बार की बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि भी मौजूदा सरकार के कई नेताओं और नौकरशाहों को समृद्ध बनाने वाली है. किसानों को 257.77 करोड़ रुपये की राहत राशि बांट दिए जाने की सूचना आधिकारिक है. इसी आधिकारिक सूचना का अगला हिस्सा यह है कि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के सात लाख 73 हज़ार किसानों अब तक 308 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित कर दी है. ये दोनों सूचनाएं एक ही दिन 13 अप्रैल को जारी हुईं. अब किसानों के बीच वितरित राशि 257.77 करोड़ रुपये मानी जाए या 308 करोड़ रुपये? इसे समझने का काम हम प्रदेश में सत्ता संभालने वाले समाजवादी लाल–बुझक्कड़ों पर ही छोड़ दें, तो ज्यादा अच्छा है. लेकिन, राहत राशि पाने वाले किसानों की संख्या का यह भ्रम भी सरकार ने ही फैलाया, जो एक ही दिन अलग–अलग गिनती बता रही है. यह सूचना प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हवाले से जारी की गई है. प्रदेश का सूचना तंत्र भी समाजवादी चाल में चल रहा है.

उस पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि राहत वितरण में लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों–कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह भी सरकार की उन्हीं घोषणाओं की तरह है, जो कभी अमल में नहीं लाई जातीं. अखिलेश ने आपदा घोषित करते हुए अधिकारियों–कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, ताकि किसानों तक राहत पहुंचाने का काम किसी भी दशा में प्रभावित न हो. बर्बाद किसानों तक राहत पहुंचाने के लिए बड़ी–बड़ी बातें कर रहे सत्ता के अलमबरदारों को किसानों की ज़मीनी हालत दिख नहीं रही और उसका आकलन करने की उनके पास कोई दृष्टि नहीं है. प्रकृति के साथ–साथ साहूकारों और बैंकों से लिए गए कर्ज उन्हें मौत का रास्ता दिखा रहे हैं. साहूकारों और बैंकों ने किसानों का जीना हराम कर रखा है. प्रदेश का क़रीब–क़रीब प्रत्येक किसान कर्ज के बोझ से दबा है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक अकेले ज़िले बुलंदशहर के तीन लाख से ज़्यादा किसानों पर बैंकों का साढ़े चार हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा का कर्ज है. अधिकतर किसानों ने बीज, खाद और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए कर्ज लिया था, लेकिन फसलों की बर्बादी ने उस कर्ज को उनकी मौत का सामान बना दिया. अब किसान कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं हैं. लाखों किसानों की ज़मीनें बैंकों में गिरवी रखी हुई हैं और ब्याज पर ब्याज लगते–लगते कर्ज की रकम दोगुनी–तिगुनी हो चुकी है. अकेले बुलंदशहर में पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का किसानों पर तीन हज़ार 780 करोड़ रुपये का कर्ज है. जबकि निजी बैंकों का किसानों पर 220 करोड़ और कोऑपरेटिव, भूमि विकास एवं ग्रामीण बैंकों का 515 करोड़ रुपये का कर्ज है. इस कर्ज की अदायगी भी उन्हें इसी सीजन में करनी थी. बैंक ऋण के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि बुलंदशहर के किसानों पर बैंकों का 40 अरब रुपये का कर्ज है, जबकि सहारनपुर एवं मेरठ मंडल के किसानों पर 178 अरब रुपये की देनदारी बकाया है. ऐसे में प्रदेश सरकार किसानों को 50 और 60 रुपये के चेक देकर अपना किसान प्रेम दर्शा रही है. ■

क़र्ज़ वसूली पर अड़े बैंक, आरबीआई का निर्देश ताक पर

किसानों की तबाही को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के सभी बैंकों को यह निर्देश दिया था कि प्रदेश के किसानों को पूर्व की वसूली लंबित रखकर नए ऋण दिए जाएं, लेकिन बैंकों ने आरबीआई के निर्देशों को ताक पर रख दिया और ऐसे आपदाकाल में भी वसूली के लिए वे किसानों पर दबाव बना रहे हैं. जबकि प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने भी प्रभावित किसानों के ऋण पुनर्निर्धारित करते हुए उन्हें नए ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश बैंकों को दिए थे. प्रदेश भर के ज़िलाधिकारियों से भी कहा गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि वसूली को लेकर किसानों का उत्पीड़न न हो. उल्लेखनीय है कि अतिवृष्टि–ओलावृष्टि से प्रदेश के प्रभावित किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 25 मार्च को प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किया था.

एक अखिलेश और एक अरविंद

प्राकृतिक आपदा के शिकार उत्तर प्रदेश के किसानों को 50 और 60 रुपये के चेक देकर अखिलेश यादव के राज में राहत देने की विचित्र व्यवस्था हो रही है, वहीं दूसरी तरफ़ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किसानों को प्रति एकड़ 50 हज़ार रुपये का मुआवज़ा देने का ऐलान करके लोगों को तुलना करने का मौक़ा दे दिया है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सरकार किसानों के साथ डटकर खड़ी रहेगी. यह किसी राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अब तक का सबसे अधिक मुआवज़ा है. केजरीवाल ने अन्य मुख्यमंत्रियों के सामने यह कहते हुए चुनौती भी फेंकी है कि दूसरे राज्यों की सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर सकतीं, जहां किसान खुदकुशी कर रहे हैं?

फैजाबाद की रुदौली तहसील के वाजिदपुर गांव के किसान मोहम्मद साबिर प्रकृति की मार से तबाह हो चुके हैं. पांच बीघा से अधिक खेत में खड़ी फसल बर्बाद होने पर उन्हें मात्र 100 रुपये का मुआवज़ा दिया गया. उनके लिए राहत का यह चेक प्रकृति की मार से कहीं अधिक घातक साबित हो रहा है. रुदौली के ही एक अन्य किसान मोहम्मद शाहिद को उनकी तीन बीघा ज़मीन पर हुई बर्बादी के लिए 63 रुपये का चेक मिला है. मोहम्मद मुस्लिम को चार बीघा खेत पर हुई बर्बादी के लिए 84 रुपये का मुआवज़ा मिला है.

feedback@chauthiduniya.com

अब सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आख़िर मीडिया ने इस मसले को क्यों नहीं दिखाया? क्या देश का मीडिया केवल सरकार की कमियां दिखाने के लिए है? क्या उसकी यह ज़िम्मेदारी नहीं है कि वह सरकार द्वारा किए गए अच्छे एवं साहसिक कार्यों की ख़बरें जनता तक पहुंचाए. लेकिन भारतीय मीडिया ने ऑपरेशन राहत में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उसे उसमें कुछ भी सनसनीखेज नज़र नहीं आया. ऐसा इसलिए, क्योंकि बचाए गए लोगों में से अधिकांश दक्षिण भारतीय ग़रीब, कामगार मुसलमान थे, जो रोजी–रोटी की तलाश में यमन तक पहुंच गए थे. मीडिया की नज़र में उनकी जान की कोई क़ीमत नहीं थी. बचाए जा रहे लोगों में न कोई धनाढ्य था और न मध्यम वर्ग का, जिनके लिए मीडिया पर तथाकथित सिविल सोसायटी के लोग आवाज़ उठाते.

ऑपरेशन राहत

कामयाबी की मिसाल

जनरल सिंह की यमन में मौजूदगी के चलते सैन्य बलों का हौसला बुलंद था. विदेश मंत्रालय, नौसेना, वायुसेना, जहाजरानी, रेल मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच बेहतरीन सामंजस्य की बदौलत बड़ी सहजता के साथ 10 दिनों तक चले इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया गया. एयर इंडिया ने ऑपरेशन में दो एयरबस–320 और एक बोइंग–777 विमान की तैनाती की थी. वहीं भारतीय सेना ने दो सी–17 ग्लोबमास्टर और वायुसेना ने सी–17 एस वायुयान तैनात किए थे.

नवीन चौहान

अजीब विडंबना है कि जब यमन में भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा था, उस समय भारतीय मीडिया प्रेस्टीट्यूड और प्रॉस्टीट्यूड की बहस में उलझा हुआ था. दूसरी ओर, विदेशी मीडिया ने भारत के ऑपरेशन राहत को जगह दी और इसके अगुवा विदेश राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह की जमकर तारीफ़ की. वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा, भारत ने बेहतरीन ढंग से बचाव कार्य की अगुवाई की और यमन में फंसे भारतीयों के अलावा 41 देशों के नागरिकों को भी बचाया. भारतीय दल द्वारा यमन से निकाले गए 960 विदेशी नागरिकों में मिस्र की 20 वर्षीय अलया गाबेर मोहम्मद भी शामिल हैं. उन्होंने खुद को यमन से निकालने के लिए भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया. अलया गाबेर मोहम्मद ने कहा कि आज वह भगवान और भारतीय सेना की वजह से जीवित हैं. भारत ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए जहाज भेजा, लेकिन उसने मानवीय निर्णय लेते हुए सभी देशों के नागरिकों को वहां से निकाला. भारत सरकार के इस निर्णय को इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा. 20 वर्षीय अलया यमन के एक होटल में काम करती थीं. उन्होंने यह बात अपनी फेसबुक वॉल पर लिखी. इसके बाद उनकी पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल हो गई. मिस्र के अधिकांश अख़बारों एवं समाचार चैनलों ने उनकी बातों को अपने यहां प्रमुखता से जगह दी.

अब सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आख़िर मीडिया ने इस मसले को क्यों नहीं दिखाया? क्या देश का मीडिया केवल सरकार की कमियां दिखाने के लिए है? क्या उसकी यह ज़िम्मेदारी नहीं है कि वह सरकार द्वारा किए गए अच्छे एवं साहसिक कार्यों की ख़बरें जनता तक पहुंचाए. लेकिन भारतीय मीडिया ने ऑपरेशन राहत में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उसे उसमें कुछ भी सनसनीखेज नज़र नहीं आया. ऐसा इसलिए, क्योंकि बचाए गए लोगों में से अधिकांश दक्षिण भारतीय ग़रीब, कामगार मुसलमान थे, जो रोजी–रोटी की तलाश में यमन तक पहुंच गए थे. मीडिया की नज़र में उनकी जान की कोई क़ीमत नहीं थी. बचाए जा रहे लोगों में न कोई धनाढ्य था और न मध्यम वर्ग का, जिनके लिए मीडिया पर तथाकथित सिविल सोसायटी के लोग आवाज़ उठाते. या फिर मीडिया जानबूझ कर यह ख़बर लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि यह नरेंद्र मोदी सरकार के एक साल से भी कम के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी. सोशल मीडिया में लोग कह रहे थे कि यह निर्णायक नेतृत्व है. हमने दुनिया को दिखा दिया कि भारत में भी विश्वस्तरीय नेता और नेतृत्व है. लेकिन, मीडिया जनरल वीके सिंह के ट्वीट को लेकर बाल की खाल निकालने में उलझा रहा और लोगों का ध्यान मुद्दे से भटकाता रहा.

यमन में भारत ने अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन यानी ऑपरेशन राहत चलाकर दुनिया को सकते में डाल दिया और यह साबित किया कि गृहयुद्ध से जूझ रहे देश से लोगों को सफलतापूर्वक और सकुशल बचाकर लाया जा सकता है. हालांकि, यमन में भारत के अलावा सात अन्य देश, जिसमें चीन, रूस एवं पाकिस्तान आदि भी शामिल हैं, बचाव कार्य में लगे थे. अमेरिका, फ्रांस एवं जर्मनी जैसे देशों ने भारत से यमन में फंसे अपने नागरिकों को बचाने का आग्रह किया. जिन 41 देशों के 960 नागरिकों को भारतीय दल ने बचाया, वे सभी भारत की ओर बहुत आशा और विश्वास से देख रहे थे. भारत ने किसी को भी निराश नहीं किया. यहां सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका सहित नाटो के सदस्य देशों को अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत की ओर देखना पड़ा. अमेरिकी सेना अभी भी इराक और अफगानिस्तान में मौजूद है. बावजूद इसके, वह यमन में फंसे अपने नागरिकों की मदद नहीं कर सकी और उन्हें वहां से बाहर निकालने में असमर्थ नज़र आई. ऐसे में इन सभी देशों ने विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन राहत की ओर रुख किया और अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकालने का अनुरोध किया. अमेरिका ने यमन में फंसे अपने नागरिकों के लिए जारी की गई एडवाइजरी में साफ़ तौर पर कहा कि भारत सना से जिबूती तक अमेरिकी नागरिकों को पहुंचाने में मदद करेगा. भारत यमन में फंसे भारतीयों और अन्य विदेशी नागरिकों को बचाने में सफल हुआ. इससे एक वर्ल्ड लीडर के रूप में भारत के कद में इज़ाफ़ा हुआ है, जिसका असर सीधे तौर पर भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे पर पड़ेगा.

25 मार्च को यमन में हवाई हमले शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के सुल्तान से फोन पर बात की और अपने नागरिकों को यमन से सुरक्षित वापस निकालने के लिए सहयोग मांगा. इसके बाद 31 मार्च को भारत सरकार ने विदेश राज्य मंत्री एवं पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह को अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन राहत की कमान देकर यमन भेजा. यह पहला मौक़ा था कि ऐसे ऑपरेशन की कमान किसी केंद्रीय मंत्री को सौंपी गई हो. जनरल सिंह ने 10 दिनों तक यमन में रहकर लोगों को वहां से सकुशल बाहर निकालने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. जनरल सिंह ने ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद लौटकर बताया कि वहां कई तरह की समस्याएं सामने आईं. एक जगह किसी समस्या का समाधान हो जाता था, तो कहीं और समस्या खड़ी हो जाती थी. ऐसे में काम कर रही सभी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर पाना बेहद जटिल था. सना के एयरपोर्ट पर हौती आतंकियों का कब्ज़ा था, लेकिन एयर कंट्रोल सऊदी अरब के नियंत्रण में था. भारत सरकार ने यमन से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राजधानी सना में रोज़ाना हवाई जहाज उतारने के लिए अनुमति मांगी.

जनरल सिंह की यमन में मौजूदगी के चलते सैन्य बलों का हौसला बुलंद था. विदेश मंत्रालय, नौसेना, वायुसेना, जहाजरानी, रेल मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच बेहतरीन सामंजस्य की बदौलत बड़ी सहजता के साथ 10 दिनों तक चले इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया गया. एयर इंडिया ने ऑपरेशन में दो एयरबस–320 और एक बोइंग–777 विमान की तैनाती की थी. वहीं भारतीय सेना ने दो सी–17 ग्लोबमास्टर और वायुसेना ने सी–17 एस वायुयान तैनात किए थे. यमन में सैनिक जहाजों को उतारने की अनुमति नहीं थी. इसलिए भारत ने इसके लिए अपने सी–17 ग्लोबमास्टर एयर क्राफ्ट का उपयोग किया, जिन पर गोलियों और छोटे हथियारों का असर नहीं होता है. उनकी मदद से हर दिन लोगों को सना से जिबूती पहुंचाया गया, वहीं नौसेना ने भी लोगों को अदन से जिबूती पहुंचाया, जहां से उन्हें भारत के लिए रवाना किया गया. नौसेना ने आईएनएस मुंबई, आईएनएस तर्कश, आईएनएस सुमित्रा जैसे जहाज ऑपरेशन में तैनात किए थे.

कब, कैसे, क्या हुआ

- 31 मार्च, 2015 को ऑपरेशन राहत प्रारंभ.
- 09 अप्रैल को मिशन पूरा.
- 5,600 लोग सुरक्षित निकाले गए.
- 4,640 भारतीय, 960 विदेशी.
- 41 अन्य देशों के नागरिक बचाए गए.
- 2,900 लोग राजधानी सना से विमान द्वारा निकाले गए.
- 2,700 लोग युद्धपोतों के ज़रिये बचाए गए, जिन्हें अदन, अल-हुदायदाह और अल-मुकल्ला नामक शहरों से निकाला गया.
- 18 विशेष उड़ानों के ज़रिये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया.

बचाव दल के लिए वहां काम कर रही एजेंसियों के साथ समन्वय बना पाना सबसे बड़ी परेशानी थी. एयरपोर्ट पर विद्रोहियों का कब्ज़ा था, लेकिन वहां के एयर स्पेस को सऊदी अरब कंट्रोल कर रहा था. ऐसे में एयरपोर्ट पर लैंड करना और तय समय सीमा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहां से निकालना एक बड़ी समस्या थी. वहां भी लोग किसी एक जगह एकत्र नहीं थे. एक समय सीमा के अंदर ही सिर्फ़ जा सकते थे और उसके बाद भारतीयों तक ख़बर पहुंचाना. जनरल वीके सिंह के वहां मौजूद रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि समस्याओं की सही समीक्षा करके उन पर त्वरित फ़ैसला ले लिया गया. आख़िरी दिन सना में एयरक्राफ्ट उतारने की अनुमति नहीं थी और वहां लोग फंसे हुए थे. ऐसे में जनरल सिंह को फ़ैसला लेना था कि छह सौ लोगों को वहां से निकाला जाए या वापस लौट जाया जाए. उस दिन हवाई अड्डे पर और कोई नहीं बचा था. जो लोग बचे थे, उनमें 140 विदेशी नागरिक थे. ऐसे में लोगों को बचाने के लिए उन्होंने जोखिम लिया, जो जायज था.

राहत अभियान की निगरानी के लिए जनरल सिंह जिबूती में डेरा डाले रहे. पहले दो दिनों तक सऊदी अरब से सना जाने की अनुमति नहीं मिली. फिर सरकार ने उनसे वहां अपने सैन्य जहाज ले जाने की बात कही. इसके बाद जब जनरल वीके सिंह सना गए और उन्होंने यमन के अधिकारियों से बातचीत की, तो बताया गया कि एयरपोर्ट पर विद्रोहियों का कब्जा है. उन्हें यह नहीं मालूम कि जो जहाज वहां उतर रहा है, वह अमेरिका का है, भारत का है या सऊदी अरब का है. यदि वहां गोलीबारी होती है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में लोगों को वहां से निकालने के लिए सैन्य जहाजों की जगह एयर इंडिया के विमानों को सना ले जाया गया. भारत सरकार ने पहले से ही दो विमान ओमान में तैयार कर रखे थे, जिन्हें सना ले जाया गया और वहां से लोगों को जिबूती लाया गया. लोगों को वहां से निकालने में दूसरी सबसे बड़ी समस्या इमीग्रेशन की थी. यमन से वापस आते वक्त एक्जिट वीजा की ज़रूरत होती है, जो वहां की इमीग्रेशन अथॉरिटी जारी करती है. एक मामला तो ऐसा था कि एक शख्स वहां विजिट वीजा पर गए थे और छह साल ज़्यादा रुक गए. इमीग्रेशन अधिकारियों ने कहा कि वे उसे कैसे एक्जिट वीजा दे सकते हैं? ऐसे में उन अधिकारियों को मनाना पड़ा. भारतीय दूतावास और जनरल वीके सिंह को इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. इसके अलावा एक समस्या यह थी कि भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी एडवाइजरी जनवरी में ख़त्म हो चुकी थी और लोग अंतिम समय तक हालात सुधरने का इंतजार करते रहे. जब हालात बेकाबू हो गए, तो लोग एक साथ बड़ी संख्या में यमन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए. जबकि एक बार में सीमित संख्या में ही लोगों को बाहर निकाला जा सकता था. ऐसे में किसी तरह विमानों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर यमन से बाहर निकाला गया.

नब्बे के दशक में खाड़ी युद्ध के दौरान हुए बचाव कार्य और इस बचाव कार्य में एक बड़ा फ़र्क़ था. इराक द्वारा कुवैत पर हमला किए जाने के बाद अमेरिका जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा था. अमेरिकी हमले की आशंका के उस दौर में इराक में रह रहे दूसरे देशों के लोगों को निकलने में इराकी प्रशासन भी मदद कर रहा था, लेकिन यमन में सरकार और प्रशासन नामक कोई चीज नहीं बची थी. राष्ट्रपति हादी ने सऊदी अरब में शरण ले रखी है. ऑपरेशन राहत ने हमारी सेनाओं के शौर्य और कौशल के अलावा भारत की कूटनीतिक शक्ति भी रेखांकित की है. इससे एक बार फिर यह साबित हुआ है कि मध्य–पूर्व को लेकर हमारी तटस्थता की नीति बिल्कुल सही है और हमें इसी दिशा में चलते रहने की ज़रूरत है. सऊदी अरब से हमारे मधुर संबंध काम आए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के शासक शाह सलमान से लगातार संपर्क में रहे. वहीं भारतीय खुफिया एजेंसियां अमेरिका और सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियों की मदद से हर पल की जानकारी भारतीय टीम को देती रहीं, जिससे बिना किसी नुक़सान के यह ऑपरेशन सफल हो सका. भारत सरकार ने इराक में फंसे भारतीयों को निकालने में हुई परेशानियों से सबक लिया था. इस बार उसने सही वक्त पर सही फ़ैसला लिया और एक केंद्रीय मंत्री को इस अभियान में लगाया, ताकि मौक़े पर ही आकस्मिक फ़ैसले लिए जा सकें. इसका फ़ायदा भी साफ़ तौर पर नज़र आया. ऐसे मामलों को नौकरशाहों के भरोसे छोड़ देने से कई चीजें ऐन मौक़े पर अटक जाती हैं. ऑपरेशन राहत को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने से दुनिया में भारत का कद बढ़ा है. आने वाले समय में यह भारत के वैश्विक शक्ति बनने की राह में एक बड़ा और महत्वपूर्ण क़दम साबित होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव

धन और बाहुबल की आजमाइश

पिछले विप चुनाव में जिस दल ने अधिक संख्या में धनबलियों-बाहुबलियों का समर्थन किया, उसका सफलता का प्रतिशत उतना ही अधिक रहा और कमोबेश सभी दल इसी पुराने फॉर्मूले को इस बार भी आजमा रहे हैं. उम्मीदवारों के चयन में धन-बल को तव्वजो दी जा रही है. सभी दलों ने 'लोहा से लोहा काटने' को विप चुनाव की सफलता का सूत्र मान लिया है, जिसके तहत जिन दलों में धन-बाहु की कमी है, उसमें सदस्यों को आयात करने पर जोर दिया जा रहा है.

अशोक सिंह

बैद्यनाथ प्रसाद

दिलीप जयसवाल

राजेश चौधरी

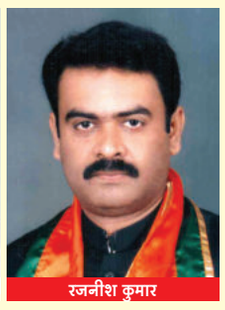
रजनीश कुमार

सचिदानंद राय

सलीम परवेज़

विनोद सिंह

प्रियदर्शी रंजन

बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय का चुनाव एक ऐसा अनोखा चुनाव है, जिसमें न ज्यादा शोर-शराबा होता है, न आम चुनाव की तरह सभाएं होती हैं, न रैलियां होती हैं, न बड़े नेताओं का भाषण होता है और न ही मुद्दे आधारित नारे गढ़े जाते हैं. अलबत्ता धनबल-बाहुबल का प्रदर्शन खुलेआम होता है, जो शायद ही किसी और चुनाव में होता होगा. हर-एक वोट को नोट से तौलने की कोशिश की जाती है. वोटों की बोली लगती है. हर वोट की एक तय राशि प्रत्याशियों द्वारा अपने सामर्थ्य के हिसाब से तय कर दिया जाता है और जो नोट से नहीं बिक रहे होते हैं, उन्हें बाहुबल से अपनी ओर करने की आजमाइश शुरू हो जाती है. हालांकि इस बार चुनाव आयोग ने पहल करते हुए वोटरों के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है. इससे धनबल के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. अन्यथा तय रेट पर सर्टिफिकेट जमा करने का दौर इस बार के चुनाव के लिए भी शुरू हो गया था. सर्टिफिकेट में फोटो नहीं रहने के कारण उसका बेजा इस्तेमाल धनबली प्रत्याशी करते आ रहे थे.

राजनीतिक पंडितों का एक खेमा यह मान कर चल रहा है कि विप चुनाव में जिस दल का अधिक सीटों पर कब्जा होगा, विधानसभा में भी सफलता के प्रतिशत की संभावना उसके लिए अधिक रहेगी. इसलिए सभी दल पुरजोर कोशिश में जुटे हैं कि विप चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर सफलता हासिल कर विरोधियों पर फाइनल से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल किया जाए. कुछ कमी रह जाए, तो वक्त रहते मुख्य मुकाबले से पहले ठीक-ठाक किया जा सके.

इस साल 24 सीटों के लिए जून के अंतिम सप्ताह या फिर जुलाई में होने वाले विप चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण है. हर दल विधानसभा चुनाव के मुख्य मुकाबले से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे विप चुनाव में खुद को आजमा लेना चाहता है. नीतीश कुमार का चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला चुनाव होगा. महाविलय का जमीन पर कितना असर पड़ा, वह इस चुनाव में साफ हो जाएगा. राजद और जदयू की मिलीजुली ताकत की पहली परीक्षा इसी चुनाव में हो जाएगी.

भाजपा यह आंकना चाहेगी कि दिल्ली की हार के बाद भी मोदी लहर कायम है या ठहर गई. लोजपा को भी आजमाने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन आजमाने के लिहाज से बड़ा अवसर मांझी के हम मोर्चा समर्थित उम्मीदवार व तीन सांसदो की पार्टी रालोसपा के पास ज्यादा होगी. हम मोर्चा समर्थित व रोलोसपा को पहली बार स्थानीय निकाय क्षेत्र के चुनाव में उम्मीदवार खड़े करने का मौका मिलेगा. एनडीए के बीच तालमेल की भी पहली परीक्षा इस चुनाव में हो जाएगी. देखना होगा कि भाजपा, लोजपा और रालोसपा मिलकर चुनाव में उतरते हैं या फिर तीनों अपनी-अपनी ताकत को आजमाएंगे.

हम मोर्चा दो-एक सीटों को झटककर चुनावी जीत का श्रीगणेश करना चाहेगी, तो रालोसपा के पास लोस चुनाव में मिले शत-प्रतिशत सफलता के जादू को भुनाने का मौका होगा. राजनीतिक पंडितों का एक खेमा यह मान कर चल रहा है कि विप चुनाव में जिस दल का अधिक सीटों पर कब्जा होगा, विधानसभा में भी सफलता के प्रतिशत की संभावना उसके लिए अधिक रहेगी. इसलिए सभी दल पुरजोर कोशिश में जुटे हैं कि विप चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर सफलता हासिल कर विरोधियों पर फाइनल से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल किया जाए. कुछ कमी रह जाए, तो वक्त रहते मुख्य मुकाबले से पहले ठीक-ठाक किया जा सके.

पिछले विप चुनाव में जिस दल ने अधिक संख्या में धनबलियों-बाहुबलियों का समर्थन किया, उसका सफलता का प्रतिशत उतना ही अधिक रहा और कमोबेश सभी दल इसी पुराने फॉर्मूले को इस बार भी आजमा रहे हैं. उम्मीदवारों के चयन में धन-बल को तव्वजो दी जा रही है. सभी दलों ने 'लोहा से लोहा काटने' को विप चुनाव की सफलता का सूत्र मान लिया है, जिसके तहत जिन दलों में धन-बाहु की कमी है, उसमें सदस्यों को आयात करने पर जोर दिया जा रहा है. मसलन, सारण लोकसभा क्षेत्र से जदयू के निवर्तमान विधान परिषद सदस्य धनबली सलीम परवेज को मुकाबला देने के लिए जदयू से ही आयातित सच्चितानंद राय को भाजपा समर्थन देने का मन बना रही है. सलीम परवेज व सच्चितानंद राय दोनों ही धनबली हैं. राजनीति का शौक पालने वाले राय कोलकाता के जाने-माने बिजनैसमैन हैं. बिहार में उनका ट्रांसपोर्ट का व्यावसाय व शिक्षण संस्थान हैं. धनबल-बाहुबल का इससे भी सटीक अंदाजा नालंदा जैसे स्थानीय निकाय से लगाया जा सकता है. नालंदा, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है और साथ में यह भी कि बिना उनके चाहे यहां कोई वार्ड कमिश्नर तक नहीं बन सकता. विधायक, सांसद, विधान परिषद चुनाव में तो नीतीश की इच्छा के बगैर फतह हासिल करना लगभग असंभव सा ही है. इसी नालंदा में पिछले चुनाव में जदयू के डॉ. कुमार पुष्पंजय को राजद-लोजपा समर्थित बाहुबली राजेश कुमार सिंह उर्फ राजू यादव ने पटखनी दी थी. राजू यादव की धमाकेदार जीत 2009 विप चुनाव के चर्चित जीत में से एक थी. नीतीश के गढ़ में बाहुबल के बूते राजद-लोजपा ने परचम लहरा दिया था. शिक्षा क्षेत्र के बड़े कारोबारी पुष्पंजय नीतीश के गढ़ में जदयू के निशान पर मात खा गए, तो इसकी वजह उनका बाहुबल में पिछड़ना व वोटों की खरीद में कंजूसी बताया गया. राजू यादव अपनी सीट को बचाने के लिए फिर मैदान में हैं, जहां इसका मुकाबला पुराने प्रतिद्वंद्वी से तो नहीं, मगर कई अन्य धनबलियों से हो सकती है. जमुई के जाने-माने समाजसेवी अशोक कुमार सिंह भी इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी अखाड़े में उतरने को तैयार हैं. संजय कुमार से उनका कड़ा मुकाबला होना तय माना जा रहा है. अशोक सिंह कहते हैं कि मुकाबला एकतरफा होगा और मेरी जीत तय है. मधुबनी में विनोद सिंह अपने विकास कार्यों और सुलभता के कारण काफी लोकप्रिय हैं और पूरे मनोयोग से चुनावी अखाड़े में उतर रहे हैं. विनोद सिंह कहते हैं कि जनता, नीतीश कुमार और अब लालू प्रसाद का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर जनता और इस क्षेत्र की सेवा का मौका मुझे जरूर मिलेगा.

ये कुछ-एक सीट तो बानगी मात्र हैं, पूरी फेहरिस्त ही धनबलियों-बाहुबलियों से अटी पड़ी है. चाहे वह सीवान का क्षेत्र हो, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र हो, पूर्वी चंपारण का क्षेत्र हो, आरा का क्षेत्र हो, नवादा का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र. सभी जगह मुख्य मुकाबला बाहुबलियों-धनबलियों बनाम बाहुबलियों-धनबलियों के बीच ही है. सीवान में वर्तमान विप सदस्य व शराब माफिया टुन्ना पांडेय का मुकाबला विधायिका कविता सिंह के पति दुर्दांत अजय सिंह से होने के आसार हैं. मुजफ्फरपुर में दौलतमंद, दबंग, दिलेर दिनेश सिंह का मुकाबला कई अन्य दौलतमंदों से होगा. पूर्वी चंपारण में साहेबगंज विधायक व विदेशों में कारोबार करने वाले राजू सिंह की पत्नी व विप सदस्य रेणु सिंह भाजपा के धनवान उम्मीदवार राजेंद्र गुप्ता आमने-सामने हो सकते हैं. दरभंगा में विप सदस्य मिश्रलाल यादव का भाजपा के अर्जुन साहनी के बीच पुराना जंग दोहराया जा सकता है. बालू घोटाला व 307 (हत्या के प्रयास) के दो मामले में नामजद नवादा क्षेत्र से विप सदस्य सलमान राजीव को टक्कर देने के लिए विरोधी इसी के कद के बाहुबली को मैदान में उतारने के फिराक में हैं. पटना क्षेत्र से विप सदस्य जदयू के बाल्मीकि सिंह को चुनौती के लिए भाजपा शराब माफिया भोला यादव को समर्थन देने पर विचार कर रही है. रुन्नी सैदपुर से विधायिका गुड्डी चौधरी के पति राजेश चौधरी भी उच्च सदन में जाने को बेचैन हैं. उनकी भिड़ंत भाजपा के व्यावसायी विप सदस्य बैद्यनाथ प्रसाद से हो सकती है. जाहिर है, जब थोक भाव में बाहुबली-धनबली भाग्य आजमाइश करेंगे, तो वोटरों के पास मोल-भाव का मौका भी होगा. सूत्र बताते हैं कि पिछले चुनाव में मुखिया व जिला परिषद सदस्यों का 15 से 25 हजार में प्रमाण-पत्र जमा कराया गया. वार्ड मेम्बर की कीमत भी 8 हजार रुपये से अधिक थी. सरपंच को 10 से 15 हजार रुपये की कीमत अदा की गई. पंचायत समीति के लिए भी यही राशी थी. सूत्रों की मानें तो इस दफा यह राशी बढ़कर डेढ़ से दोगुनी तक हो चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग की पहल के बाद इस पर अंकुश लगा है. चुनाव आयोग के फरमान को बेअसर करने के लिए संभावति प्रत्याशी दूसरा रास्ता अपना रहे हैं. चूंकि यह चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़े जाते, इसलिए राजनीतिक दलों को भी अपनी लाइन बदलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन इतना तय है कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले होने वाले इस चुनाव में राजनीतिक दलों की अपनी जमीनी ताकत का एक मोटा अंदाजा तो लग ही जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

उच्च सदन की गरिमा बचाना चाहता हूं : अनिल कुमार

बिहार बिल्डर ऐशोसिएसन के अध्यक्ष व चर्चित समाजसेवी अनिल कुमार आरा-बक्सर स्थानीय निकाय क्षेत्र से उच्च सदन में जाने हेतु भाग्य आजमाइश कर रहे हैं. उनका मुकाबला वर्तमान विधान परिषद सदस्य हुलास पांडेय से होने के आसार हैं. बाहुबल बनाम समाजसेवी के इस मुकाबले में जीत किसकी होगी, यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, मगर अनिल कुमार ने अपने जीत का दावा ठोक दिया है. अनिल कुमार से बातचीत के कुछ अंश :

राजनीति में आने व विधान परिषद के स्थानीय निकाय क्षेत्र का चुनाव लड़ने का फैसला आपने अचानक क्यों किया?

-जहां तक राजनीति में मेरे प्रवेश का सवाल है, कह सकते हैं की अचानक हुआ है, लेकिन मैं पिछले काफी अर्से से राजनीति पर नजर रखे हुए था. खासकर उच्च सदन पर. जिस उच्च सदन को अनेक महान लोगों ने सुशोभित किया, आज वहां अच्छे लोगों की कमी है. समाज के हर योग्य व्यक्ति को उच्च सदन की गरिमा बचाने का प्रयास करना चाहिए. मैं वही कर रहा हूं. बैठ कर आलोचना करने की जगह उच्च सदन को शुद्ध करने के लिए मैंने एक कदम भर बढ़ाया है. मतदाताओं के रुझान से लगता है कि चुनाव जीतने में कामयाब होंगे.

आपने आरा-बक्सर को ही चुनाव लड़ने के लिए क्यों चुना?

-यह मेरा गृह क्षेत्र है. किसी भी कार्य का आगाज घर से करना शुभ होता है और इस क्षेत्र को एक ऐसे नुमाइंदे की सख्त जरुरत है, जो समस्याओं को उच्च सदन में बेहिचक रख सके. गैंगवार, जातिवाद, नशाखोरी जैसे अनेक समस्याओं से घिरे इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव की जरूरत है. बदलाव तभी संभव होगा, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नुमाइंदे उनके दर्द को सदन में उठाने के साथ इसके निवारण के लिए संघर्ष कर सकेगें.

आप समाज सेवा के माध्यम से भी तो समस्याओं के खिलाफ संघर्ष कर सकते थे?

- सिर्फ खिलाफत से कुछ नहीं होने वाला. इसके लिए संवैधानिक ताकत चाहिए. संवैधानिक ताकत के सही इस्तेमाल से वर्षों में दूर होने वाली समस्याओं को महीनों में निपटाया जा सकता हैं. बशर्ते जनता के नुमाइंदे में काम करने की इच्छा हो.

स्थानीय प्राधिकार के संभावित उम्मीदवार

क्षेत्र का नाम	संभावित उम्मीदवार
गया, जहानाबाद व अरवरल	अनुज कुमार सिंह, सी.पी. यादव, कुंदन कुमार, मनोरमा देवी
कटिहार	अशोक कुमार अग्रवाल, हीमराज सिंह, शोयब आलम, श्रीकांत मंडल
सीतामढ़ी व शिवहर	बैद्यनाथ प्रसाद, दिलीप कुमार यादव, लक्ष्मी प्रसाद यादव, राजेश चौधरी
पटना	बाल्मीकि सिंह, भोला यादव, रीतलाल यादव.
मधुबनी	विनोद कुमार सिंह, कृष्ण देव मुखिया, देवेंद्र प्रसाद यादव, मनोज कुमार झा.
मुजफ्फरपुर	दिनेश प्रसाद सिंह, अब्दुल कयूम, अरविंद कुमार सिंह.
पुर्णिया, अररिया व किशनगंज	डॉ दिलीप कु. जायसवाल, अजीमुद्दीन, सैयद, गुलाम हुसैन, कृष्ण कुमार महतो.
आरा-बक्सर	हुलास पांडेय, अशोक कुमार, अनिल कुमार, विशेस्वर ओझा.
रोहतास कैमूर	कृष्णा कुमार सिंह, चंदन सिंह, मुन्ना राय, मनोज यादव
सीवान	टुन्ना पांडेय, इमरोज आलम, विंध्याचल प्रसाद, करणजीत सिंह.
बांका-भागलपुर	मनोज यादव, मुकेश कुमार, लखन पाठक, लक्ष्मण मंडल.
दरभंगा	मिश्रीलाल यादव, अर्जुन साहनी, सुशील कुमार सिंह, सुधीरकांत मिश्र.
सहरसा, मधेपुरा, सुपौल	मो. इसराइल, बलराम सिंह यादव, भूपनारायण यादव, जय प्रकाश सिंह.
वैशाली	राजेन्द्र राय, किशोर राय, राजेश राय, राजदेव राय.
नालंदा	राजेश कुमार सिंह, दिलीप चौधरी, कपिल देव प्रसाद, प्रवीण कुमार.
पश्चिम चंपारण	राजेश राम, पशुपति शाह, रानी तिवारी, सुरेन्द्र कुमार चंद्रा.
बेगुसराय-खगड़िया	रजनीश कुमार, डॉ. संजीव कुमार, उर्मिला ठाकुर, गजेंद्र मंडल, नीशा देवी.
पूर्वी चंपारण	रेणु सिंह, जदयू, रबीश रंजन, नंदकिशोर राय, कलावती देवी.
समस्तीपुर	रोमा भारती, राजद, संभावित उम्मीदवार- मोहन चौधरी, रंजन कुमार, नीलम देवी.
सारण	सलीम परवेज, मो. यासीन, सच्चितानंद राय, विनोद यादव.
मुंगेर, जमुई लखीसराय-शेखपुरा	संजय प्रसाद, अशोक कुमार सिंह
नवादा	सलमान राजीव, जदयू, नीवेदिता सिंह, राजो प्रसाद, बलेश्वर चौधरी.
गोपालगंज	सुनील कुमार सिंह, सुशील सिंह, अनवर हुसैन, सुधाकर तिवारी.
औरंगाबाद	रंजन कुमार सिंह, जग नारायण सिंह, उमा देवी, रणजीत सिंह

दरअसल, आरबीआई द्वारा स्वर्ण आयात को दूसरी वस्तुओं के आयात जैसे रेगुलेशन (विनियमन) लगाने से वांछित नतीजे प्राप्त हुए और स्वर्ण आयात में जल्द ही दोगुनी कमी आ गई. समान रेगुलेशन (विनियमन) होने की वजह से वित्तीय वर्ष 2014 के लिए चालू खाते का घाटा सकल घरेलु उत्पाद का 1.7 प्रतिशत रह गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आरबीआई ने अभी हाल ही में इस विनियमन को ष त्म कर दिया है और मीडिया रिपोर्टों की मानें, तो स्वर्ण आयात में एक बार फिर उछाल आ चुका है. नतीजतन, वित्तीय वर्ष के मौजूदा तिमाही में चालू खाता घाटा बढ़कर 2.1 प्रतिशत हो गया है. इस पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री ने स्वर्ण आयात कम करने के लिए अपने बजट भाषण में निम्नलिखित तीन सुझाव दिए हैं.

सोना आयात कम करने की राह में रुकावटें

एक और बात कि स्वर्ण जमा करने और उधार देने की प्रस्तावित योजना वस्तुतः प्रभावी होगी या नहीं, इसका दारोमदार पूरी तरह से इस बात पर है कि भारत में सक्रिय गोल्ड ट्रेडिंग (जिसमें मंदड़िया बिक्री और बॉन्ड क्रय–बिक्री और स्वर्ण खदानों के लिए ग्लोबल स्केलिंग शामिल हों) लागू कर पाते हैं या नहीं, लेकिन भारतीय पृष्ठभूमि में यह सारी चीज़ें नहीं हैं. ऊपर लिखित कारणों से सरकारी गोल्ड बॉन्ड और स्वर्ण मौद्रिकरण योजनाएं सफल नहीं हो पाएंगी.

वी के शर्मा

वित्त मंत्री अरुण जेटली प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से स्वर्ण आयात कम करने की बात स्वीकारी. दरअसल, लगभग 30 वर्षों से चालू खाते के घाटे का एकमात्र कारण स्वर्ण आयात ही रहा है. यह घाटा वित्तीय वर्ष 2013 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.7 प्रतिशत था, जिसमें स्वर्ण आयात का हिस्सा 3 प्रतिशत से अधिक था.

इसका मुख्य कारण यह था कि मौजूदा आयात विनियमन (आरबीआई का फेमा मास्टर सर्कुलर) में स्वर्ण आयात को दूसरी वस्तुओं (जिनमें आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं) के मुकाबले अधिक तरजीह दी गई है. इस विनियमन में स्वर्ण आयात की अनुमति तीन बुनियादों पर दी गई है : 1.कन्साइनमेंट के आधार पर 2. निर्धारित मूल्य के आधार पर 3. धातु–लोन के आधार पर. ऐसी प्राथमिकता से विदेश से सोना भेजने वाले के लिए स्वर्ण आयात से संबंधित मूल्य और मुद्रा का जोखिम समाप्त हो जाता है और इसका सारा जोखिम सोने के गहने खरीदने वालों पर आ जाता है. यह स्थिति कोयला, खाद्यान तेल के लिए नहीं होती, क्योंकि यह वस्तुएं सीधे तौर पर आयात की जाती हैं. लिहाज़ा, मैंने दिसम्बर 2012 में रिज़र्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर डॉ. सुब्बाराव और मौजूदा गवर्नर डॉ. रघुराम राजन को सुझाव दिया था कि स्वर्ण और दूसरी वस्तुओं का आयात फेमा के प्रावधानों के मुताबिक किया जाए. दरअसल, आरबीआई द्वारा स्वर्ण आयात को दूसरी वस्तुओं के आयात जैसे रेगुलेशन (विनियमन) लगाने से वांछित नतीजे प्राप्त हुए और स्वर्ण आयात में जल्द ही दोगुनी कमी आ गई. समान रेगुलेशन (विनियमन) होने की वजह से वित्तीय वर्ष 2014 के लिए चालू खाते का घाटा सकल घरेलु उत्पाद का 1.7 प्रतिशत रह गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आरबीआई ने अभी हाल ही में इस विनियमन को ष त्म कर दिया है और मीडिया रिपोर्टों की मानें, तो स्वर्ण आयात में एक बार फिर उछाल आ चुका है. नतीजतन, वित्तीय वर्ष के मौजूदा तिमाही में चालू खाता घाटा बढ़कर 2.1 प्रतिशत हो गया है. इस पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री ने स्वर्ण आयात कम करने के लिए अपने बजट भाषण में निम्नलिखित तीन सुझाव दिए हैं.

भारत स्वर्ण का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और हर साल 800 से 1000 टन स्वर्ण का आयात करता है. हालांकि भारत का स्वर्ण का कुल स्टॉक 20000 टन है, लेकिन इस स्वर्ण का न तो व्यापार होता है और न ही इसे मुद्रीकृत किया गया है. इसलिए मेरे हिसाब से :

(क) एक स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (गोल्ड मोनीटाइज़ेशन स्कीम) लागू करने का प्रस्ताव है, जो मौजूदा गोल्ड डिपॉजिट और गोल्ड मेटल लोन योजना का स्थान लेगा. नई स्कीम के तहत स्वर्ण जमाकर्ता अपने मेटल (धातु) एकाउंट्स पर ब्याज हासिल करेगा और लोन भी हासिल कर सकता है.

(ख) इसके अतिरिक्त स्वर्ण खरीदने के विकल्प के तौर पर एक वैकल्पिक वित्तीय सम्पत्ति (सरकारी गोल्ड बॉन्ड के रूप में) विकसित की जाए. इस बॉन्ड पर एक सीमित ब्याज निर्धारित होगा और स्वर्ण के बाज़ार भाव के मुताबिक कभी भी मुद्रा में भुनाया जा सकेगा.

(ग) अशोक चक्र वाला स्वर्ण का भारतीय सिक्का ढाला जाए. इस तरह के स्वर्ण का भारतीय सिक्का विदेशों में ढाले गए सिक्कों की मांग को कम कर देगा. साथ ही देश में उपलब्ध स्वर्ण को रीसायकल करने में भी सहायक होगा.

प्रस्तावित सरकारी गोल्ड बॉन्ड स्कीम अपनी डिजाइन और तर्क में बिल्कुल गोल्ड इटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) की तरह है. अंतर केवल इतना होगा कि गोल्ड इटीएफ ब्याज नहीं देता, लेकिन डीमेट फॉर्म (अभौतिक रूप) में रखे गए स्वर्ण के निवेश से हासिल रिटर्न निवेशक को अदा करता है. महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में सभी 14 गोल्ड ईटीएफ 40–50 टन से अधिक स्वर्ण नहीं रखते, जो वित्त मंत्री के बजट भाषण में बताए गए कुल 800–1000 टन आयातित स्वर्ण का केवल 5 प्रतिशत है. लिहाज़ा, गोल्ड ईटीएफ स्वर्ण धातु की मांग को ष त्म नहीं कर पाता और इसके परिणामस्वरूप स्वर्ण धातु निवेशकों के लिए सोने की मांग का एक विकल्प बन जाता है. इस प्रस्तावना की गंभीरता को ऐसे समझा जा सकता है कि स्वर्ण का मूल्य 70 के दशक के आखिरी वर्षों में सबसे अधिक 850 डॉलर प्रति ओजेड (आउंज़) से घट कर 90 के दशक में 270 डॉलर प्रति ओजेड और फिर सितम्बर 2011 में सबसे अधिक 1920 डॉलर पर पहुंच गया. स्वर्ण की कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा. इसके पीछे तर्क यह है कि अगर हम एक बार फिर यह मान लें कि गोल्ड बॉन्ड 1000 टन स्वर्ण आयात की मांग के बराबर होगा, तो बॉन्ड भुनाने के समय इसका कुल घाटा 25 अरब डॉलर होगा. यही नहीं, सरकारी गोल्ड बॉन्ड के बड़े निवेशक की वजह से स्टॉक मार्केट में इनकी कीमतों में परिपक्वता के समय तेज़ी से वृद्धि करवा सकते हैं. इसकी वजह से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

फरवरी 2013 में कॉमोडिटी एक्सचेंज के किसी विशेषज्ञ ने ऊपर बताए गए गोल्ड बॉन्ड जैसे ही एक बॉन्ड का प्रस्ताव रखा है. उनका प्रस्ताव है कि सरकारी गोल्ड बॉन्ड से प्राप्त राशि का निवेश बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाओं में किया जाए और बॉन्ड का लाभ धारक को बिना मूल्य जोखिम के या घाटे के दिया जाए. मूल्य जोखिम को कम करने के लिए गोल्ड कॉल ऑप्शन (यानी स्वर्ण खरीदने का विकल्प) खुला रखना चाहिए, लेकिन स्वर्ण खरीदने का यह विकल्प, जिसमें 1000 टन वार्षिक स्वर्ण आयात की मांग की आवश्यकता होती है, सिद्धांत रूप से तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता में प्रभावकारी नहीं है. यह सरकार पर भी उतना ही लागू होता है, जो स्वर्ण की मूल्य वृद्धि के जोखिम को स्वर्ण वायदा खरीद कर कम करना चाहती है. खरीद का विकल्प और स्वर्ण वायदा दोनों का जोखिम कम करने का अनुपात 1 होगा, जिसका मतलब होगा कि 1000 टन स्वर्ण की मांग होगी और यह मांग सरकारी बॉन्ड के बजाए स्वर्ण धातु बाज़ार से पूरी होगी, जिसके लिए स्वर्ण आयात करना पड़ेगा. यह वायदा कारोबार, जोखिम में कमी और मूल्य निर्धारण का बुनियादी सिद्धांत है, जो एक मूल्य के आधार पर संचालित होती है. दूसरे शब्दों में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलेगा. अगर कोई संपत्ति है, जो गोल्ड बॉन्ड का प्रतिलाभ देने के योग्य है, तो वह है गोल्ड यानी स्वर्ण. लिहाज़ा, प्रस्तावित सरकारी गोल्ड बॉन्ड वास्तविक नहीं हो सकता.

अब दूसरे बजट प्रस्ताव यानी 20000 टन घरेलू स्वर्ण भंडार के तथाकथित मौद्रिकरण का रुख करते हैं, जिसके बारे में वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बिल्कुल सही कहा कि न तो इसका व्यापार हुआ है और न ही मौद्रिकरण.

पूरी दुनिया के स्वर्ण भंडारों और न्यूयॉर्क, लन्दन, सिंगापुर और हांगकांग के कर्जदाता बाज़ार की खास बात यह है कि उधार स्वर्ण की मांग मंदड़िया बिक्री (शोर्ट सेलिंग) करने वालों और बड़े स्वर्ण खनिकों की तरफ से आती है. विशेष रूप से मंदड़िया बिक्री की उत्पति सट्टेबाजों, बचाव कोष (हेज फंड) और अन्य लोगों द्वारा स्वर्ण भाव में गिरावट पर सट्टा लगाना, ताकि इसकी वजह से कम कीमत पर स्वर्ण खरीद कर लाभ कमाया जा सके, लेकिन मंदड़िया बिक्री में एक तरह का अनुशासन होता है, इसलिए मंदड़िया बिक्री में देने के लिए बिक्रेता को आवश्यक रूप से स्वर्ण धातु उधार

लेना पड़ता है, जिसकी भरपाई कुछ समय बाद स्वर्ण की पुनः खरीद के बाद हो जाती है.

स्वर्ण धातु की मंदड़िया बिक्री की एक और वजह बाज़ार के भागीदारों द्वारा नकदी वायदा कारोबार में शामिल होना है. यह उस वक़्त होता है, जब स्वर्ण वायदा मौजूदा बाज़ार भाव से सस्ता होता है. इसमें वे सस्ता स्वर्ण वायदा (फ्यूचर गोल्ड) खरीदते हैं और हाज़िर बाज़ार (स्पॉट मार्केट) में बेच देते हैं और फिर हेज मार्केटिंग के जरिया परिपक्वता पर बिना किसी जोखिम के मुनाफा कमाते हैं. इस तरह का व्यापार उस वक्त तक जारी रहता है, जब तक मूल्य में फर्क बना रहता है. चूंकि पूरी दुनिया में ऐसे उधार स्वर्ण की बहुत अधिक मांग है, इसलिए इसकी आपूर्ति बैंकों में जमा या लोन मार्केट के स्वर्ण से होती है. बैंकों में जमा और उधार दर लागू होते हैं, जिसे गोल्ड लीज रेट कहते हैं. दूसरी तरफ जब बाज़ार का भाव ऊपर चढ़ता है, तो स्वर्ण का भाव भी उपर चढ़ता है. ऐसे समय में उधार स्वर्ण की मांग आमतौर पर कम रहती है, इसलिए गोल्ड लीज रेट भी कम रहता है. यह गोल्ड लीज रेट सिद्धात रूप में मुद्रा ब्याज दर का मामूली हिस्सा होता है. फ़िलहाल यह 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने और 1 साल में क्रमशः 0.09 प्रतिशत, 0.11 प्रतिशत, 0.25 प्रतिशत और 0.40 प्रतिशत रहा है.

जैसा कि ऊपर ज़िक्र किया जा चुका है कि मंदड़िया बिक्री और बॉन्ड के क्रय–बिक्री करने वाले के आलावा एक और प्रकार का स्वर्ण धातु का कर्ज़दाता होता है, जो बड़े स्वर्ण खनिक होते हैं. ये लम्बी अवधि तक स्वर्ण उधार लेते हैं, ताकि उसे बाज़ार में बेच सकें और उससे हासिल पूंजी को नये खदान में लगा सकें. सोने के मूल्य से संबंधित प्राकृतिक हेज बना सकें, जिसमें मूल्य वृद्धि का कोई जोखिम भी नहीं हो.

उल्लेखनीय रूप से सोनार को स्वर्ण उधार देने को स्वर्ण धातु ऋण कहना विरोधाभाषी है, क्योंकि यह बुनियादी तौर पर स्वर्ण की खरीद–बिक्री है. जमा करने और क़र्ज़ के लेन–देन में जो भी उधार लिया जाता है, उसे वापस भी करना पड़ता है. इसलिए यह समझने में कोई अधिक सोच–विचार की आवश्यकता नहीं है कि प्रस्तावित मौद्रिकरण योजना से वांछित नतीजे नहीं हासिल होंगे.

एक और बात कि स्वर्ण जमा करने और उधार देने की प्रस्तावित योजना वस्तुतः प्रभावी होगी या नहीं, इसका दारोमदार पूरी तरह से इस बात पर है कि भारत में सक्रिय गोल्ड ट्रेडिंग (जिसमें मंदड़िया बिक्री और बॉन्ड क्रय–बिक्री और स्वर्ण खदानों के लिए ग्लोबल स्केलिंग शामिल हों) लागू कर पाते हैं या नहीं, लेकिन भारतीय पृष्ठभूमि में यह सारी चीज़ें नहीं हैं. ऊपर लिखित कारणों से सरकारी गोल्ड बॉन्ड और स्वर्ण मौद्रिकरण योजनाएं सफल नहीं हो पाएंगी. दरअसल, जो क़दम कारगर हो पाएगा, वह है वर्ष 2013–14 में आरबीआई द्वारा लागू किए गए स्वर्ण आयात के लिए भी दूसरी वस्तुओं की तरह समान शर्तें लागू की जाएं और स्वर्ण का आयात कन्साइनमेंट के आधार पर, अनिर्धारित मूल्य के आधार पर और धातु लोन के आधार पर बंद किया जाए. ■

(लेखक रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

व्यापार करना आसान नहीं है. कोई भी विदेशी निवेशक सरकार के रवैये को लेकर उत्साहित नहीं है. वे लोग प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व से उत्साहित हैं, उनकी बातों और सपनों को उम्मीद के साथ देखते हैं, लेकिन जब बात व्यापार करने से जुड़ती है, तो वे कहते हैं कि सरकार या तो बहुत धीरे-धीरे काम कर रही है या बिल्कुल नहीं कर रही है. व्यापार सरकार की मंशा पर निर्भर नहीं करता. हर किसी का इरादा अच्छा है, लेकिन सिर्फ़ इससे काम नहीं बनता. स्थानीय व्यवसायी भारतीय प्रथाओं के अभ्यस्त हैं, लेकिन विदेशी उन्हें पसंद नहीं करते.

रक्षा मंत्री का बयान चिंता पैदा करता है

संसद का सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर कोई वास्तविक हलचल नहीं दिख रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों फ्रांस, जर्मनी एवं कनाडा के दौरे पर थे. कई लोग हैं, जो यह कहकर मज़ाक उड़ा रहे हैं कि वह प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि विदेश मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं. यह सही नहीं है. पिछले प्रधानमंत्रियों ने भी महत्वपूर्ण देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए विदेश यात्राएं की हैं. मोदी अभी नए हैं और अपना काम कर रहे हैं. वह इन देशों के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित करने के लिए बहुत उत्सुक हैं और मेरे हिसाब से वह सही कर रहे हैं. यह पूरी तरह से उचित है. हालांकि, चिंता की बात अलग है. हम फ्रांस से वायुसेना के लिए विमानों की खरीद के लिए तैयार हैं, राफेल विमान. खैर, यह सब खरीदना सरकार का अधिकार है. लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक साक्षात्कार दिया है, जो चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि यह सब प्रक्रिया समय की बर्बादी है और हमें स्टेट टू स्टेट स्तर पर उपकरणों की खरीद करनी चाहिए. इसका मतलब है कि वह जो कह रहे हैं, उससे बोफोर्स मामले में राजीव गांधी के क़दम का समर्थन कर रहे हैं. राजीव गांधी ने स्वीडेन के प्रधानमंत्री से बात करके कहा था कि सभी बिचौलियों को हटाकर स्वीडिश सरकार के साथ सीधे सौदा होना चाहिए. फिर उसके बाद क्या हुआ, हर कोई जानता है. वहां पैसे का बहुत बड़ा खेल हुआ.

मैं नहीं समझता कि राफेल खरीद को लेकर यूपीए-2 पर आरोप लगाते हुए पर्रिकर ने तथ्यों का अध्ययन किया है या वह बहुत उत्साह में आकर ऐसा बोल गए और अपने प्रधानमंत्री की सराहना करने लगे. यह गंभीर बात है. ये ऐसे मामले हैं, जिनमें हज़ारों करोड़ लगे हुए हैं. एयरक्राफ्ट की गुणवत्ता पर किसी मतभेद की गुंजाइश हो ही नहीं सकती. वायुसेना के अधिकारी बेहतर समझ सकते हैं कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है और देश के लिए बेहतर क्या है. लेकिन, वाणिज्यिक मसला भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. यहां तक कि जब बोफोर्स को लेकर सवाल उठे, तब भी कांग्रेस ने कहा था कि बोफोर्स सबसे अच्छी तोप है. कोई भी शख़्स तोप या एयरक्राफ्ट के तकनीकी गुणों को चुनौती नहीं दे रहा है. सवाल यह है कि असली क़ीमत क्या है और कितना हम भुगतान कर रहे हैं. इसके बीच क्या संतुलन है? और, यह दु:खद है कि मनोहर पर्रिकर इस रहस्य को एक स्थापित प्रक्रिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं. राजीव गांधी द्वारा लगाया गया वह प्रतिबंध कि सीधे में बिचौलिए नहीं होने चाहिए, हटाया जाना चाहिए. यह किसी भी अन्य खरीद की तरह एक रक्षा उपकरण है.

जिस किसी के पास भी यह उपकरण है, उन्हें पारदर्शी, स्पष्ट रूप से, खुले तौर पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने दिया जाए और उन्हें शर्त बताई जाए. वायुसेना को ट्रायल लेने दें, उसे जो चाहिए, उसका चयन करने दें. मूल्य के लिए सरकार को सौदा करने दें, मोल-भाव करने दें और, अगर कोई बिचौलिया कमीशन लेता है, तो उसे दें. बिचौलिया उस पर टैक्स दे. अगर वह कमीशन विदेश में लेता है, तो उसे वह पैसा रिजर्व बैंक के ज़रिये देश में लाने दें. व्यापार करने का यही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीका है. दुर्भाग्य से राजीव गांधी के समय में बोफोर्स मुद्दे पर शुरू हुई चीज़ों की वजह से भारत दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है. शस्त्र बाज़ार बहुत संवेदनशील है. पूरी दुनिया में एक, दो या पांच फ़ीसद कमीशन बिचौलिए को देने की स्थापित प्रथा है. ऐसे कई बनाना रिपब्लिक हैं, जहां कोई स्थापित प्रक्रिया नहीं है, वहां मोल-भाव होता है और 10 से 15 फ़ीसद तक उस देश के प्रधानमंत्री की जेब में चला जाता है. बोफोर्स मामले में भारत की छवि ऐसी ही बनी थी. किसे पैसा मिला, हम नहीं जानते, लेकिन शस्त्र बाज़ार यह जान गया कि भारत एक ऐसा देश है, जिसे मूर्ख बनाया जा सकता है. पांच रुपये का सामान भी अधिक में बेचा जा सकता है और बाकी

क्या मनोहर पर्रिकर देश में वही परंपरा शुरू करना चाहते हैं, जो ईमानदार रक्षा मंत्री एके एंटोनी ने बंद कर दी थी? नतीजा क्या हुआ था? खरीद रुक गई थी. यह सशस्त्र बलों के लिए अच्छा नहीं है. जब आपको उपकरण की ज़रूरत है, तो निर्णय करना चाहिए, लेकिन निर्णय निष्पक्ष, पारदर्शी और उचित तरीके से किया जाना चाहिए.अब मनोहर पर्रिकर क्या सुझाव दे रहे हैं? वह मानो यह सोच रहे हैं कि वे लोग पांच साल के लिए निर्वाचित हुए हैं, तो अब राजा की तरह हो गए हैं और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं.

रकम हजम की जा सकती है.

क्या मनोहर पर्रिकर देश में वही परंपरा शुरू करना चाहते हैं, जो ईमानदार रक्षा मंत्री एके एंटोनी ने बंद कर दी थी? नतीजा क्या हुआ था? खरीद रुक गई थी. यह सशस्त्र बलों के लिए अच्छा नहीं है. जब आपको उपकरण की ज़रूरत है, तो निर्णय करना चाहिए, लेकिन निर्णय निष्पक्ष, पारदर्शी और उचित तरीके से किया जाना चाहिए.

अब मनोहर पर्रिकर क्या सुझाव दे रहे हैं? वह मानो यह सोच रहे हैं कि वे लोग पांच साल के लिए निर्वाचित हुए हैं, तो अब राजा की तरह हो गए हैं और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं. दुर्भाग्य से वह वही ग़लती कर रहे हैं, जो राजीव गांधी सरकार ने की थी और वह भी अपने 400 सांसदों के होते हुए. आपके पास तो केवल 282 सांसद हैं. यह इस पूरे प्रकरण का गंभीर हिस्सा है. उन्होंने एक अख़बार को बहुत बड़ा साक्षात्कार दिया है. मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री को इसके बारे में जानकारी है या नहीं. यह साक्षात्कार तब दिया गया, जब प्रधानमंत्री विदेश में थे.

दूसरी बात यह है कि अभी भी विकास का पैटर्न सामने नहीं आ रहा है. हां, चीन की विकास दर नीचे जा रही है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक द्वारा कहा जा रहा है कि भारत की विकास दर चीन की तुलना में अधिक हो जाएगी और हम खुश हो रहे हैं. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हमने अपने विकास के आंकड़े बदल दिए हैं, बेस इयर (आधार वर्ष) बदल दिया है. इसलिए हम अधिक उच्च वृद्धि देख पा रहे हैं. चीन इसलिए नीचे जा रहा है कि वह बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे. लेकिन, यह हमारे लिए सांत्वना की बात नहीं है कि हम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं. अगर हम मेक इन इंडिया को सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें निवेश को आकर्षित करने के लिए तरीके खोजने चाहिए. यदि हम व्यापार को आसान बनाना चाहते हैं, तो क़ानूनों को सरल बनाना चाहिए. इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है. अपने अच्छे इरादों के बावजूद वित्त मंत्री नौकरशाही की लालफीताशाही में कटौती करने में असमर्थ हैं.

व्यापार करना आसान नहीं है. कोई भी विदेशी निवेशक सरकार को लेकर उत्साहित नहीं है. वे लोग प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व से उत्साहित हैं, उनकी बातों और सपनों को उम्मीद के साथ देखते हैं, लेकिन जब बात व्यापार करने से जुड़ती है, तो वे कहते हैं कि सरकार या तो बहुत धीरे-धीरे काम कर रही है या बिल्कुल नहीं कर रही है. व्यापार सरकार की मंशा पर निर्भर नहीं करता. हर किसी का इरादा अच्छा है, लेकिन सिर्फ़ इससे काम नहीं बनता. स्थानीय व्यवसायी भारतीय प्रथाओं के अभ्यस्त हैं, लेकिन विदेशी उन्हें पसंद नहीं करते. भारतीय व्यवसायी जानते हैं कि सरकार को कैसे मैनेज करना है, कैसे मामले को न्यायिक प्रक्रिया में उलझाना है. और फिर भारत में एक न्यायिक मामला सरकार के कार्यकाल से भी लंबा चलता है. लेकिन, विदेशी निवेशक ऐसी भाषा और शैली पसंद नहीं करते हैं. जितनी जल्दी सरकार बिजनेसमैन की बात और समस्या को सुने-समझे, उतना ही अच्छा खुद सरकार के लिए भी होगा, ताकि वह उन उम्मीदों को पूरा कर सके, जिसे उसने खुद पैदा किया है. उम्मीद करते हैं कि संसद सत्र इस बारे में कुछ नई रोशनी डालेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक औघड़ लीक से हटकर

क्या आपने कोई ऐसा औघड़ देखा है, जो सामाजिक कुरीतियों से, जनता के बीच व्याप्त अंधविश्वासों से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता हो? जो कुष्ठ रोगियों की स्वयं सेवा करता हो और अपने पास आने-जाने वालों को ध्यान करने की नहीं, देश की समस्याओं की ओर ध्यान देने की प्रेरणा देता हो? वाराणसी के भगवान राम अपने अतीत और अपनी साधना में खरे औघड़ तो थे ही, पर अपनी जीवनचर्या में किसी भी सामाजिक या राजनीतिक नेता से कई क़दम आगे भी थे. सहज ही चमत्कार पर चमत्कार घटित होते थे, बल्कि उनकी विशिष्टता इस बात में थी कि उन्होंने अध्यात्म की साधना को एक व्यापक सामाजिक आयाम दिया था. औघड़ भगवान राम को उनके चाहने वाले बाबा या सरकार कहते थे, आज भी कहते हैं. वह इतने सहज थे कि उनके पास चाहे साधारण व्यक्ति अपनी समस्याएं लेकर जाता हो या इंदिरा गांधी, जगजीवन राम या मोरारजी देसाई जैसे व्यक्तित्व, सब अपनी-अपनी ऊर्जा और अपने-अपने समाधान आसानी से पा जाते थे. आज वह हमारे बीच नहीं हैं, पर उन्होंने इतने लोगों को ऊर्जावान किया है तथा इतना कुछ सहज और सरल भाषा में कहा है, जो प्रेरणा देता रहता है. मैंने उनसे काफी कुछ जानने की कोशिश की थी, पर वह इतने संकोची थे कि बताने के साथ ही लिखने से रोकते जाते थे. मेरे क्यों पूछने पर उन्होंने कहा था कि वह नहीं चाहते कि समाज अपने उद्यम की जगह चमत्कारों की शरण में जाने लगे. जितना भी मैंने लिखा, यह उसका एक छोटा हिस्सा है, जो उन्होंने मुझे बताया था. ऐसी बहुत-सी घटनाओं का न केवल मैं साक्षी रहा हूं, बल्कि रविवार के तत्कालीन संपादक स्वर्गीय सुरेंद्र प्रताप सिंह भी उनसे विशेष रूप से मिले थे तथा मुझे फोन कर कहा था कि बाबा पर और भी रिपोर्ट होनी चाहिए. बाबा ने बाद में कुछ भी लिखने से रोक दिया था. मैंने उन्हीं विशिष्ट और अद्वितीय औघड़ को अपने नज़रिये से समझने की कोशिश की तथा औघड़ की अजब अनोखी दुनिया का एक लघु-वृत्तांत आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं.

सन् 73 की दुर्गापूजा. बनारस में नवरात्रि का अनुष्ठान चल रहा था. प्रत्येक दिन शाम को औघड़ भगवान राम का प्रवचन होता था. इसी क्रम में एक दिन उन्होंने यह कहानी सुनाई, एक देश था. उसके राजा ने अपनी औलाद और परिवारजनों की सुख-सुविधा के लिए उस राष्ट्र के निर्माताओं को प्रताड़ित करना प्रारंभ किया तथा उन्हें जेल में बंद कर दिया. उससे त्राण पाने के लिए हमारे-आपके घर-आंगन से दो लड़के उधर गए और उन्होंने जनशक्ति को संगठित किया. उस जनशक्ति से जो ज्वाला निकली, वही दुर्गा और काली थीं. जनशक्ति ही शक्ति है. मार्च 74 से जयप्रकाश का विशाल जन-आंदोलन प्रारंभ हुआ. औघड़ भगवान राम के कई भक्त इस घटना को बाबा द्वारा आंदोलन के बारे में दिया गया पूर्व संकेत मानते हैं. लाल बहादुर शास्त्री के असामयिक निधन के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए होने वाले चुनाव में इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच संघर्ष होने वाला था. मोरारजी भाई के घर पर पत्रकार सम्मेलन चल रहा था कि औघड़ भगवान राम वहां पहुंच गए. मोरारजी भाई के पास संदेश गया, तो उन्होंने कहलवाया कि उन्हें बैठाइए, मैं थोड़ी देर में फुर्सत से उनके साथ बैठूंगा. जिसने यह संदेश बाबा को दिया, उससे बाबा ने कहा, उन्हें जल्दी ही फुर्सत मिल जाएगी, तब मुलाकात होगी. इस घटना के दो दिन बाद चुनाव हुआ तथा मोरारजी भाई हार गए. अब उनके पास फुर्सत ही फुर्सत थी.

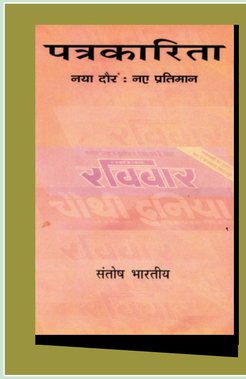

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

सन् 64 में यज्ञ नारायण चतुर्वेदी के साथ बाबा दिल्ली में थे. उसी समय भुवनेश्वर कांग्रेस होने वाली थी. बाबा पैदल दिल्ली में टहल रहे थे. एकाएक रुक गए तथा कहा, चतुर्वेदी जी, आपको कुछ महसूस हो रहा है? चतुर्वेदी जी ने कहा, नहीं तो. बाबा बोले, लग रहा है, दिल्ली में कोई बहुत बड़ी लाश सड़ रही है. इसके कुछ दिन बाद ही जवाहर लाल नेहरू अस्वस्थ हुए और चल बसे. उपर्युक्त घटनाएं चमत्कारपूर्ण प्रतीत होती हैं और सामान्य बुद्धि उन्हें स्वीकार करने से इंकार कर देती है.

सन् 64 में यज्ञ नारायण चतुर्वेदी के साथ बाबा दिल्ली में थे. उसी समय भुवनेश्वर कांग्रेस होने वाली थी. बाबा पैदल दिल्ली में टहल रहे थे. एकाएक रुक गए तथा कहा, चतुर्वेदी जी, आपको कुछ महसूस हो रहा है? चतुर्वेदी जी ने कहा, नहीं तो. बाबा बोले, लग रहा है, दिल्ली में कोई बहुत बड़ी लाश सड़ रही है. इसके कुछ दिन बाद ही जवाहर लाल नेहरू अस्वस्थ हुए और चल बसे. उपर्युक्त घटनाएं चमत्कारपूर्ण प्रतीत होती हैं और सामान्य बुद्धि उन्हें स्वीकार करने से इंकार कर देती है. पर, जो लोग औघड़ भगवान राम के संसर्ग में रहे हैं, उनके लिए यह कहानी नहीं, सच्चाई है. औघड़ भगवान राम बनारस आने से पहले हरिहरपुर आश्रम में रहते थे. जिन्हें चमत्कार कहते हैं, वे सब अधिकांश वहीं हुए. इस आश्रम में वह जब तक रहे, आश्रम की हर पत्ती दवा थी. ऐसे एक रोगी वहां की पत्तियां खाकर दस साल तक ज़िंदा रहे तथा जब मरे, तो दूसरे रोग से. हरिहरपुर के पास ही मनिहरा पोखरा में रविवार-मंगल को स्नान करने से कोई भी रोग समाप्त हो जाता था. जो भी पागल हरिहरपुर आश्रम में आता था, अपने आप ठीक हो जाता था. ऐसे ठीक होने वाले पागलों से बाबा एक-दो महीने काम कराते थे तथा बाद में भगा देते थे. रात में जो भी बाबा को देख लेता था, पागल हो जाता था. पर बाद में बाबा उसे ठीक कर देते थे. पर वहां ग्राम समाज और पुजारी के बीच चढ़ावे को लेकर झगड़ा शुरू हो गया. बाबा ने वहां जाना बंद कर दिया. और, इसके साथ ही वहां घटने वाले चमत्कारों का सिलसिला बंद हो गया.

क्रमश:

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

यह लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है

मलियाना-हाशिमपुरा और साध्वी प्रज्ञा, ये दोनों मामले बताते हैं कि न्याय व्यवस्था में भी ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए. आख़िर वही किताबें हैं, वही क़ानून है और वही क़ानून की व्याख्या करने वाले लोग उस कुर्सी पर बैठे हैं. क्यों अंतिम न्याय देने वाली अदालत ज़्यादातर उन सवालों के ऊपर अपनी अलग राय देती है, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाते हैं?

अब समय आ गया है, जबकि देश के पुलिस तंत्र और न्याय व्यवस्था के बारे में बातचीत की जाए. हमारे देश का पुलिस तंत्र आजादी के 67 सालों के बाद भी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है और न कोई सरकार पुलिस तंत्र को किसी के प्रति जवाबदेह बनाना चाहती है. पुलिस के ऊपर तभी कार्रवाई होती है, जब कोई पुलिस अधिकारी किसी बड़े अधिकारी या मंत्री की जाति से संबंध नहीं रखता या फिर वह उसके द्वारा की हुई सिफारिश को अनदेखा कर देता है. लेकिन, पुलिस के ऊपर ऐसे मामलों में कार्रवाइयां कम हुई हैं, जिनमें पुलिस ने ग़लत जांच की हो, पुलिस ने जांच ही नहीं की हो, किसी को फर्जी तरीके से जेल में बंद कर दिया हो या फिर फर्जी एनकाउंटर कर दिया हो. देखने में यह आया है कि सालों साल मुकदमा चला और उसके बाद आरोपी बेदाग छूट गया. उसने उतने दिन आराम किया, उन दिनों की तनख्वाह भी उस मिल गई और वह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए दोबारा उस इलाके में घूमने लगा, जहां लापरवाही बरतने या दमन की वजह से उसे फौरी तौर पर सजा मिली थी.

हाशिमपुरा और मलियाना कांड में लगभग 42 लोगों की मौत हुई. उन मौतों का किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया. ऐसा लगा कि सबने अपने आप खुद को गोली मार ली और पुलिस के ऊपर लगे हुए आरोप और चले हुए मुक़दमे सब ग़लत थे. नया मामला साध्वी प्रज्ञा का है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनके ऊपर कठोर धाराएं लगाने लायक कोई सुबूत पुलिस के पास नहीं है. इसलिए उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत में जाना चाहिए. साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिले या न मिले, सवाल यह नहीं है. बल्कि सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसे कोई ऐसी चीज नहीं मिली, जिससे साध्वी प्रज्ञा एवं उनके साथियों के ऊपर मकोका लगे या अन्य कठोर धाराएं लगें, तब यह चिंता की बात है. मलियाना-हाशिमपुरा और साध्वी प्रज्ञा, ये दोनों मामले बताते हैं कि न्याय व्यवस्था में भी ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए. आख़िर वही किताबें हैं, वही क़ानून है और वही क़ानून की व्याख्या करने वाले लोग उस कुर्सी पर बैठे हैं. क्यों अंतिम न्याय देने वाली अदालत ज़्यादातर उन सवालों के ऊपर अपनी अलग राय देती है, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाते हैं?

इससे पहले भी कई लोगों की इज्जत पुलिस और न्याय व्यवस्था ने तार-तार की है. कल्पनाथ राय का नाम याद कीजिए, वह कांग्रेस के बड़े नेता थे. कल्पनाथ राय के ऊपर पुलिस ने एक जांच की कि उनके किसी पीए ने किसी ऐसे आदमी को एसटीपीसी के गेस्ट हाउस में ठहरने की इजाजत दी, जो संदिग्ध था. अदालत ने कल्पनाथ राय को जेल भेज दिया. बाद में कल्पनाथ राय सर्वोच्च अदालत से छूट गए. पर तब तक कल्पनाथ राय के ढाई या तीन साल जेल में बीत चुके थे और उनकी इज्जत तार-तार हो गई थी. उस सदमे से वह निकल नहीं पाए और उनकी मौत हो गई. ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, जिनमें वे मिसालें नहीं आतीं, जिनका रिश्ता उन ग़रीबों से है, जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे पुलिस को पैसा दे सकें या न्याय का दरवाजा खटखटाने और अंतिम फ़ैसला पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकें.

पुलिस तंत्र अगर ग़लत जांच करता है, तो उसकी जवाबदेही निश्चित हो, उसके लिए उसे सजा देने का प्रावधान हो. उसी तरीके से अगर अदालतें ग़लत फ़ैसला दें या फिर ऐसे फ़ैसले दें, जो अंतिम न्याय देने वाले दरवाजे से ग़लत साबित होते दिखाई दें, तो उन जजों की ज़िम्मेदारी तय हो और कम से कम उनके प्रमोशन के ऊपर रोक लगे. ऐसा करना बहुत आवश्यक है, वरना लोकतंत्र हमेशा पुलिस और न्याय व्यवस्था के ज़रिये दागदार होता रहेगा. लोकतंत्र में जिसके पास ताकत नहीं है, जो ग़रीब है, दलित है, आदिवासी है, मुसलमान है और जो बेवजह सताया हुआ है, अगर उसका संरक्षण नहीं होगा, तो आम लोगों का विश्वास लोकतंत्र के प्रति थोड़ा डिग जाएगा.

क्या यह सवाल अब नहीं उठना चाहिए कि पुलिस तंत्र अगर ग़लत जांच करता है, तो उसकी जवाबदेही निश्चित हो, उसके लिए उसे सजा देने का प्रावधान हो. उसी तरीके से अगर अदालतें ग़लत फ़ैसला दें या फिर ऐसे फ़ैसले दें, जो अंतिम न्याय देने वाले दरवाजे से ग़लत साबित होते दिखाई दें, तो उन जजों की ज़िम्मेदारी तय हो और कम से कम उनके प्रमोशन के ऊपर रोक लगे. ऐसा करना बहुत आवश्यक है, वरना लोकतंत्र हमेशा पुलिस और न्याय व्यवस्था के ज़रिये दागदार होता रहेगा. लोकतंत्र में जिसके पास ताकत नहीं है, जो ग़रीब है, दलित है, आदिवासी है, मुसलमान है और जो बेवजह सताया हुआ है, अगर उसका संरक्षण नहीं होगा, तो आम लोगों का विश्वास लोकतंत्र के प्रति थोड़ा डिग जाएगा. लोकतंत्र के यही वे अंग हैं, जो उसके चेहरे का हिस्सा बनते हैं, जिनमें पुलिस, न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका और विधायिका प्रमुख हैं. कार्यपालिका और विधायिका के सवाल अलग हैं और उनकी ज़िम्मेदारियां अलग हैं. लेकिन जिनका सीधा रिश्ता आम जनता से है, वे हैं निचले स्तर की न्यायपालिका और पुलिस, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं. क्या हम यह मांग नहीं उठा सकते कि देश में एक ऐसी बहस शुरू हो और सरकार उस बहस की शुरुआत करे कि किस तरीके से पुलिस तंत्र को ज़्यादा ज़िम्मेदार बनाया जा सकता है और किस तरीके से न्यायपालिका को ज़्यादा संवेदनशील बनाया जा सकता है? अगर यह नहीं होगा, तो फिर हमें मान लेना चाहिए कि हम धीरे-धीरे पुलिस स्टेट की तरफ़ बढ़ रहे हैं. और, पुलिस स्टेट की तरफ़ बढ़ना लोकतंत्र के लिए बहुत ख़तरनाक है. ■

editor@chauthiduniya.com

आदर्शवाद काफी नहीं है

आदर्शवाद बुरा राजनेता बनाता है, जबकि यथार्थवादी किसी भी क़ीमत पर जीतना चाहते हैं. वे वापस सत्ता में आना चाहते हैं और इसके लिए वे धर्मनिरपेक्षता और मंडल से जुड़ी हर एक चाल अपनाएंगे. अब लोग उन्हें सुनते हैं या नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा कि नरेंद्र मोदी समावेशी विकास के अपने वादे को कितनी तेजी से पूरा करते हैं. अगर वह सफल होते हैं, तो कोई वैकल्पिक राजनीति कामयाब नहीं होगी. लेकिन, अगर भाजपा कमंडल राजनीति करती है, तो लोहियावादियों के पुराने समूह के लिए उम्मीद बाकी है.

मेघनाद देसाई

दिल्ली पर बुरा वक़्त आया हुआ है. पहली आप सरकार इसलिए गिरी, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह भ्रम था कि सत्ता में रहने के बावजूद वह सत्ता का स्थायी तौर पर विरोध करने वाले एक छात्रनेता हैं. अब वही रागनी फिर से गाई जा रही है, लेकिन इस बार हंगामे के केंद्र में कोर ग्रुप के मेंबर हैं. उनमें हर कोई यह समझ रहा है कि एक वही उन आदर्शों का पालन कर रहा है, जिन पर पार्टी बनाई गई थी और बाकी जो हैं, वे अवसरवादी खलनायक हैं. खैर, ऐसा तो देर-सबेर होना ही था. आइए, इस पर एक नज़र डालते हैं. अभी तक खेल ख़त्म नहीं हुआ है. जब कोई पार्टी 70 सीटों में से 67 सीटें जीत जाती है, तो आप देखेंगे कि अधिकतर एमएलए कभी न कभी खुद को गैर ज़रूरी ज़रूर महसूस करते होंगे. उन्हें लगता है कि सरकार चलाने के लिए महज 36 विधायक ही तो ज़रूरी हैं. फिर सरकार चलाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए तो पार्टी के चार लोग ही काफी हैं. साधारण अर्थ में आप एक राजनीतिक दल नहीं हैं. यह आदर्शों से भरे हुए एक आंदोलन के तौर पर शुरू हुई थी. यह पार्टी अवास्तविकता से भरी हुई है, इसमें आंतरिक लोकतंत्र बहुत कम है. पार्टी एक बैंड ऑफ ब्रदर्स है, जिसमें सबको लगता है कि वह खास है. अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वही केवल पार्टी के सबसे अच्छे नेता हैं. यह अजीब नहीं है कि वे लोग, जिन्होंने सोचा था कि वे भी प्रसिद्ध हैं, खुद को पीछे पाने लगे. चूंकि पार्टी के पास साधारण मनुष्य के रूप में भी सदस्यों के साथ व्यवहार के लिए कोई उचित प्रक्रिया नहीं थी, इसलिए भाइयों के बीच विवाद लगातार बढ़ता चला गया. और तो और, लोकपाल को भी उचित सूचना दिए बिना बर्खास्त कर दिया गया.

बहरहाल, इस ग़लती को भी माफ़ किया जा सकता था, यदि केजरीवाल कुछ प्रभावी शासन दे रहे होते. आदर्शवाद शुरुआत में ठीक है, सदाचार के लिए इनाम हो सकता है, लेकिन जैसे ही लोगों के जीवन में बदलाव लाने की शक्ति आपके पास आती है, वैसे ही सदाचार दूसरे स्थान पर चला जाता है. उसमें पहले काम करने की क्षमता आ जाती है. राजनीतिक दलों से प्रभावी होने की उम्मीद की जाती है, न कि शुद्ध होने की. हमारे पास एक प्रधानमंत्री थे, जिनकी व्यक्तिगत शुचिता संदेह से परे है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता को लेकर कई सवाल उठे.

आदर्शवादी या यथार्थवादी लाइन के दूसरे छोर पर पुरानी जनता पार्टी के टुकड़ों के बीच नए विलय की कहानी है. पाठकों को याद होगा कि पिछले साल मई में भाजपा की विजय के बाद मैंने संभावना जताई थी कि भाजपा या एनडीए के ख़िलाफ़ केवल एक व्यवहारिक गठबंधन पुराने लोहियावादी समूह से आएगा. पुराने और अनुभवी नेताओं के साथ आने से उन पर आदर्शवाद का आरोप लगाए जाने की संभावना नहीं है. और, फिर वे केजरीवाल की तरह किशोर विपक्ष की तरह व्यवहार भी नहीं करेंगे.

उत्तर प्रदेश एवं बिहार के यादवों के साथ जुड़ने, बिहार में अपने कुर्मी आधार के साथ जद (यू) और फिर जद (एस) गठजोड़ से इन दो राज्यों के 120 संसदीय क्षेत्रों में भाजपा के लिए एक चुनौती की शुरुआत हो गई है. जैसा कि अमेरिकी कहेंगे, यह कई पार्टी चीफ का समूह है, न कि पर्याप्त भारतीयों का. उक्त सारे नेता एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं और हो सकता है कि फिर से एक बार प्रतिद्वंद्वी हो जाएं. थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और दक्षिण से एचडी देवेगौड़ा का साथ आना अहम होगा. उद्घाटन के अवसर पर तृणमूल कांग्रेस और राकांपा के उपस्थित रहने के दावे किए जा रहे हैं. आप याद कर सकते हैं कि पुरानी जनता पार्टी के कोर मेंबर कांग्रेसी ही थे, जिन्हें इंदिरा गांधी ने बर्खास्त कर दिया था. उक्त नेता सालों पुराने हैं, ओबीसी पॉलिटिक्स में उनका पुराना अनुभव रहा है तथा वे सत्ता पाने और शासन चलाने के तौर-तरीकों से भलीभांति परिचित हैं. यदि राकांपा और तृणमूल अच्छी तरह से शामिल हो जाएं, तो बाहर सिर्फ इंदिरा कांग्रेस बचेगी, जो पहले से बुरी हालत में है.

आदर्शवाद बुरा राजनेता बनाता है, जबकि यथार्थवादी किसी भी क़ीमत पर जीतना चाहते हैं और इसके लिए वे धर्मनिरपेक्षता और मंडल से जुड़ी हर एक चाल अपनाएंगे. अब लोग उन्हें सुनते हैं या नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा कि नरेंद्र मोदी समावेशी विकास के अपने वादे को कितनी तेजी से पूरा करते हैं. अगर वह सफल होते हैं, तो कोई वैकल्पिक राजनीति कामयाब नहीं होगी. लेकिन, अगर भाजपा कमंडल राजनीति करती है, तो लोहियावादियों के पुराने समूह के लिए उम्मीद बाकी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कुष्ठ रोग के लिए बनी अवधारणा के लिए केवल समाज या कानून बनाने वाले लोगों को ही पूरी तरह से दोषी नहीं करार दिया जा सकता है. क्योंकि यह छुआछूत से फैलने वाली एक लाइलाज बीमारी है और इससे ग्रसित व्यक्ति अपंग भी हो जाता है. इसी ख़तरे की वजह से कुष्ठ रोगी को समाजिक बहिस्कार का सामना करना पड़ता था. लेकिन अब स्थिति बदल गई है. कुष्ठ रोग जो कुछ वर्ष पहले तक लाईलाज बीमारी मानी जाती थी अब इसका पूर्णतः इलाज संभव है. इसलिए इस बीमारी को कलंक के तौर पर देखने की अवधारणा पर भी पूर्ण विराम लगना चाहिए. इसी वजह से बेकार और बेमतलब कानूनों को कानून की किताब से ख़त्म करने की शिफारिश करने के लिए पूर्व न्यायाधीश अजित प्रकाश शाह की अध्यक्षता में गठित 20वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट नंबर 256 में कुष्ठ रोग से संबंधित कुछ ऐसे कानूनों की पहचान की है, जो अब बेकार हो चुके हैं.

ये क़ानून कोढ़ में खाज जैसे हैं

शफीक आलम

feedback@chauthiduniya.com

कोढ़ या कुष्ठ एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही हमारे माथे पर बल पड़ जाना कोई असामान्य बात नहीं है. यदि कोई बदनसीब एक बार इस बीमारी से ग्रसित हुआ तो जैसे उसके जीवन पर पूर्ण विराम लग जाता है. उसे या तो गांव और आबादी से दूर अलग–थलग जगह पर रहने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर भीख मांगने पर मजूबर कर दिया जाता है. बात सिर्फ यहीं तक रहती तो कोई बात नहीं थी. चूंकि हिंदुस्तान में बीमारियों को एक कलंक के तौर पर देखा जाता है, इस वजह से इंसान की जानकारी में सबसे प्राचीन बीमारी होने के कारण सबसे अधिक कलंकित रोग कुष्ठ ही है. इससे संबंधित आम अवधारणा यह है कि पीड़ित व्यक्ति ने इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई न कोई पाप ज़रूर किया है, जिसकी सजा उसे कुष्ठ रोग के रूप में मिली है. हमारे समाज का अफसोसजनक पहलू यह भी है कि हम बीमारियों के नाम का इस्तेमाल फिकरे कसने, किसी को निचा दिखाने या किसी को कोसने लिए भी करते हैं. हमारी आम बोल–चाल की भाषा में कई ऐसे मुहावरे शामिल हैं जो इस बीमारी से जुड़े हुए हैं, जैसे कोढ़ी होना या समाज का कोढ़ होना, और तो और हमारे शायरों ने भी इसे नहीं बख्शा मसलन कुली कुतुब शाह कहते हैं: नहीं इश्क जिसे वो बड़ा कोढ़ है / कधीं उससे मिल बैसिया जाये ना. और सोने पर सुहागा यह कि देश के कानून की किताब में कुछ ऐसे कानून दाखिल कर लिए गए हैं जो कुष्ठ रोगी को संक्रमण लगते ही उसे आम आदमी से विशेष आदमी का दर्जा दे देते हैं.

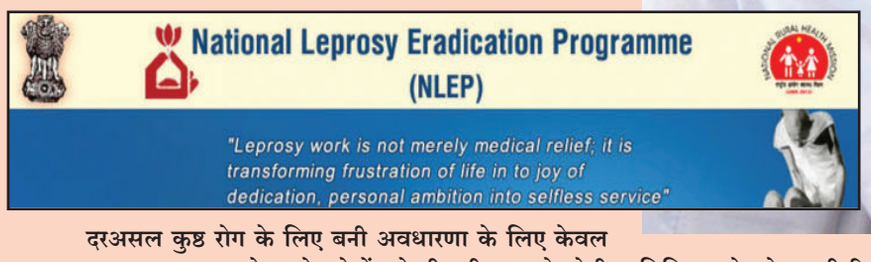

दरअसल कुष्ठ रोग के लिए बनी अवधारणा के लिए केवल समाज या कानून बनाने वाले लोगों को ही पूरी तरह से दोषी नहीं करार दिया जा सकता है. क्योंकि यह छुआछूत से फैलने वाली एक लाइलाज बीमारी है और इससे ग्रसित व्यक्ति अपंग भी हो जाता है. इसी खतरे की वजह से कुष्ठ रोगी को समाजिक बहिस्कार का सामना करना पड़ता था. लेकिन अब स्थिति बदल गई है. कुष्ठ रोग जो कुछ वर्ष पहले तक लाईलाज बीमारी मानी जाती थी अब इसका पूर्णतः इलाज संभव है. इसलिए इस बीमारी को कलंक के तौर पर देखने की अवधारणा पर भी पूर्ण विराम लगना चाहिए. इसी वजह से बेकार और बेमतलब कानूनों को कानून की किताब से ख़त्म करने की शिफारिश करने के लिए पूर्व न्यायाधीश अजित प्रकाश शाह की अध्यक्षता में गठित 20वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट नंबर 256 में कुष्ठ रोग से संबंधित कुछ ऐसे कानूनों की पहचान की है, जो अब बेकार हो चुके हैं. आयोग ने इन भेद–भाव से पूर्ण कानूनों में संशोधन करने और निरस्त करने का सुझाव रखा है.

वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वसम्मति से कुष्ठ रोग से संबंधित भेद–भाव को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें इस रोग से गस्त रोगियों का जीवन स्तर सुधरने के लिए भी सुझाव दिए गए थे. इसके अतरिक्त 2007 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) का भारत भी हस्ताक्षरी है. लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा इन कानूनों में संशोधन या उन्हें रद्दे करने या भेद–भाव दूर करने के लिए नए कानून बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई है. हालांकि 20वें विधि आयोग ने अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट नंबर 249 में इस कुष्ठ रोग अधिनियम, 1898 को रद्द करने की सिफारिश की थी लेकिन यह कानून अभी तक बरक़रार है, जबकि कई राज्यों ने इस कानून को निरस्त कर दिया है. यह कानून भिखारी और गरीब कुष्ठ रोगियों का इलाज करने, उन्हें अलग–थलग रखने और समाज से बाहर करने का अधिकार देता है. हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कानून जिन परिस्थितियों में बनाया गया था, अब वह परिस्थितियां बिलकुल बदल गई हैं, लिहाज़ा इसकी अब ज़रूरत नहीं है.

आयोग ने कई पर्सनल लॉ में बदलाव करने और उन्हें निरस्त करने की सिफारिश की है. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1)(4) , मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 की धारा 2 (6), भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10(1)(4), विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 27 (जी)और हिंदू दत्तक–ग्रहण एवं रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 18 (2)(सी) के मुताबिक पति पत्नी में से कोई भी यदि कुष्ठ रोग ग्रसित है तो यह तलाक का आधार हो सकता है. कानून की किताब में इन कानूनों को शामिल करने की जो सब से खास वजह थी, वह थी इस रोग के फैलाव को रोकने की. अब जबकि यह रोग लाइलाज नहीं रहा तो इन कानूनों का कोई औचित्य ही नहीं है. दरअसल इनके बने रहने से कुष्ठ रोगियों के प्रति जो पूर्वाग्रह समाज में बने हुए हैं, वह कभी समाप्त नहीं होंगे. उसी तरह से भीख मांगने के कानून हैं. जिनके मुताबिक अगर कुष्ठ रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति भीख मांगता है तो कुष्ठ रोगी और उससे संबंधित व्यक्ति को उनके लिए बने कुष्ठालय के हवाले कर देना चाहिए. इसके अतिरिक्त कानूनी सेवा अधिनियम 1987, मोटर वाहन अधिनियम 1988, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का विधेयक 2014, राज्य नगर निगम और पंचायती राज्य अधिनियमों के भेद–भाव पूर्ण प्रावधानों में संशोधन की शिफारिश आयोग ने पेश की है.

अंत में आयोग ने इस संबन्ध में एक नया विधेयक लाने और इस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों का जीवन बेहतर बनाने और उन्हें सामान्य जीवन गुजारने में मदद देने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं. जिसमें भेद–भाव ख़त्म करने, भूमि का अधिकार देने, रोज़गार हासिल करने का अधिकार देने, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश देने, पूर्वाग्रह से ग्रसित भाषा समाप्त करने और आज़ादी से कहीं आने–जाने और इलाज में रियायत देने और सामाजिक चेतना को जगाने का सुझाव दिया है. ज़ाहिर है जब दुनिया के बहुत सारे देश इस तरह का प्रावधान कर रहे हैं तो भारत को भी इस बीमारी से जूझ रहे लोगों की भलाई के लिए कुछ क़दम उठाने चाहिये. यह और अधिक ज़रूरी इस लिए भी हो जाता है क्योंकि विधि आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले वर्षों में इस रोग में गिरावट तो आई है लेकिन आज भी विश्व के 58 प्रतिशत रोगी भारत में पाए जाते हैं, जो शर्मनाक भी है और चिंता जनक भी. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) के मुताबिक भारत में हर साल कुष्ठ रोग के 1.25 से 1.35 लाख नये मामले सामने आते हैं, और उनमें सबसे अधिक संख्या बच्चों की होती है. कुष्ठ से सम्बंधित कानूनों कि वजह से वे बहुत कम आयु में ही भेद भाव के शिकार हो जाते हैं. हालांकि कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति का जीवन स्तर सुधारने की राह में सामाजिक रवैया सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन इस संबंध में आयोग द्वारा चिन्हित किये गए कानून से जल्द से जल्द छुटकारा हासिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कानून कोढ़ में खाज के जैसे हैं.■

नाजियों को दी मनोवैज्ञानिक शिकस्त

रोम में रहने के दौरान बारबरा ने जर्मन बंदियों को अपने साथ मिलाकर एक टीम बनाई. जिसका इस्तेमाल उन्होंने काउंटरइंटेलिजेंस की तौर पर करना शुरू कर दिया. इस टीम के लिए जर्मन बंदियों को चुनने का कारण यह था कि इन बंदियों का इस्तेमाल करके आसानी से जर्मन सेना में सेंध लगाई जा सकती थी. उन्होंने साउरक्राउत नाम का ऑपरेशन शुरू किया.

अरुण तिवारी

feedback@chauthiduniya.com

महिला जासूसों की अपनी इस श्रृंखला में हमने इसके पहले ऐसी कई जासूसों के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाई जिन्होंने अपनी बहादुरी का जलवा दुश्मनों के समक्ष रणश्रेत्र में किया था. इस अंक में हम आपका परिचय एक ऐसी महिला से कराएंगे जिसने नाजियों के खिलाफ मनोवैज्ञानिक जंग की कमान संभाली थी और उन्हें पटकनी दी थी. उनका नाम था बारबरा लावर्स. बारबरा ने इटली मे रहते हुए अमेरिकी मोरेल ऑपरेशन की कमान संभाली थी. मोरेल ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन होते थे जिनमें शत्रु को सीधे युद्ध में परास्त करने की बजाए उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता था. बारबरा ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया था.

बारबरा का जन्म 22 अगस्त 1914 को ब्रानो में हुआ था जो उस समय ऑस्ट्रिया–हंगरी राजतंत्र का हिस्सा था. बड़ी होकर वे एक वकील बनीं और द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले उन्होंने पत्रकारिता के पेशे को अपना लिया था. बारबरा शादी के बाद बेल्जियन कांगो चली गईं और जैसे–जैसे विश्व युद्ध की विभीषिका बढ़ती गई तो दंपत्ति ने अमेरिका की तरफ रुख किया. पर्ल हार्बर पर हुई बमबारी के बाद बारबरा के पति ने सेना ज्वाइन कर ली. वहीं बारबरा ने चेक दूतावास में नौकरी कर ली. लेकिन जल्दी ही उन्होंने भी सेना की खुफिया शाखा ज्वाइन कर ली और अपनी सेवाएं देने के लिए रोम चली गईं. रोम में बारबरा ने नाजी सैनिकों के छक्के छुड़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक चालें चलना शुरू कीं.

रोम में रहने के दौरान बारबरा ने जर्मन बंदियों को अपने साथ मिलाकर एक टीम बनाई. जिसका इस्तेमाल उन्होंने काउंटरइंटेलिजेंस की तौर पर करना शुरू कर दिया. इस टीम के लिए जर्मन बंदियों को चुनने का कारण यह था कि इन बंदियों का इस्तेमाल करके आसानी से जर्मन सेना में सेंध लगाई जा सकती थी. उन्होंने साउरक्राउत नाम का ऑपरेशन शुरू किया. उन्होंने इटली के उन सभी इलाकों में हिटलर के खिलाफ प्रोपेगैंडा फैलाना शुरू किया, जिन इलाकों पर

मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो गया था. लोगों वहां के लोगों में हिटलर के खिलाफ कई तरह की गलत जानकारियां देना शुरू कर दिया. जिससे लोगों में हिटलर के खिलाफ अधिक डर बैठ जाए और वो उसे और अधिक नापसंद करना शुरू कर दें.

बारबरा ने वहां पर लीग ऑफ लोनली वॉर वुमेन नाम की संस्थां भी बनाई थी. यह एक छद्म संस्था थी जिसका निर्माण नाजी सैनिकों को हतोत्साहित करने के लिए किया गया था. इसके जरिये बारबरा नाजी सैनिकों की पत्नियों की तरफ से छद्म चिट्ठियां लिखवाया करती थीं. इन चिट्ठियों में यह लिखा होता था कि नाजी छुट्टी लेकर घर जाने के लिए अपने अधिकारियों से झगड़ने लगे. अधिकारियों के लिए इस स्थिति से निपटना मुश्किल होने लगा. सबसे मजेदार बात तो यह हुई कि उनके इस ऑपरेशन की वजह से एक बार वॉशिंगटन पोस्ट अखबार भी बेवकूफ बन गया था. अखबार को यह खबर लगी कि कई जर्मन सैनिक अपने घर गए हुए हैं तो उसने यह खबर छाप दी कि जर्मन सैनिक अपनी महिला मित्रों की तलाश में इटली के फ्रंट से वापस अपने देश गए हुए हैं. ये सैनिक अपने रिश्ते बचाने के लिए घर गए हुए हैं क्योकि उनकी पत्नियां उनसे बेवफाई कर रही हैं. दरअसल यह खबर अखबार को इटली में ही एक सर्कुलर से मिली थी जिसे जर्मन सैनिकों के लिए लिखा गया था. लेकिन वास्तविकता में वह सर्कुलर तो बारबरा ने लिखा था और जर्मन बंदियों से बंटवाया था. वॉशिंगटन पोस्ट अखबार तक का चक्कर में पड़ जाना बारबरा के इस ऑपरेशन की कामयाबी को बयान करता है.

बारबरा ने एक और ऑपरेशन को कामयाब बनाया था जिसके लिए उन्हें ब्रान्ज क्रास दिया गया था. इस ऑपरेशन के दौरान बारबरा ने सैनिकों की एक टुकड़ी के दिमाग में ऐसी विरोधी बातें भरी थीं कि इन सैनिकों ने जर्मन सेना का साथ देने से इंकार कर दिया था और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया था.

जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई तो वे वापस अमेरिका लौट गईं. इसके बाद भी वे कई तरह के सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहीं. सामाजिक कार्यों के प्रति उनके मन में रुझान पूरी जिंदगी रहा. साल 2009 में उनकी मौत हो गई. दरअसल बारबरा ने समाज से कुरीतियों को खत्म करने को भी अपनी जिम्मेदारी माना और कई काम किए.■

प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा

सफलता के नए सोपान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपनी यात्रा के दौरान फ्रांस,जर्मनी और कनाडा के साथ जो साझेदारी स्थापित किया, वह एक मिशाल है. आतंकवाद, रेलवे, सामरिक और अंतरिक्ष सहित अन्य क्षेत्रों में पीएम ने इन विकसित देशों से भारत के लिए जो निवेश आकर्षित किया, उससे आनेवाले समय में भारत इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नये सोपान तय करेगा, यह तय है.

राजीव रंजन

फ्रांस, जर्मनी और कनाडा, ये तीनों देश जी–7 देश हैं तथा औद्योगिक लोकतंत्र भी हैं. इन देशों के साथ साझेदारी स्थापित करने में भारत का बड़ा आर्थिक हित है. वे हमारे अनेक राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों के लिए फिट बैठते हैं. वे लोकतांत्रिक देश भी हैं. इसलिए, इस मायने में उनके साथ हमारा एक बड़ा राजनीतिक तालमेल भी है. फ्रांस के साथ हमारे संबंध परंपरागत रूप से रक्षा, अंतरिक्ष एवं परमाणु के क्षेत्र में रहे हैं तथा ये तीनों इस संबंध के प्रमुख आयाम हैं. जहां तक रक्षा क्षेत्र का संबंध है, फ्रांस की कंपनियां इसमें बहुत सक्षम और अनुभवी हैं. भारत और फ्रांस के बीच 17 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं. फ्रांस आने वाले समय में भारत में 2 बिलियन यूरो का निवेश करेगा. साथ ही वह भारत के तीन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएगा. नागपुर और पॉन्डिचेरी इस लिस्ट में शामिल हैं. मोदी को एक और सफलता हाथ लगी है कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद को आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ देने के लिए राजी कर लिया है. मोदी ने कहा है कि फ्रांस की कंपनी रक्षा क्षेत्र में भारत का सहयोग करेगी और भारत में रक्षा उपकरण बनाएगी. मोदी ने बताया कि भारत फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदेगा. भारत–फ्रांस सामरिक संबंधों को नये स्तर पर ले जाते हुए मोदी और ओलांद ने महाराष्ट्र में रुकी हुई जैतापुर परमाणु परियोजना पर आगे बढ़ने पर भी सहमति व्यक्त की. मेक इन इंडिया को मुख्य विषय मानते हुए दोनों पक्षों ने असैन्य परमाणु, शहरी विकास, रेलवे और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में करीब 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए. जैतापुर परियोजना से करीब 10 हजार मेगावाट क्षमता का बिजली उत्पादन होगा. फ्रांस ने भारत को अपने उस निर्णय के बारे में सूचित किया, जिसमें भारतीय पर्यटकों के लिए 48 घंटे में शीघ्र वीजा देने की योजना लागू करने की बात कही गई है.

दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत वे संयुक्त रूप से ग्रहों से संबंधित अभियान पर आगे बढ़ेंगे.

अगर हम जर्मनी की बात करें, तो भारत का पूरा फोकस विनिर्माण पर होगा. जर्मनी को विश्व में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माता के रूप में माना जाता है. वास्तव में, हन्नोवर फेयर से हमें जर्मनी की कंपनियों के साथ भारतीय कंपनियों की मैच मेकिंग का अवसर प्राप्त भी हुआ. इसके अलावा, यह भी माना जाता है कि जर्मनी में विश्व का सर्वश्रेष्ठ कौशल विकास कार्यक्रम है, जो हमारे लिए फायदेमंद है. जर्मन कार्यक्रम का तीसरा बड़ा पहलू यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा में वर्चस्व की उनकी स्थिति पर हम आस लगाए बैठे हैं. जर्मनी के हन्नोवर में इस साल हन्नोवर फेयर है, जो भारतीय कंपनियों के निवेश की तलाश के लिए माकूल समय और जगह प्रदान करता है. हन्नोवर को इस वजह से चुना गया है कि हन्नोवर मेस्से, जो इस साल हन्नोवर फेयर है, में हम पार्टनर कंट्री हैं. वहां हमारी भारतीय कंपनियों की बहुत बड़ी उपस्थिति है.

प्रधानमंत्री जी की कनाडा यात्रा भी काफी अहमियत रखती है, क्योंकि चालीस साल बाद यह कनाडा की प्रधानमंत्री के स्तर पर पहली यात्रा है. प्रधानमंत्री के स्तर पर पिछली यात्रा 1973 में हुई थी. इस प्रकार, यह 42 साल बाद हो रही है. वास्तव में हम कनाडा को निवेश, व्यापार एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने स्वयं के विकास संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखते हैं. कनाडा विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. इसके अलावा, यदि हम परिसंपत्तियों की दृष्टि से देखें, तो उनके पांच शीर्ष पेंशन फंड अकेले ही लगभग 700 बिलियन डॉलर की परिसंपत्तियों का नियंत्रण करते हैं. इस प्रकार, यहां निवेश की प्रचुर संभावनाएं हैं. कनाडा ऊर्जा की दृष्टि से भी सुपर पावर है और यहां पर विश्व की सर्वोत्तम शोध संस्थाएं और विश्वविद्यालय स्थित हैं. दूसरी बात कि कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की आबादी 1.2 मिलियन है, जो मायने रखती है. भारत और कनाडा जिस प्रौद्योगिकी का अनुसरण करते हैं, उसे पी एच डब्ल्यू आर (प्रेशरराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर) कहा जाता है. कनाडा विश्व में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है. वास्तव में, विश्व के 16 प्रतिशत यूरेनियम भंडार कनाडा में हैं. इसे देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर की मौजूदगी में कमेको और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग ने 35 करोड़ डॉलर की यूरेनियम आपूर्ति के लिए एक समझौता किया. इस नये करार के तहत अगले पांच वर्षों में भारत, कनाडा से तीन हजार टन से ज्यादा यूरेनियम खरीदेगा. इसका इस्तेमाल भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में किया जाएगा.

रूस और कजाकिस्तान के बाद कनाडा तीसरा देश है, जो भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा. यूरेनियम आपूर्ति से भारत के हरित ऊर्जा मिशन को पूरा करने में मदद मिलेगी. स्वच्छ ऊर्जा मानवता के लिए हमारी वैश्विक जिम्मेदारी है. स्वच्छ ऊर्जा मिशन के लिए यूरेनियम बेहद जरूरी है. इस समझौते से हमारे मिशन के पूरा होने में मदद मिलेगी. भारत और कनाडा ने मुक्त व्यापार समझौते के बारे में भी प्रतिबद्धता जताई है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बाजार खोलने संबंधी इस समझौते की रूपरेखा सितंबर तक तैयार कर ली जाएगी. मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौता (बीआईपीपीए) भी जल्द कर लिया जायेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

आतंक फैलाने के लिए आज़ाद हुआ लखवी

क्या मोदी सरकार ने भारत–पाक बॉर्डर पर पाक प्रायोजित आतंकी गतिविधियों को लेकर भारत ने जो सख्ती दिखाई है, उससे पाकिस्तान तिलमिला गया है? क्या लखवी की रिहाई के पीछे भारत में किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश है? आखिर क्यों लखवी की रिहाई की खुशी में पाक में उसके घर पर पाकिस्तानी अधिकारियों और आतंकवादियों के बीच जमकर पार्टी हुई? मसला चाहे जो भी हो, लेकिन लखवी की रिहाई पर पाक सरकार के नापाक इरादे को लेकर भारत सहित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जबरदस्त आलोचना हुई है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

अभी लश्कर–ए–तैयबा के ऑपरेशन कमांडर और 2008 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी की रिहाई हुई ही थी कि उसके तुरंत बाद ही सुरक्षा एजेंसियों ने मुंबई सहित देश के कई शहरों में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया. आईबी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि एक लेटर मिला है, जिसके अनुसार दो से तीन महीने के अंदर मुंबई में बड़े पैमाने पर हमला हो सकता है. बड़ा सवाल यह है कि भारत के तमाम ऐतराजों के बावजूद खूंखार आतंकी लखवी जेल से बाहर आ कैसे गया? लखवी की रिहाई को भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार की आतंक पर लगाम लगाने की असफलता नीति के रूप में भी देखा जा रहा है. लखवी की रिहाई के पीछे आनेवाले दिनों में पाकिस्तान द्वारा भारत में किसी बड़े हमले की योजना भी हो सकती है. हालांकि भारत के सुरक्षा तंत्र ने एक आंकलन तैयार किया है, जिसकी समीक्षा जारी है. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान लखवी को गुड टेररिस्ट की श्रेणी में रखता है और उसके खिलाफ वह कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान भारत विरोधी अपनी मंशा को इतनी आसानी से पूरा कर ले, ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि फ्रांस, अमेरिका और इजरायल की तरफ से लखवी की रिहाई के मुद्दे पर पाकिस्तान को मिली फटकार के बाद भारत उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग–थलग करने की अपनी कोशिशों को और तेज करेगा. एक खास बात यह है कि इस बार कोशिश सिर्फ विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के स्तर पर नहीं होगी, बल्कि विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के स्तर पर भी पाक के दोहरे चरित्र को बेनकाब किया जाएगा. एक बात और ध्यान देने लायक है कि हो सकता है पाकिस्तान लखवी पर भारत से और अधिक सबूत की मांग करे, लेकिन भारत को यह बात ध्यान देना होगा कि वह किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को अब लखवी के मसले पर कोई सबूत न दे, क्योंकि भारतीय अधिकारियों का भी कहना है कि लखवी के मसले पर पाक सरकार को काफी सबूत दिए जा चुके हैं. ऐसे में अगर भारत फिर से कोई सबूत सौंपने की कोशिश करता है, तो वह भारतीय विदेश नीति को कमजोर ही करेगा और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की किरकिरी ही होगी.

मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी की रिहाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना शुरू हो गई है. लखवी की रिहाई पर अमेरिका ने भी चिंता व्यक्त की. अमेरिका का कहना है कि आतंकवादी हमले सभी देशों की सामूहिक सुरक्षा व बचाव पर एक हमला है. हालांकि पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का यह नाटक कोई नया नहीं है. नाटक इसलिए कि जब अमेरिका से पूछा

गया कि क्या उसके विरोध का असर पाकिस्तान पर किसी भी प्रकार से पड़ सकता है? इस पर उसका जवाब था कि उसने पाकिस्तान के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन वह किसी तरह के परिणामों और नतीजों का अनुमान नहीं लगा सकते. फ्रांस ने भी भारत के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि लखवी की रिहाई न तो भारत के लिए ठीक है और न ही दुनिया के लिए. फ्रांस ने यह स्टेटमेंट उस समय दिया, जब भारतीय पीएम फ्रांस के दौरे पर थे. यही बात भारत को समझनी होगी कि किसी देश का चेहरा देख कर या उस देश की नीति के अनुसार भारत अपनी नीति न बनाए, जैसा कि भारत शुरू से ही करता आ रहा है. आजभारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी खामी यही है कि उसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है और वह पाकिस्तान या अन्य देश के मसले पर अमेरिका या अन्य देशों की प्रतिक्रिया आने का इंतजार करता है और उसके बाद हो–हल्ला मचाता है. यही कारण है कि भारत को पाकिस्तान जैसे देशों पर कुछ खास सफलता हासिल होती नहीं दिखती. क्या अमेरिका भारत से या किसी अन्य देश से यह पूछने आता है कि पाकिस्तान में छिपे ओसामा बिन लादेन पर कार्रवाई करे या नहीं.

भारत ने लखवी की रिहाई को मुंबई हमले के पीड़ितों का अपमान बताया है. उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के दोहरे मानदंड की ओर ध्यान दिलाया है. भारत यहीं गलत करता है. एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि भारत इस बात को समझने में देर क्यों कर रहा है कि उस पर आतंकी हमलों का असर विदेशों पर नहीं पड़ता. खासतौर पर उस समय तक जब तक कि वह देश भी पाकिस्तानी या अन्य तरह के आतंकवाद का निरंतर भुक्तभोगी न हो. अगर यह बात सच नहीं होती तो आखिर अमेरिका हाल ही में पाकिस्तान को एक बिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता क्यों देता? भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी अरब को भी यमन में जारी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की जरूरत है. इसलिए सभी देश अपने हक में ही पाकिस्तान के पक्ष या विपक्ष में फैसला लेंगे. जब तक भारत अन्य देशों का मुंह देखता रहेगा, उसे पाकिस्तान के प्रति सख्त रवैया अपनाने में कभी सफलता नहीं मिलेगी और न ही अन्य देशों की तरफ से पाकिस्तान पर कोई सख्त कार्रवाई का भरोसा ही मिलेगा. भारत को चाहिए कि वह आतंकवाद के मुद्दे पर सीधे और प्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान से निपटे, क्योंकि पाक आतंकवाद का असली भुक्तभोगी भारत ही है. बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान पूछे गए प्रश्नों के जवाब में जो कहा, वह भारतीय पीएम की आतंकवाद के मुद्दे पर चिंता को व्यक्त करता है. उन्होंने कहा कि जितनी सेंसिटिविटी न्यूक्लियर वेपन को लेकर के है, उतनी ही आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के प्रति भी होनी चाहिए. गृहमंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि भारत पाक के साथ बातचीत करना चाहता है, लेकिन लखवी की रिहाई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है. ऐसे कदमों से दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर असर पड़ता है. सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान को भारत के साथ अपने रिश्ते की परवाह है? क्या पाकिस्तान आतंक के रास्ते से हटकर भारत के साथ अपने रिश्ते पर गंभीरता से विचार कर रहा है? इसका जवाब न में ही होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान को भारत के साथ अपने रिश्तों के बनने या बिगड़ने की परवाह होती, तो वह भारत द्वारा दिए गए सबूत चाहे वह कसाब के बयान हों, डेविड हेडली या फिर अबू जिंदाल के बयान हों, की परवाह जरूर करता, लेकिन इसके उलट पाकिस्तान ने भारत द्वारा दिए गए किसी भी सबूत को तरजीह नहीं दी.

लखवी की रिहाई का विरोध सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के पड़ोसी मुल्क और लखवी के अपने ही देश पाकिस्तान में भी हो रहा है. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने लखवी की रिहाई को पाक सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कहा है कि लखवी की रिहाई से उसके लिए मुश्किल बढ़ गई है. सरकार ने अपनी दलील में यहां तक कहा है कि लखवी की रिहाई से मुंबई हमले मामले की जांच भी प्रभावित हो सकती है. पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए लखवी को फिर से सिक्योरिटी ऐक्ट के तहत हिरासत में लिया जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जो प्रयत्न द्वारा अंततः मुक्ति पा ही लेते हैं. लेकिन दोनों में एक श्रेणी और होती है जो खुद को बचाए रहती है. एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह श्रेणी कैसी है? परमहंस देव बोले, हां, वह बड़ी महत्वपूर्ण है. इस श्रेणी के मनुष्य उन मछलियों के समान हैं जो जाल के निकट कभी नहीं आतीं और जब वे निकट ही नहीं आतीं, तो उनके फंसने का प्रश्न ही नहीं उठता.

साई का हर संदेश राह दिखाता है

चौथी दुनिया ब्यूरो

इस विश्व में असंख्य संत हैं, परंतु अपना पिता (गुरु) ही सच्चा पिता (सच्चा गुरु) है. दूसरे चाहे कितने ही मधुर वचन क्यों न कहते हों, परंतु अपने गुरु का उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए. संक्षेप में सार यही है कि शुद्ध हृदय से अपने गुरु से प्रेम कर, उनकी शरण जाओ और उन्हें श्रद्धापूर्वक साष्टांग नमस्कार करो. तभी तुम देखोगे कि तुम्हारे सम्मुख भवसागर का अस्तित्व वैसा ही है, जैसा सूर्य के समक्ष अंधेरे का. सच तो यह है कि बाबा की हर कथा में कुछ न कुछ संदेश छिपा रहता है.

यह सभी साई भक्त जानते हैं कि बाबा ने काका साहेब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के दो ग्रंथ श्रीमद्भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी. काकासाहेब इन ग्रंथों का नियमपूर्वक पठन बाबा के समय से करते आए हैं और बाबा के समाधि लेने के उपरांत भी वह उसी प्रकार अध्ययन करते रहे. एक समय चौपाटी (मुंबई) में काकासाहेब प्रातःकाल एकनाथी भागवत का पाठ कर रहे थे. माधवराव देशपांडे (शामा) और काका महाजनी भी उस समय वहां उपस्थित थे. ये दोनों ध्यानपूर्वक पाठ श्रवण कर रहे थे. उस समय 11वें स्कंध के द्वितीय अध्याय का वाचन चल रहा था, जिसमें नवनाथ अर्थात ऋषभ वंश के सिद्ध यानी कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोर्त्र, द्रुमिल, चमस और कर भाजन का वर्णन है, जिन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनक को समझायी थी. राजा जनक ने इन नवनाथों से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और इन सभी ने उनकी शंकाओं का बड़ा संतोषजनक समाधान भी किया था. पठन समाप्त होने पर काकासाहेब बहुत निराशापूर्ण स्वर में माधवराव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना है, परंतु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है. माधवराव को यह निराशावादी धारणा अच्छी नहीं लगी. वह कहने लगे कि हमारा अहोभाग्य है, जिसके फलस्वरूप ही हमें साई सदृश अमूल्य हीरा हाथ लग गया है, तब फिर इस प्रकार का राग अलापना बड़ी निंदनीय बात है. यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है, तो फिर इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता ही क्या है? माना कि नवनाथों की भक्ति अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ और प्रबल होगी, परंतु क्या हम लोग भी प्रेम और स्नेहपूर्वक भक्ति नहीं कर रहे हैं. क्या बाबा ने अधिकारपूर्ण वाणी में नहीं कहा है कि श्रीहरि या गुरु के नाम जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है. तब फिर भय और चिंता का स्थान ही कहां रह जाता है. परंतु फिर भी माधवराव के वचनों से काकासाहेब का समाधान न हुआ. वे फिर भी दिन भर व्यग्र और चिंतित ही रहे. दरअसल, यह विचार उनके मस्तिष्क में बार-बार चक्कर काट रहा था कि किस विधि से नवनाथों के समान भक्ति की प्राप्ति संभव हो सकेगी. एक महाशय, जिनका नाम आनंदराव पाखाडे था, माधवराव को ढूंढते-ढूंढते वहां आ पहुंचे. उस समय भागवत का पठन हो रहा था. श्री पाखाडे भी माधवराव के समीप जाकर बैठ गए और उनसे धीरे-धीरे कुछ वार्ता भी करने लगे. वे अपना स्वप्न माधवराव को सुना रहे थे.

इनकी कानाफूसी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा. अतएव काकासाहेब ने पाठ स्थगित कर माधवराव से पूछा कि क्यों, क्या बात हो रही है? माधवराव ने कहा कि कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था, यह चर्चा भी उसी का समाधान है. कल बाबा ने श्री पाखाडे को जो स्वप्न दिया है, उसे उनसे ही सुनो. उसमें बताया गया है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या उनका पूजन करना ही पर्याप्त है. सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र इच्छा थी और सबसे अधिक काकासाहेब को. सभी के कहने पर श्री पाखाडे अपना स्वप्न सुनाने लगे, जो इस प्रकार है. मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हुआ हूं. पानी मेरी कमर तक है और अचानक जब मैंने ऊपर देखा, तो साईबाबा के श्री-दर्शन हुए. वे एक रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री-चरण जल के भीतर थे. यह दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देखकर मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ. इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कह सकेगा. मैंने देखा कि माधवराव भी बाबा के समीप ही खड़े हैं और उन्होंने मुझसे भावुकतापूर्ण शब्दों में कहा कि आनंदराव, बाबा के श्री-चरणों पर गिरो. मैंने उत्तर दिया कि मैं भी यही करना चाहता हूं. परंतु उनके श्री-चरण तो जल के भीतर हैं. अब बताओ कि मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूं. मैं तो निस्सहाय हूं. इन शब्दों को सुनकर शामा ने बाबा से कहा कि अरे देवा, जल में से कृपाकर अपने चरण बाहर निकालिए. बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैं उनसे तुरंत लिपट गया. बाबा ने मुझे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंदपूर्वक जाओ. घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है. अब तुम्हारा कल्याण होगा. उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि एक ज़री के किनारों की धोती मेरे शामा को दे देना, उससे तुम्हें बहुत लाभ होगा. बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही श्री पाखाडे धोती लाए और काकासाहेब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए, परंतु माधवराव ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया. उन्होंने कहा कि जब तक बाबा से मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होती, तब तक मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं. कुछ तर्क-वितर्क के पश्चारत काका ने दैवी आदेशसूचक पर्चियां निकालकर इस बात का निर्णय करने का विचार किया. काकासाहेब का यह नियम था कि जब उन्हें कोई संदेह हो जाता, तो वे काग़ज़ की दो पर्चियों पर स्वीकार-अस्वीकार लिखकर उसमें से एक पर्ची निकालते थे और जो कुछ उत्तर प्राप्त होता था, उसके अनुसार ही कार्य किया करते थे. इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने उपयुक्त विधि के अनुसार ही दो पर्चियां लिखकर बाबा के चित्र के समक्ष रख दिया और एक अबोध बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा. बालक द्वारा उठाई गई पर्ची जब खोलकर देखी गई, तो वह स्वीकारसूचक पर्ची ही निकली और तब माधवराव को धोती स्वीकार करनी पड़ी. इस प्रकार आनंदराव और माधवराव संतुष्ट हो गए और काकासाहेब का संदेह भी दूर हो गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

पॉलीथीन पर लगे रोक

समाचार पत्र पढ़ने वालों ने दर्जनों बार पढ़ा होगा कि सरकार चाहती है कि निश्चित मानक से पतली पॉलीथीन का प्रयोग लोग न करें, क्योंकि यह अविघटित होने के कारण धरती की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रही है. यदि ऐसा हो तो सरकार इसके उत्पादन पर रोक क्यों नहीं लगाती? जब उत्पादन ही बंद हो जाएगा तो लोग स्वत: इसका प्रयोग बंद कर देंगे. हमारे देश का यही दुर्भाग्य है कि यहां समस्या की जड़ को समाप्त करने पर विचार नहीं किया जाता है.

-राजकिशोर पांडेय(प्रहरी), लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

बात नहीं काम करने की जरूरत है

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने धर्म की आजादी और देश में असामानता की बात की. सीरी फोर्ट सभागार में ओबामा का भाषण राजनीतिक संचार का बेहतरीन नमूना था. उसमें मित्रता का भाव था, दूरदर्शिता थी, गंभीरता थी और साथ ही उपदेश भी शामिल था. धर्म की आजादी पर ओबामा की बातों को केन्द्र सरकार और भाजपा के लिए एक चेतावनी की तरह देखा जा सकता है. क्योंकि पिछले दिनों धर्मांतरण का मुद्दा जोरों पर था. सरकार अपने प्रदर्शन को किस हद तक समझ पा रही है. यह यक्ष प्रश्न है. अपने ही शब्दाडंबर पर यकीन करना सरकार की भूल होगी. हमारी नई केन्द्र सरकार को दिखावे से आगे निकलने की जरूरत है. जनतंत्र में प्रभावी राजनीतिक नियंत्रण और दिशा निर्देश बेहद महत्वपूर्ण है. मोदी सरकार भारतीय नौकरशाही को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए जो कुछ कर रही है वह सही है. लेकिन सरकार कब काम करेगी? क्योंकि अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है.

-अशोक निर्मोही, दरभंगा, बिहार.

न्याय व्यस्था पर दाग

मेरठ के हाशिमपुरा में 22 मई 1987 को पीएसी जवानों द्वारा कथित एक समुदाय के 42 लोगों की बर्बर हत्या के 28 वर्ष बाद दोषी पुलिस कर्मियों को पहचान के अभाव में बरी हो जाना पुलिस बल में व्याप्त भ्रष्टाचार का नमूना है. न्याय में होता देरी भारतीय न्याय व्यवस्था पर दाग है, जिससे हर अपराधी तकनीकी पेंच और प्रभाव का इस्तेमाल करके इतना विलंब करा लेता है कि साक्ष्य समाप्त हो जाए और गवाह न मिलने पर वह छूट जाए. अत: भारतीय न्याय प्रणाली में ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिसमें अपराधी को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का अवसर ही न मिले.

-सत्य प्रकाश (शिक्षक) लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

सच्ची पत्रकारिता यही है

कलम की बेताज दुनिया में चौथी दुनिया का हर अंक आमजन मानस को शुकून और राहत देने वाला और भ्रष्ट नौकरशाही के लिए आफत भरा होता है. घोटालों का कॉरपोरेशन आवरण कथा में घोटाले बाजों की दागभरी छवि को सार्वजनिक करने का साहस दिया है. किसानों की दुखभरी कहानी पर सरकार की लाचारी और बेरुखी भी इस धरती के अन्नदाता की बदनसीबी को और बढ़ाती है. साहित्य पर आपके नियमित स्तंभ बहुत प्रेरणादायी है.

-छैलबिहारी शर्मा, छाता, उत्तर प्रदेश.

सीबीआई जांच की जरूरत

नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की जांच कर रही एसीबी की टीम द्वारा पूर्व में घोटाले से संबंधित नामों वाली डायरी मिलने का जिक्र किया गया था, लेकिन अब ऐसी किसी डायरी के मिलने से मुकर रही है, जो संदेह को जन्म देता है. संदिग्ध मंत्रियों व रसूखदारों को बचाने का तो यह खेल नहीं खेला जा रहा है. क्या एसीबी द्वारा जांच के दौरान वीडियो रिकार्डिंग की गई थी. यदि नहीं तो डायरी का सबूत आसानी से मिटाया जा सकता है. यदि वीडियो रिकार्डिंग की गई तो उसमें डायरी की बात जांची जा सकती है, बशर्ते वीडियो रिकार्डिंग जानबूझकर खराब या डिलीट न की गई हो. चाहे जो हो, अब जांच सीबीआई से कराये बिना सच सामने आने वाला नहीं है और छत्तीसगढ़ सरकार ऐसी जांच किसी कीमत में नहीं करवाने वाली. अब असली घोटालेबाज भले बच जाएं. लेकिन जनमानस में सरकार की छवि तो जरूर धूमिल हुई है.

-सुरेश वाहने, शिवनगर कुम्हारी, दुर्ग, छत्तीसगढ़.

न्याय कब मिलेगा

मैंने 06 अप्रैल-12 अप्रैल 2015 के अंक में संपादकीय पेज पर प्रकाशित आलेख देश को किस रास्ते पर जाना चाहिए, विक्रम मल्लाह और फूलन देवी-5 औरत फिर बनी मौत की वजह, राहुल गांधी का अप्रासंगिक होना और जब तोप मुकाबिल हो राजनीतिक तंत्र को ज़िम्मेदार बनाने की ज़रूरत है पढ़ा बेहद प्रभावित किया. संतोष भारतीय ने अपने संपादकीय में सही कहा है कि हाशिमपुरा हत्याकांड ऐसा मसला है, जो ये बताता है कि अगर आप सरकार के अंग हैं और आपने अत्याचार किए हैं या हत्याएं की हैं, तो जांच एजेंसियां भी आपकी मदद करेंगी. आप सस्पेंड भी नहीं होंगे. आप गिरफ्तार भी नहीं होंगे. क्योंकि जांच एंजेसिया जो सत्ता में होता है उसके इशारे पर कार्य करती हैं.

-उमाशंकर सिंह, बक्सर, बिहार.

लघु कथा

सबसे बड़ी बात

एक दिन सुबह के समय परमहंस देव अपने शिष्यों के साथ टहल रहे थे. तभी उन्होंने देखा कि पास ही कुछ मछुआरे जाल फेंक कर मछलियां पकड़ रहे हैं. वह अचानक एक मछुआरे के पास पहुंचकर खड़े हो गए और अपने शिष्यों से बोले, तुम लोग इस जाल में फंसी मछलियों की गतिविधियां गौर से देखो. शिष्यों ने देखा कि कुछ मछलियां ऐसी हैं जो जाल में निश्चल पड़ी हैं. वे निकलने की कोई कोशिश भी नहीं कर रही हैं, जबकि कुछ मछलियां जाल से निकलने की कोशिश करती रहीं. हालांकि, उनमें कुछ को सफलता नहीं मिली, लेकिन कुछ जाल से मुक्त होकर फिर से जल में खेलने में मगन हैं.

जब परमहंस ने देखा कि शिष्य मछलियों को देखने में मगन होकर दूर निकल गए हैं, तो फिर उन्हें अपने पास बुला लिया. शिष्य आ गए तो कहा, जिस प्रकार मछलियां मुख्यत: तीन प्रकार की होती हैं, वैसे ही अधिकतर मनुष्य भी तीन प्रकार के होते हैं. एक श्रेणी उन मनुष्यों की होती है, जिनकी आत्मा ने बंधन स्वीकार कर लिया है. अब वे इस भव-जाल से निकलने की बात ही नहीं सोचते. दूसरी श्रेणी ऐसे व्यक्तियों की है, जो वीरों की तरह प्रयत्न तो करते हैं पर मुक्ति से वंचित रहते हैं. तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जो प्रयत्न द्वारा अंतत: मुक्ति पा ही लेते हैं. लेकिन दोनों में एक श्रेणी और होती है जो खुद को बचाए रहती है. एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह श्रेणी कैसी है? परमहंस देव बोले, हां, वह बड़ी महत्वपूर्ण है. इस श्रेणी के मनुष्य उन मछलियों के समान हैं जो जाल के निकट कभी नहीं आतीं और जब वे निकट ही नहीं आतीं, तो उनके फंसने का प्रश्न ही नहीं उठता. ■

जब परमहंस ने देखा कि शिष्य मछलियों को देखने में मगन होकर दूर निकल गए हैं, तो फिर उन्हें अपने पास बुला लिया. शिष्य आ गए तो कहा, जिस प्रकार मछलियां मुख्यत: तीन प्रकार की होती हैं, वैसे ही अधिकतर मनुष्य भी तीन प्रकार के होते हैं.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

चुनिंदा सत्य के ख़तरे

अनंत विजय

मराठी एक ऐसा शब्द है, जिसे महाराष्ट्र में राजनीति करने वाले सभी दल लगातार भुनाते रहे हैं, भुना रहे हैं और आगे भी भुनाते रहेंगे. राजनीतिक दलों को लगता है कि मराठी अस्मिता के नाम पर वे जो भी कार्ड खेलेंगे, वह तुरुप का इक्का ही होगा. दरअसल, राजनीतिक दल अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए बहुधा इस तरह की चाल चलते हैं. कभी-कभार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए भी इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं. महाराष्ट्र में मराठी और मराठा मानुष के नाम पर राजनीति की एक लंबी परंपरा रही है. आज़ादी के बाद की परिस्थितियों में शिवसेना ने इसे काफी भुनाया और राज ठाकरे की राजनीति की तो बुनियाद ही मराठी अस्मिता रही है. हालांकि, पिछले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने इस तरह की राजनीति करने वालों को उनकी सही जगह दिखा दी.

अब इसी मराठी भावना को भुनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मल्टीप्लैक्स को शाम छह बजे से नौ बजे तक मराठी फिल्में दिखाने का फरमान जारी कर दिया. यह एक ऐसा फरमान था, जिसके ख़िलाफ़ बुद्धिजीवियों को मजबूती से उठ खड़े होना चाहिए था. राजनेताओं से तो ऐसी अपेक्षा की नहीं जा सकती, क्योंकि जहां उन्हें संविधान और वोट बैंक में से किसी एक को चुनना होता है, तो उनकी प्राथमिकता वोट बैंक होती है. लेखकों की कोई मजबूरी नहीं होती है, उन्हें तो सत्य के साथ होना चाहिए. इस बार भी लगभग पूरा लेखक समाज चुप रहा, लेकिन अंग्रेजी की लेखिका एवं पत्रकार शोभा डे ने इसके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी. उन्होंने ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपना विरोध दर्ज कराया. उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के इस फरमान पर तंज कसते हुए लिखा कि अब मल्टीप्लैक्स में पॉपकार्न की जगह दही मिसल और वड़ा पाव मिला करेंगे. इसके अलावा भी उन्होंने कई ट्वीट करके अपना विरोध जताया.

शोभा डे के ट्वीट के बाद आगबबूला शिवसेना ने उनके ख़िलाफ़ बयानों की झड़ी लगा दी, लेकिन शोभा अपने स्टैंड पर कायम रहीं. इसके बाद शोभा डे के ख़िलाफ़ शिवसेना विधायक ने महाराष्ट्र विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस तक डे डाला, लेकिन शोभा टस से मस नहीं हुईं. इस बीच शोभा के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन तेज होने लगे, पुतले फूंके जाने लगे, उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, वड़ा पाव लेकर शिवसैनिक उनके घर तक जा पहुंचे, लेकिन हमारा लेखक समुदाय खामोश रहा. जितनी चिंता की बात सरकार का सिनेमाघरों को मराठी फिल्मों के लिए वक्त तय करना है, उससे ज़्यादा चिंता की बात लेखक और बुद्धिजीवी समुदाय का इस मुद्दे पर खामोश रहना है. यह एक ऐसा सवाल है, जिस पर देश भर के लेखकों को विचार करना होगा, गंभीरता से चिंतन और मनन करना होगा. इस तरह की खामोशी एक तरह से सरकारों को बल प्रदान करती है.

संविधान के नाम पर शपथ लेकर सत्ताधीश बने नेताओं के हौसले इस कदर बुलंद हो जाते हैं कि वे संविधान की परवाह करना छोड़ने की सोचने लगते हैं, लेकिन एक शोभा डे की पहल ने महाराष्ट्र सरकार को अपना फरमान बदलने के लिए मजबूर कर दिया. भारत में लेखकों एवं साहित्यकारों द्वारा सत्ता और उसके फ़ैसलों के विरोध की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन हाल के दिनों में उसका क्षरण रेखांकित किया जा सकता है. आज़ादी के बाद लेखक समुदाय हर मसले पर अपनी राय रखता था और उसे प्रकट करता था. पिछले लोकसभा चुनाव में भी मशहूर कन्नड़ लेखक अनंतमूर्ति ने नरेंद्र मोदी का विरोध किया था. यह अलहदा बात है कि विरोध करने के लिए उन्होंने जिन शब्दों का चयन किया था, वे अनुचित थे. उन्होंने मोदी के जीतने पर देश छोड़ने की बात कह दी थी, जिस पर बाद में उन्होंने सफाई भी दी.

राजनीति के आगे मशाल की तरह चलने वाला साहित्य इन दिनों उसी राजनीति का शिकार हो गया है. सत्य और चुनिंदा सत्य में जो फ़र्क़ होता है, उसने साहित्य जगत को बड़ा नुक़सान पहुंचाया. अगर हम हिंदी साहित्य की ही बात करें, तो देखते हैं कि साठ व सत्तर के दशक के बाद से लेखन और विमर्श में प्रतिरोध की खूब बातें हुईं. सत्ता के विरोध और प्रतिरोध के नाम पर जमकर सत्ता सुख भोगने के मामले भी सामने आए. प्रगतिशीलता, जनवाद आदि जैसे जुमले गढ़कर देश की जनता को गुमराह करने का खेल खेला गया. साहित्य में प्रगतिशीलता की कोई आवश्यकता ही नहीं थी. साहित्य तो खुद प्रगतिशील होता है. दरअसल, यह पूरा खेल अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर खेला गया था. लेखक संघ बनाए गए. जो भी लेखक संघ बने, वे किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े रहे और उनके बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की तरह काम करते रहे, लेकिन जनता के सामने अपना दूसरा चेहरा पेश कर उसे भरमाते रहे.

प्रगतिशील लेखक संघ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अंग रहा. उसी तरह जनवादी लेखक संघ सीपीएम का बौद्धिक प्रकोष्ठ बना रहा. जैसे-जैसे वामपंथी पार्टियों में विभाजन होते रहे, उनके लेखक प्रकोष्ठ बनते रहे. जब सीपीएम में विभाजन हुआ, तो एक और बौद्धिक प्रकोष्ठ बना, जिसका नाम पड़ा जन संस्कृति मंच. दरअसल, हमारा मानना है कि लेखकों को इन वामदलों ने सिद्धांत, प्रतिरोध, ग़रीब, दबे-कुचले जैसे शब्दों के नाम पर भ्रमित किया और फिर उनका फ़ायदा उठाया. जब ये लेखक संगठन इन पार्टियों के बौद्धिक प्रकोष्ठ की तरह काम करने लगे, तो जाहिर है कि उनके विरोध और प्रतिरोध में भी अपने राजनीतिक आकाओं की मुंहदेखी होने लगी. इसका सर्वोत्तम उदाहरण यह है कि प्रगतिशील लेखक संघ ने इमरजेंसी का समर्थन किया. इस तरह के कई उदाहरण हैं, लेकिन उनका उल्लेख यहां आवश्यक नहीं है.

शोभा डे के ट्वीट के बाद आगबबूला शिवसेना ने उनके ख़िलाफ़ बयानों की झड़ी लगा दी, लेकिन शोभा अपने स्टैंड पर कायम रहीं. इसके बाद शोभा डे के ख़िलाफ़ शिवसेना विधायक ने महाराष्ट्र विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस तक डे डाला, लेकिन शोभा टस से मस नहीं हुईं. इस बीच शोभा के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन तेज होने लगे, पुतले फूंके जाने लगे, उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, वड़ा पाव लेकर शिवसैनिक उनके घर तक जा पहुंचे, लेकिन हमारा लेखक समुदाय खामोश रहा.

अब तो प्रगतिशील लेखक संघ की हालत यह हो गई है कि वह लेखकों की सहमति के बगैर उन्हें पार्टी के पद बांट रही है. ताजा मामला पश्चिम बंगाल का है, जहां कवि राज्यवर्धन को बगैर उनकी जानकारी और सूचना के राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया. राज्यवर्धन ने फेसबुक पर इस बारे में लिखकर जानकारी साझा की है. पार्टियों के बौद्धिक प्रकोष्ठ बनने का नतीजा यह हुआ कि लेखकों ने चुनिंदा सत्य बोलना शुरू कर दिया. चुनिंदा और सुविधानुसार बोला गया सत्य झूठ से कहीं ज़्यादा नुक़सान पहुंचाता है. इन लेखक संगठनों से जुड़े रचनाकार तस्लीमा नसरीन के मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन वहीं एमएफ हुसैन के मामले में जोरदार विरोध शुरू हो जाता है. गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का विरोध करने वाले लोग सलमान रुश्दी के मामले में खामोश हो जाते हैं. क्या यह एक प्रकार की लेखकीय सांप्रदायिकता नहीं है?

कट्टरपंथी हिंदूवादी ताकतों के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले लेखक मुस्लिम कट्टरपंथ के ख़िलाफ़ बोलने में घबराने लगते हैं, उनकी ज़ुबान खामोश हो जाती है. ऐसे लेखकों को लगता है कि अगर वे मुस्लिम कट्टरपंथ के ख़िलाफ़ बोलेंगे, तो उन्हें सांप्रदायिक मान लिया जाएगा. सांप्रदायिकता और फासीवाद की आड़ लेने वाले लेखक उसी का शिकार होते चले गए. इस तरह की प्रवृत्ति लंबे समय तक चलती रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि लोगों का लेखकों से भरोसा उठता चला गया. लेखक भी सत्ता के हिसाब से अपनी प्राथमिकताएं तय करने लगे. राजनीति के आगे चलने वाली मशाल सत्ता की पिछलग्गू बन गई. जब आप सत्ता के पिछलग्गू बनेंगे, तो फिर उसके ख़िलाफ़ बोलने के साहस का ह्रास होता चला जाएगा. नतीजे के तौर पर हमें शोभा डे जैसे मामले देखने को मिलेंगे. शोभा डे के समर्थन में साहित्य जगत का न आना चौंकाता ही नहीं, बल्कि उसी धारणा को पुष्ट करता है. दरअसल, अगर हम पूरी गंभीरता से हिंदी के लेखकीय परिदृश्य पर विचार करें, तो निराशाजनक तस्वीर सामने आती है. मुक्तिबोध और उनकी कविता की पंक्ति-तोड़ने ही होंगे सारे गढ़ और मठ को नारे की तरह इस्तेमाल करने वाले लेखक गढ़ और मठ में शामिल होने की जुगत में लगे रहते हैं. कोई किसी अकादमी का सदस्य बनना चाहता है, तो कोई किसी सरकारी कमेटी में फिट होने के जुगाड़ में लगा रहता है. किसी की ख्वाहिश किसी विश्वविद्यालय का कुलपति बनने की होती है, तो कोई पुरस्कार के दंद-फंद में जुटा रहता है.

ऐसे परिदृश्य में यह अपेक्षा करना बेमानी है कि लेखक सरकारी फ़ैसलों के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत कर पाएंगे. सरकारी संरक्षण हासिल करने की लालसा लिए घूम रहे ऐसे लेखकों की भीड़ बढ़ती जा रही है. इसकी ऐतिहासिकता में अगर जाएं, तो इसके बीज इंदिरा गांधी के शासनकाल में दिखाई देते हैं, जब इमरजेंसी पूर्व ही उन्होंने साहित्य और संस्कृति का मसला वामपंथियों को सौंप दिया. इंदिरा गांधी की यह एक सोची-समझी रणनीति थी, जिसके वामपंथी शिकार हुए और इसकी एवज में वे इंदिरा गांधी का समर्थन करते रहे. अब वक्त आ गया है कि लेखक समुदाय, खासकर हिंदी के लेखकों को साहस के साथ सच बोलना चाहिए, वह भी समग्रता में, क्योंकि चुनिंदा सत्य ने लेखकों से समाज का भरोसा कम कर दिया है. चुनौती उसी भरोसे को वापस लाने की है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

स्मृति शेष

आम जन के कवि थे सनकी

महेंद्र अवधेश

आम लिखो न खास लिखो,
फूस लिखो न घास लिखो,
और न कोई इतिहास लिखो,
सारा देश खा गए नेता, उनका सत्यानाश लिखो.

****

बात जब छिड़ती आमों की, दशहरी याद आती है,
मिली ससुराल में थी, वह मसहरी याद आती है.

कवि सम्मेलन उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, फैजाबाद, इलाहाबाद में हो या देश के किसी कोने में, मंच पर यदि श्रीनारायण अग्निहोत्री उर्फ़ सनकी मौजूद हों, तो हास्य के रसिक श्रोताओं की ओर से उक्त रचनाओं की मांग उठना लगभग तय माना जाता था. वह कविता पढ़ें, इससे पहले यानी उनके खड़े होते ही ठहाके बरबस गूंजने लगते थे. बीते चार अप्रैल को अवधी भाषा के प्रसिद्ध हास्य-व्यंग्य रचनाकार श्रीनारायण अग्निहोत्री उर्फ़ सनकी का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. कानपुर के नर्वल गांव में आठ मार्च, 1933 को जन्मे सनकी ने शुरुआती शिक्षा हासिल करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में परास्नातक किया. इसके बाद वह लखनऊ के चौक स्थित काली चरण इंटर कॉलेज में अध्यापक हो गए, जहां से 1993 में सेवानिवृत्त हुए.

सनकी न केवल आम जनता के कवि थे, बल्कि वह कवियों के बीच भी खासे लोकप्रिय थे. उनके सरल स्वभाव के सब कायल थे. हास्य कवि अशोक झंझटी के मुताबिक, कवि सम्मेलन जहां होता था, सनकी वहां का सूर्य नहीं देखते थे. कविता पढ़ने के बाद वह अपनी मंडली के साथ वहां से निकल लेते थे, चाहे साधन मिले या न मिले. उनके झोले में बिस्किट, किशमिश, काजू आदि हमेशा रहते थे, जो वह हम लोगों में बांटा करते थे. बकौल अशोक, सनकी देश के निर्विरोध कवि थे. हास्य कवि सर्वेश अस्थाना के शब्दों में, सनकी जी कवि सम्मेलन में जाने का पैसा नहीं मांगते थे. आयोजक जो कुछ दे देते थे, उसे वह खुशी के साथ रख लेते थे. सनकी कहते थे कि वह पैसा मांगकर कविता को छोटा नहीं करना चाहते.

हास्य कवि राजेंद्र पंडित कहते हैं कि रमई काका और वंशीधर शुक्ल के बाद अवधी हास्य व्यंग्य की पताका सनकी के हाथों में थी. पूरी गंभीरता के साथ हास्य लिखने वाले सनकी जिस मंच पर प्रस्तुति देते थे, वह उन्हीं के नाम से जाना जाता था. हास्य लेखन में उन्होंने नए-नए प्रयोग किए. पारंपरिक शैली के अलावा उन्होंने ग़ज़ल, लोकगीत और अतुकांत कविताओं में भी अद्भुत हास्य प्रस्तुत किया. जीवन के अंतिम समय में सनकी जी आर्थिक तंगी के शिकार रहे. पिछले काफी दिनों से वह अस्वस्थ थे. अपनी रचनाओं के ज़रिये पूरी ज़िंदगी जन-सामान्य को गुदगुदाने वाले सनकी जी ने क़रीब दस वर्ष पूर्व लखनऊ स्थित केजीएमयू को अपना शरीर दान कर दिया था. उनकी कुल तीन पुस्तकें प्रकाशित हुईं-सनक, आओ बच्चों, ठिठोली. बकौल वरिष्ठ कवि सूर्य कुमार पांडेय, रमई काका ने अवधी में जो हास्य लिखा, वह अतुलनीय है. लेकिन, उनके बाद जिनका नाम लिया जा सकता है, वह थे सनकी. दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने बड़े जनकवि को जो पहचान मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली. ■

mahendra.awdhesh@gmail.com

ससुराल की होली

शादी के बाद परी होली,
ससुरारी से पाती आई.
पहिली होली ससुरारी की,
लिखि भेजेन सब भौजाई.

होली जब निकचॉय लागि,
बढ़िया कपड़ा हम बनुवावा.
होली मा अईबे ज़रूर,
ससुरारि ख़बर या पहुंचावा.

सैकरन रूपैया खर्च कीन,
बनुवावा केतनिव शर्ट-पैंट.
दाढ़ी का करिकै सफाचट्ट,
बारन मा खुशबूदार सैंट.

जब ससुरारी पहुंचेन भाई,
सब दऊरि परीं सरहज-सारी.
जीजा-जीजा कहि टूटि परीं,
बरसावैं लागीं पिचकारी.

बारन मा माटी भरि दीन्हेन,
मुंह मा दीन्हेन कालिख लगाय.
सब दुर्गति हमरी कइ डारेन,
लखुवा बानर दीन्हेन बनाय.

भै कपड़न कै छीछालेदर,
घर फूंकि तमासा कई डारा.
बुरा न मानौ होरी है,
समुझावै लाग बड़ा सारा.

केतनेव नाखून लगे मुंह मा,
साली की हंसी-ठिठोली से.
अब कबौं न अईबे ससुरारी,
भरि पावा अईसी होली से.

हम तो धोखा अब खाय गयेन,
मुलु तुम भाई हुशियार रहेव.
हमरी अस दुर्गति होइ जईहै,
जो फागुन मा ससुरारि गयेव.

-श्रीनारायण अग्निहोत्री (सनकी)

स्वयं शिक्षण प्रयोग एक ग़ैर सरकारी संगठन है, जो ग्रामीण विकास को समर्पित है और समाज के पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है. साथ ही प्राकृतिक आपदाओं एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करता है.

स्मार्टफोन बनेगा माउस

श्याम सुन्दर प्रसाद

आप अपने कम्प्यूटर या लैपटॉप में Wireless Mouse का आनंद लेना चाहते हैं या आप बैठे–बैठे कम्प्यूटर या लैपटॉप पर मूवी या किसी अन्य प्रोग्राग जैसे गाने या धारावाहिक का आनंद ले रहे हों और आपको किसी कारण प्रोग्राम को बंद करना पड़े, चाहे आवाज कम या ज्यादा करना हो या आप कम्प्यूटर को बन्द करना चाहते हैं, तो किसी को आवाज देते हैं कि वह आकार बंद कर दें या आपको खुद उठकर बंद करने के लिए जाना पड़ता है. लेकिन अब आपको उठने या किसी और को आवाज लगाने की जरूरत नहीं है. अब आप अपनी जगह पर रहकर भी वायरलेस माउस का प्रयोग कर कम्प्यूटर या लैपटॉप बंद कर सकते हैं. अगर आपके पास वायरलेस माउस नहीं है तो आप अपने स्मार्टफोन को बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के वायरलेस माउस बनाकर अपना काम आसानी से कर सकते हैं.

स्मार्टफोन को बनाए वायरसेल माउस

आप अपने स्मार्टफोन को वायरलेस माउस में बदलने के लिए अपने कम्प्यूटर और एंड्रॉयड फोन में Android Mouse andKeyboard Apps (Andro-Mouse 3.0) डाउनलोड करें. यह एप्स एंड्रॉयड फोन के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कम्प्यूटर के लिए (Andromouse Desktop Server 3.0)आप एंड्रॉयड माउस के ऑफिशियल वेबसाइट (http://www.andromouse.com/) से डाउनलोड कर सकते हैं. कम्प्यूटर में जब आप Android Mouse and Keyboard Apps इनस्टॉल करेंगे तो यहां आपको आईपी एड्रेस दिखाई देगा, यह सभी कम्प्यूटर में यूनिक होता है इसे आप नोट कर लें. अब अपने एंड्रॉयड फोन में इस एप्स को इनस्टॉल करें. जब आप ऐप्प इनस्टॉल करके उसे खोलेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन वाई–फाई और ब्लूटुथ आयेगा, यहां आप वाई–फाई को सेलेक्ट कर अपने कम्प्यूटर से प्राप्त किए गए आईपी एड्रेस को भर कर मोबाइल एप्प से कनेक्ट कर दीजिए. अब आपका स्मार्टफोन(एंड्रायड) बन गया बिल्कुल मुफ्त वायरलेस माउस.

एंड्रॉयड फोन को बनाएं वाई–फाई राउटर

वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो शहरों में लगभग सभी घरों में इंटरनेट कनेक्शन के लिए राउटर या वाई–फाई लगे होते हैं. अगर आपका एंड्रॉयड फोन एक वाई–फाई हॉट स्पॉट/राउटर का काम करे और आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन वाई–फाई राउटर में बदल लेते हैं, तो आप बहुत आसानी से अपने फोन के डाटा का इस्तेमाल कर आप अपने घर या ऑफिस में मौजूद सभी वाई–फाई डिवाइस, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप आदि चला सकते हैं और साथ ही आप चाहें तो अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों या करीबियों के साथ भी अपने इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं. स्मार्टफोन को राउटर या वाई–फाई बनाकर आप अतिरिक्त खर्चे से बच सकते हैं.

कैसे बनाएं राउटर

सबसे पहले आप अपने एंड्रॉयड फोन के मेन्यू बटन पर क्लिक करें और सेटिंग्स में जाएं. उसके बाद वायरलेस एंड नेटवर्क मेन्यू में जाकर टेथरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट को सेलेक्ट करें (सैमसंग/माइक्रोमैक्स/शियोमी मोबाइल में मोर ऑप्शन पर क्लिक करें. उसके बाद (उसके अंदर ये ऑप्शन मिलेगा) टेथरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट ऑप्शन को क्लिक कर उसके अंदर जाकर हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग सेटिंग/सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट

आप ब्लूटुथ से आसानी से अपने कांटेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जब आपका फोन सही हो, लेकिन अगर आपका फोन टूट जाता है या खराब हो जाता है तो इस स्थिति में यह काम बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिये जरूरी है कि अपने कांटेक्ट लिस्ट को ऐसी जगह सेव रखें जहां से किसी भी समय आप आसानी से उसका बैकअप ले सकें.

सेटिंग को खोलकर आप यहां पर Network SSID में कोई नाम लिखिए (उदाहरण चौथी)तथा Security ऑप्शन में WP2 PSK ऑप्शन को सेलेक्ट करें. उसके बाद पासवर्ड के ऑप्शन में कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड टाइप करें और सेटिंग्स को सेव कर दीजिए और टेथरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट ऑप्शन से बाहर आकर आप अपने वाई–फाई हॉटस्पॉट को ऑन कर दीजिये. ऑन करने के बाद आपका अपना प्राइवेट वाई–फाई तैयार हो जाएगा. अब आपको जिस–जिस डिवाइस में वाई–फाई के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करना हो उसके वाई–फाई ऑप्शन में जाकर Network SSID में जो नाम दिया हो(चौथी) वो सर्च करें और वही पासवर्ड के माध्यम से कनेक्ट करें जो आपने सेटिंग के समय उस डिवाइस में समिट किया था. आप चाहे तो बिना पासवर्ड के भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिसको आप यह सुविधा नहीं देना चाहते हैं, वे भी बिना पासवर्ड के आपके वाई–फाई का प्रयोग कर सकतें हैं. इसलिए पासवर्ड के प्रयोग से आपके डाटा की सिक्योरिटी बनी रहती है और आपका वाई–फाई वही लोग इस्तेमाल कर पाएंगे जिनको आपके पासवर्ड की जानकारी होगी. इस तरह से आप अपने मोबाइल फोन के डाटा को शेयर करके अपने करीबी लोगों के खर्च में कुछ कमी कर सकते हैं.

कैसे कांटेक्ट बैकअप ई–मेल पर सेव करें

आपके मोबाइल फोन में मौजूद लगभग सभी कंटेंट जैसे फोटो, वीडियो, ऑडियो, डाक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं. लेकिन इन सब में आपका कांटेक्ट लिस्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, अगर यह आपके फ़ोन से गायब हो जाये तो आपको फिर से सभी को दोबारा हासिल करने में कठिनाई होगी और हो सकता है कि कई सारे कांटेक्ट नंबर मिल भी न पाएं. अगर आप नया मोबाइल फोन लेते हैं तो पूराने मोबाइल से नए मोबाइल कांटेक्ट नंबर ट्रांसफर करने में सबसे ज्यादा कठिनाई होती है. आप ब्लूटुथ से आसानी से अपने कांटेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जब आपका फोन सही हो, लेकिन अगर आपका फोन टूट जाता है या खराब हो जाता है तो इस स्थिति में यह काम बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिये जरूरी है कि अपने कांटेक्ट लिस्ट को ऐसी जगह सेव रखें जहां से किसी भी समय आप आसानी से उसका बैकअप ले सकें. उसके लिए सबसे सही जगह है आपकी ई–मेल आईडी, ई–मेल ही एक ऐसी जगह है जहाँ फोन कांटेक्ट लिस्ट को सेव करने पर उसका बैकअप आसानी से कहीं भी कभी भी लिया जा सकता है.

उसके लिए आप अपने फ़ोन के कांटेक्ट लिस्ट में जाएं. उसके बाद ऑप्शन बटन को दबाएं वहां आपको इम्पोर्ट/ एक्सपोर्ट कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा और उसको क्लिक करें. अब कॉपी कांन्टेक्ट्स फ्रॉम में उस जगह को चुनिए जहां आपके मौजूदा कॉन्टेक्ट्स सेव हैं, अब नेक्स्ट ऑप्शन को चुनें, अब आपको आपकी ई–मेल आईडी, व अन्य ऑप्शन फ़ोन में, मेमोरी में या सिम में बैकअप लेने के लिए दिखाई देंगे, आप इसमें से अपनी ई–मेल एड्रेस को सेलेक्ट कीजिये और नेक्स्ट कीजिये फिर अपने फोन के सभी कांन्टेक्ट्स को सेलेक्ट ऑल कर सेलेक्ट कीजिये. उसके बाद नेक्स्ट बटन को टच कीजिये, आपके फोन के सभी कनटैक्ट्स का बैकअप आपकी ई–मेल आईडी पर सेव हो जायेगा, इसी तरह आप नये कॉन्टेक्ट्स को भी अपने ईमेल पर सेव कर सकते हैं, उसके लिए आप ऐड टू कॉन्टेक्ट्स करते समय अपनी ई–मेल आईडी को सलेक्ट करें. ■

feedback@chauthiduniya.com

यामाहा की सुपरबाइक

यामाहा ने भारत में अपनी दो नई सुपरबाइक YZF- R1 और R1M लॉन्च कर दी है. यामहा की वाईजेडएफ–आर1(YZF- R1) ब्लू–सफेद मेटैलिक रंग में उपलब्ध है. कंपनी ने इस मॉडल की कीमत 29 लाख 43 हजार रुपये रखी है. वहीं आर1एम (R1M) दो रंगों में उपलब्ध है. कंपनी ने इस मॉडल की कीमत 22 लाख 34 हजार रुपये रखी है. दोनों ही बाइक ऑर्डर पर उपलब्ध होंगे. वाईजेडएफ–आर1 और आर1एमकी हाई टेक आर्म्ड प्योर सपोर्ट के कॉन्सेप्ट पर तैयार की गईं हैं. इन दोनों ही बाइक में 998सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन, 4 स्ट्रोक, इन लाइन फोर सिलिंडर, 4– वॉल्व इंजन के साथ 200बीएचपी का इंजन लगा है. साथ ही इन सुपरबाइक्स में टैक्शन कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और ड्वइड जैसे फीचर्स भी शामिल हैं. ■

कंपनी ने इस मॉडल की कीमत 22 लाख 34 हजार रुपये रखी है. दोनों ही बाइक ऑर्डर पर उपलब्ध होंगे. वाईजेडएफ–आर1 और आर1एमकी हाई टेक आर्म्ड प्योर सपोर्ट के कॉन्सेप्ट पर तैयार की गईं हैं. इन दोनों ही बाइक में 998सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन, 4 स्ट्रोक, इन लाइन फोर सिलिंडर, 4– वॉल्व इंजन के साथ 200बीएचपी का इंजन लगा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

ग्रामीण विकास की गाथा लिख रही हैं सखी

चौथी दुनिया ब्यूरो

यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) और स्वयं शिक्षण प्रयोग (एसएसपी) के संयुक्त तत्वावधान में पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में महिला उद्यमियों की अहम भूमिका विषयक इस कार्यक्रम में नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की संयुक्त सचिव वर्षा जोशी, यूएसएआईडी के मिशन डायरेक्टर जॉन बीड, स्वयं शिक्षण प्रयोग की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेमा गोपालन एवं कीनिया में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की अध्यक्ष वंजीरा मथाई ने अपने विचार व्यक्त किए.

अपने संबोधन में प्रेमा गोपालन ने कहा कि स्वयं शिक्षण प्रयोग पिछले 20 वर्षों से महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाक़ों में महिलाओं को स्व–रोज़गार के प्रति जागरूक कर रहा है. इसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है. जॉन बीड के मुताबिक़, भारत की एक बड़ी आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है. गांवों के विकास में स्वयं शिक्षण प्रयोग से जुड़ी महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं. स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता न सिर्फ़ पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए भी यह बेहद ज़रूरी है. अफ़्रीकी देश कीनिया में ग्रीन बेल्ट से जुड़ी वंजीरा मथाई ने कहा कि अफ़्रीका के देशों में ग़रीबी काफ़ी ज़्यादा है. अन्य देशों की तुलना में वहां लोगों का जीवन स्तर निम्न है. खाना पकाने के लिए अफ़्रीकी देशों में लकड़ियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, जिससे वहां जंगलों के विस्तार में कमी आ रही है. नतीज़तन, वातावरण पर इसका प्रतिकूल असर हो रहा है. अफ़्रीकी देशों में स्वच्छ ऊर्जा की बेहद आवश्यकता है. उनके मुताबिक, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट इस दिशा में सार्थक पहल कर रहा है.

स्वयं शिक्षण प्रयोग एक ग़ैर सरकारी संगठन है, जो ग्रामीण विकास को समर्पित है और समाज के पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है. साथ ही प्राकृतिक आपदाओं एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करता है. वर्ष 2006 में स्थापित सखी यूनिक रूरल इंटरप्राइस के माध्यम से स्वयं शिक्षण प्रयोग ग्रामीण महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और बिहार में महिलाओं को स्व–शिक्षण प्रयोग द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है. यहां महिलाओं को एक कामयाब उद्यमी बनाने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यापारिक सहयोग प्रदान किया जाता है. इन महिलाओं को व्यापारिक नेटवर्क के विषय में बताया जाता है, ताकि वे आर्थिक रूप से सबल हो सकें. स्वयं शिक्षण प्रयोग ने एक ग्रामीण मार्केटिंग और वितरण कंपनी को भी प्रोत्साहित किया है, जिसे वर्ष 2006 में स्थापित किया गया था. लाभ–हानि रहित इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वर्ष 2009 में पंजीकृत किया गया. आज यह उन कंपनियों के लिए एक व्यापारिक सहयोगी के रूप में कार्य कर रही है, जो ग्रामीण व्यापार में प्रवेश करना चाहती हैं और सखी नेटवर्क के साथ अपने उत्पादों को घर–घर पहुंचाना चाहती हैं.

कार्यक्रम के दूसरे सत्र में महिला सशक्तीकरण और पर्यावरण संरक्षण समेत कई मुद्दों पर गंभीर विचार–विमर्श किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अपूर्वा चतुर्वेदी, स्वच्छ ऊर्जा विशेषज्ञ (यूएसएआईडी इंडिया), प्रेमा गोपालन, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एसएसपी, मणि खुराना, वर्ल्ड बैंक, आशीष कुमार साहू, सीईओ (क्लीन एनर्जी एक्सेस नेटवर्क), अजेयता शाह, संस्थापक एवं सीईओ, फ्रंटियर मार्केट्स, अविक रॉय, संस्थापक, री–इमरजिंग वर्ल्ड, सोमा दत्ता,

कार्यक्रम समन्वयक, इनर्जिया और उपमन्यु पाटिल, डायरेक्टर, सखी यूनिक रूरल इंटरप्राइस समेत कई गणमान्य लोगों ने अपने अनुभव साझा किए.

सखी यूनिक रूरल इंटरप्राइस के डायरेक्टर उपमन्यु पाटिल ने चौथी दुनिया को बताया कि प्राकृतिक आपदाओं का सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है. विपत्ति की मारी ऐसी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद कर रही है स्वयं शिक्षण प्रयोग नामक यह संस्था. महाराष्ट्र के लातूर में वर्ष 1993 में भूकंप आया था. उन दिनों वहां चारों तरफ़ तबाही का आलम था. लोगों के बीच सरकार को लेकर काफ़ी गुस्सा था. इसलिए हमारे लिए वहां काम करना किसी चुनौती से कम नहीं था. लातूर में हमारी संस्था ने यह महसूस किया कि वहां लोगों को मदद की ज़रूरत तो थी, लेकिन वे उसी पर आश्रित नहीं थे. कुछ ऐसा ही अनुभव भुज और सुनामी से तबाह हुए तमिलनाडु में भी देखने को मिला. पाटिल ने बताया कि स्वयं शिक्षण प्रयोग पिछले 20 वर्षों से काम कर रही है. इस संस्था से जुड़े क़रीब 70 हज़ार घरों की आय में 33 फ़ीसद का इजाफ़ा हुआ है. सखी (महिला उद्यमी) 1,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक कमा रही हैं. अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने, आग तापने, रोशनी, कृषि और कारोबार के लिए स्वच्छ ऊर्जा का सीमित उपयोग होता है. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़कर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों को बेचने के लिए उत्सुक हैं. ■

कौन होगा फ्लेचर का उत्तराधिकारी

टीम इंडिया को कोच इस बार देशी होगा या विदेशी इस पर सबसे ज्यादा अटकलें लग रही हैं. क्योंकि साल 2001 में जॉन राइट के भारतीय टीम का कोच बनने के बाद फ्लेचर तक टीम इंडिया के सभी कोच विदेशी ही रहे हैं. ग्रैग चैपल के कार्यकाल को छोड़ दें तो बाकी सभी कोचों का कार्यकाल बेहद सफल रहा है. जान राइट के कोच रहते टीम इंडिया विश्व कप के फाइनल में पहुंची. गुरु गैरी ने 2011 में टीम इंडिया को विश्व विजेता बना दिया. डंकन टीम इंडिया को विश्व कप के सेमी-फाइनल तक पहुंचाने में सफल रहे. राइट के बाद ग्रैग चैपल, गैरी क्रिस्टन और डंकन फ्लेचर विदेशी कोचों की इस कड़ी का हिस्सा हैं. यह देखने वाली बात होगी कि यह चेन आगे बढ़ेगी या इस पर विराम लग जायेगा. हांलांकि, इस बार देशी कोच चुने जाने की संभावना सबसे ज्यादा है. कोच बनने देशी दावेदारों में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के अलावा संजय बांगड़, रॉबिन सिंह और प्रवीण आमरे जैसे खिलाड़ियों के नाम सबसे आगे हैं.

धर्मेंद्र कुमार सिंह

आईसीसी विश्व कप-2015 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमी फाइनल मुकाबले में हार के साथ ही डंकन फ्लेचर का भारत के कोच के रुप में चार साल लंबा सफर खत्म हो गया. विश्व कप खिताब न बचा पाने के बाद, न ही बीसीसीआई फ्लेचर का कार्यकाल बढ़ाना चाहता था और डंकन ने भी कांट्रेक्ट को आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं जताई. साल 2011 में भारत को विश्व चैंपियन बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले गैरी क्रिस्टन ने पारिवारिक कारणों की वजह से टीम इंडिया का कोच बने रहने से इंकार कर दिया था. इसके बाद बीसीसीआई ने गुरू गैरी की अनुशंसा पर ही जिंबाब्वे के पूर्व कप्तान डंकन फ्लेचर को टीम इंडिया का कोच नियुक्त किया था. हांलाकि, तब टीम इंडिया का कोच बनने की दौड़ में पूर्व कीवी कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग और जिंबाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर भी शामिल थे.

नए कोच के चयन को लेकर बीसीसीआई में एक बार फिर गहमा-गहमी बढ़ गई है. कोच के चयन को लेकर बीसीसीआई की नवगठित वर्किंग कमेटी की 26 अप्रैल को कोलकाता में बैठक होने जा रही है. यह जगमोहन डालमिया के अध्यक्ष चुने जाने के बाद बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की पहली मीटिंग भी है. संभावना है कि इस बैठक में नए कोच के चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में गहन चर्चा होगी. विश्व कप के बाद भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय दौरा जून में बांग्लादेश का है. इसलिए बोर्ड के पास कोच के चयन के लिए पर्याप्त वक्त है. फिलहाल भारतीय टीम की कोचिंग की कमान डायरेक्टर रवि शास्त्री, सहायक कोच के संजय बांगर, भरत अरुण और आर श्रीधर की तिगड़ी के हाथों में रहेगी. ऐसे में नए कोच की नियुक्ति तक प्रवीण आमरे को बैटिंग कोच बनाए जाने की संभावना नज़र आ रही है.

इस बार कोच देशी होगा या विदेशी इस पर सबसे ज्यादा अटकलें लग रही हैं. क्योंकि साल 2001 में जॉन राइट के भारतीय टीम का कोच बनने के बाद फ्लेचर तक टीम इंडिया के सभी कोच विदेशी ही रहे हैं. ग्रैग चैपल के कार्यकाल को छोड़ दें तो बाकी सभी कोचों का कार्यकाल बेहद सफल रहा है. जान राइट के कोच रहते टीम इंडिया विश्व कप के फाइनल में पहुंची. गुरु गैरी ने 2011 में टीम इंडिया को विश्व विजेता बना दिया. डंकन टीम इंडिया को विश्व कप के सेमी-फाइनल तक पहुंचाने में सफल रहे. राइट के बाद ग्रैग चैपल, गैरी क्रिस्टन और डंकन फ्लेचर विदेशी कोचों की इस कड़ी का हिस्सा हैं. यह देखने वाली बात होगी कि यह चेन आगे बढ़ेगी या इस पर विराम लग जायेगा. हांलांकि, इस बार देशी कोच चुने जाने की संभावना सबसे ज्यादा है. कोच बनने देशी दावेदारों में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के अलावा संजय बांगड़, रॉबिन सिंह और प्रवीण आमरे जैसे खिलाड़ियों के नाम सबसे आगे हैं. वही विदेशी दावेदारों में न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल हसी के नाम सामने आ रहे हैं. 16 अप्रैल को यह खबर भी आई कि सौरव गांगुली की इस संबंध में जगमोहन डालमिया से गुपचुप बैठक की है. ऐसे में इस बात का आकलन करने की जरूरत है कि फ्लेचर के कार्यकाल में ऐसी कौन सी कमियां रह गईं जिन्हें पूरा करना नए कोच के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी.

नए कोच के सामने सबसे बड़ी चुनौती विदेशी धरती पर टीम इंडिया को टेस्ट मैच जिताने की होगी. इस पद के लिए उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल लोगों में जो इस कमी को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त नज़र आएगा वही टीम इंडिया का चीफ कोच बनने में कामयाब होगा.

नए कोच के सामने सबसे बड़ी चुनौती विदेशी धरती पर टीम इंडिया को टेस्ट मैच जिताने की होगी. इस पद के लिए उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल लोगों में जो इस कमी को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त नज़र आएगा वही टीम इंडिया का चीफ कोच बनने में कामयाब होगा. फ्लेचर के कोच रहते भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दौरों पर मुंह की खानी पड़ी. इंग्लैंड में साल 2011 में 4-0 और साल 2014 में 3-1 के अंतर से हार मिली, वहीं ऑस्ट्रेलिया में साल 2011-12 में 4-0 और 2014-15 में 2-0 के अंतर से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. वहीं न्यूजीलैंड की धरती पर 2013-14 में 1-0 और दक्षिण अफ्रीका में 2013 में 1-0 के अंतर से हार मिली. इस वजह से टीम इंडिया की जमकर आलोचना भी हुई. फ्लेचर की देखरेख में टीम इंडिया ने कुल 38 टेस्ट मैच खेले. इनमें से 13 में जीत हासिल हुई और 17 में टीम को हार का सामना करना पड़ा, जबकि 9 मैच बराबरी पर समाप्त हुए. हाल ही में जारी हुई टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया सातवें पायदान पर पहुंच गई है. दूसरी तरफ वन-डे में टीम इंडिया का प्रदर्शन अच्छा रहा. फ्लेचर के कोच रहते टीम इंडिया ने 106 वन-डे मैच खेल जिनमें से 64 में जीत और 32 में हार हुई जबकि 3 मैच टाई रहे और 7 बेनतीजा समाप्त हुए. साल 2013 में टीम इंडिया ने लगातार आठ वन-डे सीरीज जीतने का अनोखा रिकॉर्ड कायम किया. जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी की जीत भी शामिल थी.

पूर्व कप्तान सौरव गांगुली इस बार भारतीय टीम के कोच बनने की दौड़ में फिलहाल सबसे आगे हैं. दादा टीम इंडिया के विदेशी धरती पर प्रदर्शन को लेकर हमेशा आवाज उठाते रहे हैं. उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने विदेशी धरती पर कई टेस्ट मैच जीते थे. सबसे अहम बात यह है कि उन्हें मॉर्डन डे क्रिकेट की अच्छी समझ है. जिस आक्रामक अंदाज में उन्होंने कप्तान रहते टीम की चाल, चरित्र और चेहरा बदल दिया था. उसे तरह के आक्रामक रुख वाले कोच की टीम इंडिया को जरूरत है. लेकिन दादा का बहुत ज्यादा आक्रामक होना और कोचिंग देने का अनुभव न होना उनकी राह का रोड़ा बन सकता है. विश्व की तकरीबन सभी टीमों के साथ ऐसे कोच जुड़े हैं जिन्हें कोचिंग देने का पुराना अनुभव है. ऐसे में उनके नाम पर एकतरफा राय बन पाना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है.

मिस्टर परफेक्शनिस्ट के रूप में विख्यात राहुल द्रविड़ का नाम भी टीम इंडिया के नए कोच के रूप में सामने आ रहा है. फिलहाल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स टीम के कोच और मेंटोर की भूमिका निभा रहे हैं. युवा खिलाड़ियों से सजी इस टीम के प्रदर्शन में द्रविड़ की देखरेख में बहुत सुधार आया है. आईपीएल के वर्तमान सीजन में उनका शुरूआती प्रदर्शन भी बेहतरीन है. जगमोहन डालमिया इस बात के संकेत दिये हैं कि इस बार टीम का कोच कोई भारतीय ही होगा. ऐसे में सौरव गांगुली का भी बंगाल से होना फायदेमंद साबित हो सकता है. राहुल द्रविड़ की तुलना में सौरव का पलड़ा इसलिए भारी दिखाई पड़ रहा है क्योंकि सौरव की पहचान एक आक्रामक कप्तान की रही है. वहीं राहुल एक शांत मिजाज के खिलाड़ी और कप्तान रहे हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग का नाम टीम के नए कोच के रूप में इस बार भी आ सकता है. फ्लेमिंग धोनी की पसंद हो सकते हैं, क्योंकि सीएसके में बतौर कप्तान धोनी फ्लेमिंग के साथ छह साल से काम कर रहे हैं. सीएसके का प्रदर्शन भी उनके कोच रहते स्थिर रहा है. इसके अलावा फ्लेमिंग बिग बैश में मेलबर्न स्टार टीम के भी कोच हैं. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइक हसी भी कोच के रूप में चयनकर्ताओं की पसंद हो सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दौरान बात आई थी, कि धोनी ने हसी की बतौर कोच न्युक्ति करने की अनुशंसा की थी. इसके जवाब में हसी ने कहा था कि मुझे खुद को भी नहीं मालूम है कि मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूं या नहीं, फिलहाल वह क्रिकेट खेल रहे हैं और उनका कोच बनने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है.

टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच और किंग्स इलेवन पंजाब के कोच संजय बांगर की हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल जॉनसन ने बहुत तारीफ की है. उन्होंने कहा कि बांगर भारतीय टीम के सहायक कोच की भूमिका बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं ऐसे में वह टीम इंडिया का मुख्य कोच बनने के प्रमुख उम्मीदवार हैं.

भारतीय टीम के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी रॉबिन सिंह भी टीम इंडिया के कोच बनने की दौड़ में शामिल हैं. रॉबिन के पास कोचिंग का लंबा अनुभव है वह साल 2007 से 2009 तक बौतर फील्डिंग कोच टीम इंडिया के साथ जुड़े रहे थे. फिलहाल वह मुंबई इंडियन के कोच के रुप में कार्यरत हैं. रॉबिन सिंह हांगकांग की राष्ट्रीय टीम, इंडिया-ए, डेक्कन चार्जर्स और अमेरिका की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम के कोच की भूमिका निभा चुके हैं. उनका कोचिंग का लंबा अनुभव उनके बहुत काम आएगा. दूसरी तरफ वह बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं. खिलाड़ी से लेकर कोचिंग करियर तक वह कभी किसी विवाद में नहीं पड़े. ऐसे में साफ सुथरी छवि के रॉबिन भारतीय टीम के कोच बनने के सशक्त उम्मीदवार हैं, लेकिन करियर में केवल एक टेस्ट मैच खेलने का अनुभव निश्चित तौर पर उनकी राह की सबसे बड़ी परेशानी साबित होगा.

कई बार विश्व के कई बेहतरीन खिलाड़ी कई टीमों के कोच बने हैं लेकिन व कोच के रूप में वे उतने सफल नहीं हुए जितना वे बतौर खिलाड़ी सफल रहे थे. एक सफल कोच होना, सफल खिलाड़ी होने से बहुत अलग है. इसके लिए अलग क्लालिटी(गुणों) की आवश्यक्ता होती है. एक सफल खिलाड़ी, एक सफल कोच साबित हो, ऐसा सुनिश्चित नहीं है. एक असफल खिलाड़ी भी एक सफल कोच साबित हो सकता है. उदाहरण के लिए कपिल देव, जावेद मियादाद और ग्रैग चैपल ऐसे कुछ नाम हैं जो बतौर खिलाड़ी तो बेहद सफल थे लेकिन कोच की भूमिका में तीनों असफल रहे. वहीं दूसरी तरफ डेव व्हाटमोर, बॉब वूलमर जैसे अन्य कई की पहचान महान खिलाड़ियों की नहीं रही, बावजूद इसके उन्होंने खुद को एक बेहतरीन कोच साबित किया. किसी खिलाड़ी को कोच नियुक्त करते समय उसका आकलन केवल और केवल बतौर खिलाड़ी उसकी सफलताओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, उसके अपने दौर के खिलाड़ियों खासकर टीम मेट्स के साथ ड्रेसिंग रूम में संबंधों की कसौटी पर भी कसा जाना चाहिए. जिससे टीम में किसी तरह की कोई दरार न पैदा हो. और किसी भी परिस्थिति में टीम एक जुट रहे. क्रिकेट एक जटिल खेल है जिसमें कई फैक्टर अहम होते हैं. प्राथमिक रूप में यह एक टीम गेम है. इससे अलग व्यापक पैमाने पर एक कोच की सफलता खिलाड़ियों की व्यक्तिगत गुणवत्ता और प्रतिभा पर निर्भर करती है. जिससे टीम का निर्माण होता है. कोच टीम के खेल के स्तर में सुधार लाता है. कोच एक दिन या एक महीने में कोई चमत्कार करके टीम की काया नहीं पलट सकता है. आम तौर पर कप्तान के बारें में कहा जाता है कि वह तभी अच्छा कप्तान साबित हो सकता है जब उसकी टीम अच्छी हो. लेकिन एक अच्छा कोच वह होता है जो एक औसत खिलाड़ी को बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में रूपांतरित कर सके. कोच टीम को मैच नहीं जिता सकता, क्योंकि वह मैदान में उतरकर न तो बल्लेबाजी करता है और न ही गेंदबाजी. इसलिए उसमें रणनीतिक कुशलता और मैन-मैनेजमेंट जैसे गुणों आवश्यक रूप से होने चाहिए. एक कोच खिलाड़ियों के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. यदि कोच की खेल की तकनीकि समझ बेहतर है तो उसे खिलाड़ियों की कमजोरियों को समझने में देर नहीं लगती है. उनकी कमियों को दूर कर उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाने में कोच महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. एक कोच के खिलाड़ियों के साथ मित्रवत संबंध होने चाहिए जिससे कि खिलाड़ी खुलकर अपनी बात उनके सामने रख सकें.

नियमों के मुताबिक खिलाड़ियों को कोच के पद के लिए आवेदन करना होगा. ऐसे में कई सवाल हैं यदि सौरव या राहुल जैसा कोई टीम का नया कोच बनता है तो डायरेक्टर रवि शास्त्री की क्या भूमिका होगी. क्या टेस्ट कप्तान विराट कोहली और एकदिवसीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की राय कोच की नियुक्ति के लिए ली जायेगी और क्या ऐसे में ये दोनों द्रविड़ या गांगुली को टीम का कोच बनाने के हक में होंगे. खासकर धोनी की जिनकी कप्तानी में सौरव और राहुल दोनों ही खेल चुके हैं. ये देखने वाली बात होगी.■

feedback@chauthiduniya.com

शानदार सलीम खान के बेटे हैं सलमान खान

मनीष कुमार

सलीम ख़ान रोज अपने घर पर डॉक्टरों के साथ बैठते हैं. उनके पास 6-7 डॉक्टरों की एक टीम है. हर दिन उनके साथ कम से कम दो डॉक्टर होते हैं. सलीम खान इन डॉक्टरों के साथ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है. उनके यहां ऐसे लोग आते हैं जिनके परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती होता है. ये लोग सलीम खान के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं. डॉक्टरों की टीम अस्पताल द्वारा दिए गए कागजों को पढ़ती है और अस्पताल में फोन कर बीमारी के बारे में जानकारी लेती है. इलाज में कितने पैसे खर्च होंगे और और कब तक इलाज चलेगा इसकी तसल्ली होने के बाद इलाज में लगने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा या फिर कभी-कभी पूरी की पूरी रकम का चेक बनाकर फौरन जरूरतमंद हाथ में दे देते हैं. चेक हमेशा अस्पताल के नाम से दिया जाता है. सलीम खान ये काम रोज करते हैं. लेकिन, गुरुवार को वह ज्यादा समय के लिए बैठते हैं. हर दिन यही होता है. लोग अपनी परेशानियां बताते रहते हैं और सलीम खान चेक बांटते रहते हैं.

ऐसे शानदार पिता के बेटे हैं सलमान खान. पिता की तरह सलमान भी लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं वह भी बिना किसी स्वार्थ के. बॉलीवुड में यदि नये व छोटे कलाकारों या फिल्मी दुनिया में संघर्ष करने वाले नौजवानों को मदद करने वालों की यदि कोई लिस्ट बनाई जाए तो सलमान खान का नाम उसमें सबसे ऊपर आएगा. असलियत तो यह है कि अब तक बॉलीवुड में जितने भी सुपर स्टार हुए हैं उनमें नए लोगों को मौका देने और उनकी मदद करने वालों में सलमान खान जैसा कोई है ही नहीं. सलमान की इस खासियत से बॉलीवुड का हर शख्स अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन लोगों के सामने सलमान की ये खूबियां नहीं आई हैं. कई हीरो और हीरोइनों के अलावा हिमेश रेशमिया, संजय लीला भंसाली, साजिद-वाजिद जैसे कई लोगों को पहचान दिलाने में सलमान का अहम योगदान रहा है. गोविंदा जैसे स्टार को फिल्म इंडस्ट्री ने भुला ही दिया था, उन्हें फिल्म पार्टनर में मौका देकर उनकी सक्सेस फुल वापसी सलमान खान ने ही करवाई. आज के ज़माने में ऐसा कौन करता है? इसके अलावा, सलमान बिइंग ह्यूमन नाम की एक फाउंडेशन चलाते हैं, जिसके जरिए वह गरीबों, बच्चों और खासकर फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की मदद करते हैं. गरीबों की आर्थिक मदद करने के अलावा वह गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत खर्च करते हैं. फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के बीच वह अक्सर कंबल वैगरह बंटवाते हैं. समाजसेवा का ये काम सलमान बहुत ही गुपचुप तरीके से करते हैं. वह ऐसे कामों को कभी मीडिया की सुर्खियां नहीं बनने देते और न ही सोशल मीडिया में इसका ढिंढोरा पीटते हैं.

> सलमान खान की शख्सियत भी अजीबो-गरीब है. सबकी मदद करने वाला शख्स हमेशा गलत वजहों से मीडिया की सुर्खियों नजर आता है. फिल्मी दुनिया के लोगों से सलमान के बारे में पूछा जाये तो शायद ही कोई मिले जो उनकी शिकायत करे. हर शख्स यही कहता है कि वह तो मुसीबत में घिरे लोगों के लिए एक मसीहा हैं.

मुंबई फिल्म-जगत में ऐसा कोई नहीं है जिसने सलमान से मदद मांगी हो और उन्होंने उनकी मदद न की हो. सलमान एक जिंदादिल इंसान होने के साथ-साथ एक दयावान व्यक्ति हैं. वह हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं. ये बात और है कई लोग इसे सलमान की कमजोरी मानते हैं. बॉलीवुड में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सलमान से नजदीकियां बढ़ाईं, उनके नाम का इस्तेमाल किया, सफलता हासिल की और दूसरे रास्ते निकल पड़े. सलमान के साथ कई लोगों ने धोखा किया. दोस्त बनकर उनकी पीठ पर खंजर चलाये. लेकिन इतने धोखे खाने के बाद भी सलमान ने अपना रास्ता कभी नहीं बदला. लोगों की मदद करना बंद नहीं किया.

सलमान खान की शख्सियत भी अजीबो-गरीब है. सबकी मदद करने वाला यह शख्स हमेशा गलत वजहों से मीडिया की सुर्खियों में नजर आता है. फिल्मी दुनिया के लोगों से सलमान के बारे में पूछा जाये तो, शायद ही कोई मिले जो उनकी शिकायत करे. हर शख्स यही कहता है कि वह तो मुसीबत में घिरे लोगों के लिए एक मसीहा हैं. दूसरी तरफ एक और सच्चाई जिसे देश की मीडिया ने बनाया है. मीडिया ने कभी भी सलमान के स्टारडम के मुखौटे के पीछे छिपे एक इसांन की खोज नहीं की. उल्टा, सलमान खान को एक अजीबो-गरीब इमेज-ट्रैप में फंसा दिया. खबर बेचने के धंधे में लगे लोगों ने सलमान खान की एक नकारात्मक छवि दुनिया के सामने पेश की है. एक ऐसे व्यक्ति की छवि, जो नशे में गाड़ी चलाता है, पार्टियों में हंगामा और गाली-गलौज करता है आदि, आदि. साल 1998 में सलमान पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा. तब से मीडिया ने सलमान की छवि एक बिगड़ैल व्यक्ति की बना दी. इसके बाद मीडिया ने उनके निजी जीवन में घुसकर ऐसी-ऐसी कहानियां गढ़ीं, जिससे उनकी इमेज और भी बगड़ती चली गई. वो फोन पर गाली-गलौज करने वाले, धमकी देने वाले, सेट पर पहुंचकर उनके साथ धक्का-मुक्की करने वाले सलमान खान बना दिए गए. मीडिया ने सलमान को बॉलीवुड का बैड बॉय तो बना दिया लेकिन ये सलमान की खुशकिस्मती है कि ऐसी छवि होने के बावजूद उनकी फिल्में हमेशा सपुर हिट रहीं. कहने का मतलब यह कि मीडिया की लाख कोशिशों के बावजूद सलमान के प्रति लोगों का प्यार कम नहीं हुआ.

फिलहाल, सलमान खान मुसीबतों से घिरे हुए हैं. एक तरफ साल 2002 के हिट एंड रन केस में फैसला आने वाला है, वहीं दूसरी तरफ काले-हिरण का शिकार करने के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी है. हाई कोर्ट ने सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में चार और गवाहों को पेश करने की अनुमति देने वाले आदेश को बहाल रखा है. ये दोनों ही मामले सलमान के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं. इस दोनों मामलों में मीडिया द्वारा बनाई गई उनकी नकारात्मक छवि का असर साफ दिखता है. एक मामला 17 साल से और दूसरा 13 साल से कोर्ट में चल रहा है. इतने सालों से सलमान मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं. जिसे अगर मापा जा सकता तो उन्हें सजा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती. अधिकतम सजा से ज्यादा वो वैसे ही झेल चुके हैं. लेकिन, कोर्ट को तो अपना काम करना है. कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी हैं और सबूतों के आधार पर न्याय भी देना है. अब हमारा देश ही ऐसा है जहां न्याय पाने में इतना लंबा वक्त लग जाता है तो शिकायत किससे की जाये.

वैसे एक बात तो जरूर समझ में आती है कि अदालत में न्याय की देवी की आंखों पर काली पट्टी बंधी है. वह कोर्ट में दी जाने वाली दलीलों को सुन तो सकती है लेकिन कटघरे में खड़े इंसान के अंदर झांक नहीं सकती. अगर ये पट्टी नहीं होती तो शायद सलमान अब तक आजाद होते. क्योंकि सच तो यह है कि दुनिया ने सलमान को उसी रूप को देखा है जिस रूप में मीडिया ने उन्हें दिखाया उनकी जो छवि बनाई. छवि तो छवि ही है, यह हकीकत से अलग होती है, और हकीकत यह है कि सलमान बॉलीवुड का बैड बॉय नहीं बल्कि अकेला सुपर स्टार है जो सुपर ́ युमन है.■

manishbph244@gmail.com

संघर्ष से बना गीतकार शब्बीर अहमद

इंटरव्यू

कहते हैं मुंबई सपनों का शहर है, यदि आपके इरादे मजबूत हैं और आपमें कुछ कर गुजरने का जुनून है, तो आप यहां अपने सपनों साकार कर सकते हैं. ऐसे में यदि कोई आपके सपनों को परवाज देने वाला मिल जाये तो सोने पे सुहागा है. कुछ ऐसी ही कहानी है युवा गीतकार शब्बीर अहमद की. उनके साथ चौथी दुनिया के संपादक समन्वय मनीष कुमार से हुई बातचीत के मुख्य अंश...

फिलहाल आप कौन-कौन सी फिल्मों के लिए गीत लिख रहे हैं?

अभी काफी फिल्में आ रही हैं. कई अच्छी फिल्मों के लिए के लिए गीत लिख रहा हूं, जैसे सलमान भाई के प्रोडक्शन की और टी सीरीज की ***ऑल इज वेल*** जैसी कई फिल्में हैं.

सबसे पहले अपने किस फिल्म के लिए गीत लिखे?

सबसे पहले सलमान खान ने मुझे ***शादी करके फंस गया*** फिल्म में एक गीत दिलवाया. इसके बाद उन्होंने फिल्म गर्व के लिए मुझे गीत लिखने का मौका दिया. फिर साजिद भाई ने मौका दिया था. मैं सलमान भाई के पास आता-जाता रहता था. साजिद भाई मेरे लिखे गीतों के मुखड़े सुनते थे. हिमेश रेशमिया जी के साथ सलमान भाई के लिए मैंने कई गीत लिखे. उनके साथ कई और गीत आने वाले हैं. मेरे गाने आपने देखे होंगे जैसे ***तुझे अक्सा बीच घुमा दूं आ चलती क्या, तेरी मेरी प्रेम कहानी दो लफ़्ज़ो में बयां न हो पाये, जुम्मे की रात है चुम्मे की बात है, सोणी के नखरे सोणे लगदे, केंदी पो केंदी चेन, या हम तुमको निगाहों में इस तरह बसा लेगें*** जैसे कई हिट गीत मैंने लिखे हैं.

आप मूल रूप से कहां के रहने वाले हैं और आप मुंबई कैसे आये?

मेरी पैदाइश मुंबई के भिवंडी की है लेकिन मेरी मातृभूमि उत्तर प्रदेश का जौनपुर है. हमारा परिवार यहीं रहता था और जब मुंबई में दंगे हुए थे, तब मेरे वालिद और मां के अंदर दहशत बैठ गयी थी. फिर वे हमें लेकर वापस गांव चले गए. हमारी पढ़ाई-लिखाई वहीं हुई, लेकिन हमारा मुंबई आना-जाना लगा रहता था.

आपको उस दौर में क्या-क्या सहना पड़ा?

फिल्म लाइन में आने का मुझे शौक था. जो लोग इसमें छोटे-मोटे काम करते थे मैं उन लोगों के पास जाता था. उनके हाथ-पैर जोड़ता था, उनसे मिन्नतें करता था कि मुझे भी मौका दिलाओ. मुझे याद है कि मैं भिवंडी में लूम चलाता था. हमारी एक लकड़ी की खोली थी, वह भी आधी टूटी और आधी झुकी थी. बिस्तर में बहुत सरे खटमल थे, मैं और मेरा भाई उसमें रहते थे. मेरा भाई दिन-रात ड्यूटी करता था, वह दिन में केवल 2-3 घंटे सोता था. वह मुझे पैसे देता था, बोलता था कि भाई तू जा मेहनत कर. धीरे-धीरे यहां से वहां, वहां से यहां, दर-बदर घूमता रहा. कई होटलों में नौकरी की. 50 किलो की गेहूं-चावल की बोरी लेकर 7-8 माला बिल्डिंग में जाता था. लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा था. फिर मेरी मुलाकात सलमान भाई हुई, वह एक फरिश्ते की तरह मेरी ज़िन्दगी में आये और हमें कहां से कहां पंहुचा दिया. उन्होंने हमारी ज़िन्दगी बदल दी.

आपकी मुलाक़ात सलमान खान से कहां और कैसे हुई?

मुंबई के मड-आईलैंड में शूटिंग चल रही थी. मैं रात 3 बजे साजिद भाई के साथ वहां गया, तब वहां सलमान भाई से मुलाकात हुई. सलमान भाई ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा, कंधे पर हाथ रखकर साथ लेकर गये और बोले कि अच्छे से मेहनत करो, अच्छा काम करो. मैंने कहा कि मैं करूंगा. इसके बाद मैं मुखड़े लिखने लगा. फिर सलमान भाई को साजिद भाई के साथ मुखड़े बनाकर सुनाने लगा. भाई को मुखड़े अच्छे लगने लगे, वह बताने लगे इसे ऐसा करो, वैसा करो. ऐसा करते-करते सलमान भाई ने मुझे ***शादी करके फंस गया*** फिल्म में एक गीत दिलवाया.

शादी करके फंस गया फिल्म के कौन-कौन से गीत आपने लिखे?

उस फिल्म में सलमान भाई और शिल्पा शेट्टी पर फिल्माया गीत ***दीवाने दिल को जाने जां कहीं आराम नहीं..***, ये मेरा पहला गीत था. इसके बाद सलमान भाई ने दूसरी फिल्म गर्व दिलाई. इसके बाद मेरी मुलाकात सलीम सुलेमान जी से हुई. फिर सलमान भाई के साथ मैं शाहरुख़ भाई से भी मिला. तब शाहरुख़ भाई काल फिल्म में काम कर रहे थे. करण जौहर और शाहरुख़ खान साथ-साथ थे. मैंने भी एक गीत लिखा **तौबा-तौबा इश्क न करिया**. अल्लाह के करम से वो गाना उन्हें पसंद आया. फिर दूसरे गाने की बारी आई कि शाहरुख़ भाई और मलाईका अरोड़ा जी के ऊपर एक आइटम सॉन्ग चाहिए था, मैंने फिर वह गाना लिखा ***इस काल-काल में करें धमाल***. ये सब सिलसिला चलता रहा लेकिन इसकी शुरुआत सलमान भाई से हुई.

मगर अभी तो उनके खिलाफ दो-दो केस चल रहे हैं?

उनके केस के बारे में मुझे तो अभी कुछ नहीं पता है कि क्या है और क्या नहीं. लेकिन खुदा करे मालिक हर सदी में उनको लोगों की मदद करने के लिए भेजे. लोगों की मदद करना, लोगों को मंजिल तक पहुंचना, ये कोई आम बात नहीं है. बहुत बड़ी बात है. फिल्म इंडस्ट्री में तो सब बोलते हैं लेकिन कोई काम नहीं देता, केवल बड़ी-बड़ी बातें करते हैं.

ये लोग ऐसा क्यों करते हैं?

ये सबका अपना-अपना तजुर्बा है, अपना-अपना तरीका है. मगर आप सलमान भाई के सेट पर चले जाओ, घर पर चले जाओ, बिना खाए जाओ या खाकर जाओ. चाहे वो कोई भी हो, उनके यहां खाना, नाश्ता, पानी हर चीज़ आपको मिलेगी और वो देते हैं.

ऐसे कितने वाकये हैं सलमान भाई के?

अभी हाल ही में एक बार मैंने ***जुम्मे की रात*** गाने की लाइनें भाई को दीं, घर में कुछ बातचीत हुई फिर मैं वहां से निकल गया. मैं बोला चला जाता हूं. मैं वहां से जुहू तक ही पहुंचा था कि सलमान भाई ने फोन करके पूछा कि बिना खाना खाये चला गया. उन्होंने मुझे वापस बुलाया, कहा कि खाना खाओ फिर जाना. सलमान भाई की वजह से आज मेरे पांच भाई-बहनों की शादी हुई. मैंने मुंबई में अपना घर लिया. आज मेरा पूरा परिवार सेटल है. 2 महीने पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया. मुझे खुशी है कि भाई की वजह से मेरे वालिद ने दुनिया की हर खुशी देखी.

फिल्म *दिमाग का दही* के लिए आपने गीत लिखे हैं, खासकर जो कव्वाली आपने बनाई है उसके बारे में बताइए. कहां से इंस्पायर हुए?

देखिये, फौजिया अर्शी मेरी बहन हैं और इसका सारा क्रेडिट उन्हें जाता है क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से सिचुएशन और थॉट को एक्सप्लेन किया था, उस चीज तक पहुंचने की मैंने उसी हिसाब से कोशिश की. मैंने तो बस कोशिश की है. लेकिन एक अच्छा गाना बना है. फिल्म का टाइटल तो इतना फनी है, टाइटल सॉन्ग इंशाअल्लाह सुपरहिट होगा. ***फ्रॉक पहन के शॉर्ट, लगती हो बड़ी हॉट, बेबी किल मी ऑन द स्पॉट,*** इसके आलावा जो कव्वाली का सूफियाना अंदाज हो या रोमांस या रोमांटिक शायरी हर लेवल पर उनके साथ काम करना और इन सारी चीजों को साथ लाना कमाल की बात है. मेरे और उनके बीच यह डिबेट होता था कि ये सिंगर होना चाहिए. ये लिरिक्स होने चाहिए, इस तरह होना चाहिए. फौजिया जी ने कमाल का कंपोज़ किया है. कैलाश जी ने, शफाकत-अमानत अली जैसे लोगों ने इस फिल्म में गाने गाये हैं.■

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

27 अप्रैल–03 मई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

कांग्रेस और मांझी में पक रही है खिचड़ी

कांग्रेस का एक तबका यह मान कर चल रहा है कि जनता परिवार का विलय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है और लालू व नीतीश की मिली हुई ताकत हर हाल में नरेंद्र मोदी को बिहार में रोक देगी. इसलिए बेहतर होगा कि सूबे में महागठबंधन में ही सम्मानजनक स्थान खोजने का प्रयास किया जाए. जबकि एक खेमा चाहता है कि पार्टी को ज़मीन पर अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए.

सरोज सिंह

कहा जाता है राजनीति अपने हित में संभावना तलाशने और उसे अमलीजामा पहनाने का ही खेल है. कांग्रेस इन दिनों बिहार में राजनीति का यही गेम खेल रही है. पिछले दो दशकों से बिहार की राजनीति में लगभग हाशिये पर खड़ी कांग्रेस के लिए इस बार के सूबे के चुनाव में कुछ बेहतर करने का भारी दबाव है. यह दबाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा दिल्ली में अपनी गिरती साख को लेकर चिंतित बड़े नेताओं पर भी है. कांग्रेस आज केंद्र और बिहार की राजनीति में जिस दोराहे पर खड़ी है, उसके मद्देनज़र इस बार के बिहार चुनाव का महत्व और भी बढ़ जाता है. यही वजह है कि दिल्ली से लेकर पटना तक कांग्रेसियों के बीच गहन मंथन का दौर जारी है. दरअसल कांग्रेस के सामने चुनौती दोहरी है. पहला सबसे बड़ा टास्क नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकना है तो दूसरी प्राथमिकता राज्यों में अपनी ज़मीन को मजबूत करना भी है. बिहार में सत्ता से हटने के बाद से ही कांग्रेस सूबे में कभी लालू प्रसाद तो कभी नीतीश की पिछलग्गू बनकर ही रही है. मौजूदा नीतीश सरकार को भी कांग्रेस का समर्थन हासिल है. प्रदेश अध्यक्ष खुद तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की कृपा से एमएलसी बन गए पर कांग्रेस का चुनावी भविष्य क्या होगा, इसे लेकर कोई भी नेता आश्वस्त नहीं है. यह कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा कि सत्ता से हटने के बाद पार्टी का ज्यादा समय आपसी लड़ाई में ही गुजरा. एक अध्यक्ष बना नहीं कि दूसरा गुट उसे हटाने में लग गया. यह सिलसिला आज की तारीख तक जारी है. इस दौरान अगर कुछ दिनों के लिए अनिल शर्मा का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस ने अपना पूरा वक्त आपसी झगड़े में ही गुजार दिया. नतीजा यह हुआ कि पार्टी कभी अपने आप को ज़मीन पर खड़ी नहीं कर पाई. चुनाव में उसे बैसाखी की जरूरत पड़ने लगी और लालू प्रसाद अपनी शर्तों पर हमेशा इस काम के लिए तैयार दिखे. इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भूत कांग्रेस को परेशान किए हुए है. कांग्रेस को नरेंद्र मोदी को भी रोकना है और चुनावों में भी बेहतर करना है. चूंकि लक्ष्य दोहरा है इसलिए चुनावी रणनीति को लेकर भी एक राय नहीं बन रही है. कांग्रेस का एक तबका यह मान कर चल रहा है कि जनता दल परिवार का विलय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है और लालू व नीतीश की मिली हुई ताकत हर हाल में नरेंद्र मोदी को बिहार में रोक देगी. इसलिए बेहतर होगा कि सूबे में महागठबंधन में ही सम्मानजनक स्थान खोजने का प्रयास किया जाए. अभी हाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा भी था कि कांग्रेस के लिए बेहतर होगा कि वह महागठबंधन के साथ रहे ताकि नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोका जा सके.बिहार में भाजपा की हार से नरेंद्र मोदी का जादू देशभर में उतर जाएगा. जबकि कांग्रेस का दूसरा तबका मानता है कि जनता ने लालू नीतीश और सुशील मोदी का शासन देख लिया है इसलिए बेहतर होगा कि कांग्रेस बिहार में एक नया प्रयोग करे. इस खेमे का कहना है कि कांग्रेस को जीतनराम मांझी के साथ चुनावी तालमेल कर या फिर उनके पूरे कुनबे को कांग्रेस में शामिल कर अकेले चुनाव मैदान में उतरना चाहिए. इस खेमे का कहना है कि विलय सबसे आदर्श स्थिति होगी लेकिन अगर यह नहीं हो पाता है तो फिर जीतन राम मांझी को सीएम का प्रत्याशी घोषित कर आधी आधी सीटों पर चुनावी जंग में उतरना चाहिए. इस खेमे का तर्क है कि ऐसा करके कांग्रेस अपने पुराने जनाधार को एक बार फिर से जिंदा करने में सफल रहेगी. दलित, महादलित अल्पसंख्यक और अगड़ी जातियों को गोलबंद कर कांग्रेस बिहार में काफी बेहतर परिणाम हासिल कर सकती है. इससे पार्टी को अपनी ज़मीन तैयार करने में काफी मदद मिलेगी. सालों से सुस्त पड़ गए कांग्रेसियों को लगेगा कि पार्टी इस बार बिहार में किसी की पिछलग्गू नहीं बल्कि अपने बलबूते सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतरी है. अगर कांग्रेस बिहार में बेहतर नतीजे दे सकी तो फिर देशभर में उसे जिंदा होने का एक सुनहरा अवसर मिल जाएगा. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी कहते हैं कि अभी तो नीतीश कुमार सरकार को हमारा समर्थन है अब आगे क्या करना है इसका फैसला करने का अधिकार तो केंद्रीय नेतृत्व को है.

– शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

भूमि अधिग्रहण बिल के बहाने ज़मीन तैयार कर रही कांग्रेस

चंपारण में अपना वजूद खो चुकी कांग्रेस इन दिनों भूमि अधिग्रहण बिल के बहाने जनता को लुभाने व अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए संघर्ष करने लगी है. कांग्रेसी इलाके का भ्रमण कर रहे हैं और भूमि अधिग्रहण बिल के ख़िलाफ़ लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं.वे अपने कार्यकर्ताओं में भी पूरी तरह से उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं और एक बेहतर कार्ययोजना बनाकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं. क्या है भूमि अधिग्रहण बिल और इस बिल से क्या हानि होगी,विस्तार से चर्चा करते हुए कांग्रेसी नही थक रहे हैं.

पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया, संग्रामपुर, बंजरिया, कोटवा समेत सभी इलाकों में उनकी सक्रियता देखी जा रही है और इस अभियान से आगामी चुनाव में पड़ने वाले दूरगामी असर की समीक्षा की जाने लगी है.चौक-चौराहों पर भी कांग्रेस के इस अभियान की चर्चा हो रही है. कैसे आगामी चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रर्दशन करे, इस बाबत कार्यकर्ताओं को विशेष टास्क भी दिया जा रहा है और प्रदेश नेतृत्व की पूरी टीम इस अभियान में काफी सक्रिय दिख रही है. सुस्त पड़े कार्यकर्ताओं को भी जगाने की कोशिश की जा रही है और अपने आलाकमान के फैसले को आम-जनता तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं. यह पद यात्रा कांग्रेसियों के लिए कितनी सार्थक होगी और आगामी चुनाव में क्या रंग लायेगी, यह तो आने वाला समय ही निर्धारित करेगा किन्तु इस यात्रा ने जिस तरह राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है उसके अनुसार, कांग्रेस का यह अभियान भाजपा को काफी नुकसान पहुंचायेगा. बीते दिनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के नेतृत्व में केसरिया व संग्रामपुर में पहुंची पद यात्रा व इस यात्रा की स्वागत में उमड़ी भीड़ ने यह साफ कर दिया कि केन्द्र सरकार का भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेसियों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है और जनता का झुकाव भी उनके पक्ष में हो रहा है.यहां बताते चलें कि चंपारण में कांग्रेस पूरी तरह से अपना वजूद खो चुकी है और बीते लोक सभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद कांग्रेसी काफी सुस्त हो गये थे. किन्तु इस पद यात्रा ने एक बार फिर उन्हें जगा दिया है.प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने इस यात्रा के बाद केसरिया में एक सभा की और जो संदेश दिया उससे कार्यकर्ता उत्साहित तो हुए ही साथ ही पुराने साथी भी कांग्रस के नजदीक आ गये. उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल पर केन्द्र की मोदी सरकार पर जम कर निशाना साधा और कहा कि पुंजीपतियों को खुश करने के लिए मोदी सरकार यह बिल लायी है.इस बिल के खिलाफ कांग्रेस अपना अभियान जारी रखेगी और हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी.दूसरी तरफ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेन्द्र शुक्ला ने बताया कि कांग्रेसी प्रत्येक गांव में पहुंचने के लिए संकल्प ले चुके हैं और अपने लक्ष्य के अनुसार जनता तक पहुंच रहे हैं.उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से मान सम्मान देने का आश्वासन दिया और कहा कि कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज तैयार हो रही है जो प्रत्येक गांव व इलाके में जायेगी और लोगों को जागरूक करेगी. सभा के दौरान पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह, ब्रजेश पांडेय, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार, उपाध्यक्ष विपिन झा, राष्ट्रीय नेता शंभू सिंह, पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष राम पासवान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रजनीश कुमार सिंह, अंकु पांडेय, बच्ची पांडेय, मधुबाला पांडेय, जिला उपाध्यक्ष शशि कान्त मिश्र, मो. कलाम हुसैन, मुनमुन जायसवाल आदि ने अपनी पूरी सक्रियता दिखाकर चंपारण की राजनीति गरमा दी. कुल मिलाकर चंपारण में कांग्रेस अपनी जमीन तैयार करने की भरपूर कोशिश कर रही है और उसके कार्यकर्ता भी लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं.

– इंतेज़ारुल हक़

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

एक नज़र

रंगीन राजनीति का लोकार्पण

महंत हनुमानशरण कॉलेज, शिवम क्लासेज एवं साई–शिवम पब्लिक स्कूल, कुर्जी, दीघा, पटना–11 के सौजन्य से कथाकार डॉ. लालजी प्रसाद सिंह की 41वीं पुस्तक 'रंगीन राजनीति' (उपन्यास) का 'लोकार्पण –मार्च' अनोखे अंदाज में हुआ. लोकार्पण के लिए कारगिल चौक से जे.पी. गोलम्बर, गांधी मैदान, पटना तक तिरंगा एवं कैंडिल के साथ गाजे–बाजे, लाउडस्पीकर, शंख, डमरू बजाते हुए मार्च किया गया, जिसमें सैकड़ों प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, कलाकार, साहित्यकार और छात्र–छात्राएं शिक्षा एवं ज्ञान संबंधी विविध तख्तियां एवं स्लोगन लिए हुए शामिल थे. लोकार्पण–मार्च का नेतृत्व महंत हनुमान शरण कालेज के प्राचार्य एवं शिवम क्लासेज तथा साई–शिवम पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉ. बिमल नारायण आर्य और खुद कथाकार डॉ. लालजी प्रसाद सिंह कर रहे थे. उक्त अवसर पर प्राचार्य डॉ. बिमलनारायण आर्य ने कहा कि इस पुस्तक (रंगीन राजनीति) में कथाकार डॉ. लालजी प्रसाद सिंह ने निर्भीकता के साथ राजनीतिज्ञों की पर्दे के पीछे की रंगीन मिजाजी एवं काली करतूतों का वर्णन किया है. मार्च को सफल बनानेमें प्रो आरएस तिवारी, प्रो बीके राय, प्रो. सी.डी.सिंह, प्रो रंजना कुमारी, प्रो संजय ठाकुर, उपेन्द्र कुमार, मनोज कुमार, सीएन आर्या, प्रो गुलाम रब्बानी, प्रो रीना सिन्हा, प्रो मीरा कुमारी, प्रो दीपक कुमार, प्रो पंकज कुमार, बिन्देश्वर प्रसाद सिंह, प्रो नवीनकुमार, शैलेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र कुमार तथा छात्र–छात्राओं में शैलेश, शैलेन्द्र, ज्योतिका, नदीम, मधु, , माही, अभिषेक, रमेश, आदित्य इत्यादि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. *– भारती*

राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित

सीतामढ़ी शहर के राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज के सभागार में भारतीय इतिहास संकलन समिति उत्तर बिहार व एसआरकेजी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया. युग युगीन मिथिला : अतीत से वर्तमान तक विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्व विद्यालय के कुलपति डॉ साकेत कुशवाहा एवं मुख्य वक्ता के रूप में डॉ बालमुकुन्द पांडेय, विशिष्ट अतिथि डॉ देवनारायण यादव, डॉ मनोरंजन कुमार दूबे, डॉ आरके मेहता, डॉ राणा तेज प्रताप सिंह, भारतीय इतिहास संकलन समिति उत्तर बिहार की महासचिव डॉ बबिता कुमारी, संगठन सचिव संतोष कुमार झा समेत अन्य थे. डॉ देवनारायण झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया. मिथिला के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जानकी स्मारिका का विमोचन किया गया. कार्यक्रम में सांसद राम कुमार शर्मा, विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद, चंदौना कॉलेज के प्राचार्य डॉ बुद्धदेव प्रसाद सिंह, डॉ कमलेश दास, राम शरण अग्रवाल, डॉ रेणु चटर्जी, डॉ प्रो संजीव कुमार राम, अभय प्रसाद, वसंत मिश्रा समेत अन्य थे. *– विकास कुमार*

बेगूसराय

बीड़ी मज़दूरों का आर्थिक शोषण

सुरेश चौहान/पंकज कुमार झा

नियोजक, ठेकेदार, बिचौलिये एवं दलालों द्वारा राज्य के लगभग 10 लाख बीड़ी मजदूरों का व्यापक पैमाने पर आर्थिक शोषण जारी है. इंदिरा आवास, स्वास्थ्य बीमा, वृद्धापेंशन, स्वनियोजन, खाद्य सुरक्षा, लालकार्ड, पीलाकार्ड सहित अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं बिहार के बीड़ी मजदूर. पसमांदा समाज के अंसारी, कौमाराईन कौमामसूरी, दफाली, नाई, धोबी, पमरिया, हलालखोर लालबेगी, मेहतर आदि परिवार के बच्चे–बूढ़े एवं औरत–मर्द 100 वर्षों से बीड़ी बनाकर इससे प्राप्त पारिश्रमिक से अपने परिवार का भरण–पोषण करते आ रहे हैं. कम आमदनी के कारण इनकी जीवनशैली जानवरों जैसी है. प्राणघातक बीमारियों से ग्रसित बीड़ी मजदूर उपचार के अभाव में असमय ही कालकवलित हो रहे हैं. न रहने को घर है, न बच्चों को पढ़ाने की क्षमता है और न इलाज के लिए पैसे हैं. क्या नीतिश सरकार के स्लोगन 'न्याय के साथ विकास' के दायरे में बीड़ी मजदूर नहीं आते है? सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं मिलती है?

आजाद बीड़ी मजदूर यूनियन, बिहार के महासचिव मो. एहतेशामुलहक अंसारी कहते हैं कि बिहार में खुलेआम श्रम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है. प्रजातंत्र का तंत्र गरीबों की मदद करने में सर्वथा विफल साबित हो रहा है. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा बीड़ी मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी 182 रुपये प्रति हजार निर्धारित है. लेकिन राज्य के किसी भी भाग में बीड़ी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नसीब नहीं हो रही है. बीड़ी कंपनियों के नियोजक, ठेकेदार, बिचौलिये एवं दलाल द्वारा बीड़ी मजदूरों को 182 रुपये प्रति हजार की जगह 30 से 70 रुपये प्रति हजार ही दिए जाते हैं. मजदूरी देने में भी लिंग भेद किया जाता है. महिलाओं को पुरुषों से कम मजदूरी दी जा रही है. महासचिव को विरासत में मिली है, बीड़ी मजदूर का पेशा. उनके माता–पिता भी बीड़ी मजदूर थे. महासचिव खुद व इनकी पत्नी अभी भी इसी पेशा से जुड़े हैं और कार्यालय कार्य से बचे समय में वे अभी भी बीड़ी बनाने का काम करते हैं. बीड़ी मजदूरो की दशा सुधारने के लिए राज्य/केन्द्रीय सरकार के यहां अनेक दफा मेमोरेन्डम दिया. बन्धुआ मुक्ति मोर्चा सहित अन्य श्रमिक संगठनो से भी अपील किया. मांग को लेकर धरना प्रदर्शन सम्मेलन किया लेकिन प्रजातंत्र के प्रवर्त्तकों पर इसका प्रभाव नही पड़ा.

बीड़ी मजदूरों के इलाज के लिए बिहार में 12 अस्पताल स्थापित हैं. इसके साथ ही गंभीर बीमारी के इलाज के लिए बिहार शीरफ में 32 बेड का एक अस्पताल है. लेकिन सभी अस्पताल खुद बीमार है. कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं अन्य स्टाफ नहीं. दवा की भारी किल्लत है. चौंकानेवाली बात यह है कि एक अस्पताल के लिए (बिहार शरीफ को छोड़कर) मात्र 30 हजार रुपये सालाना दवा खरीदने के लिए स्वीकृत है. बेगूसराय के बछबाड़ा में भी एक अस्पताल है जहां बेगूसराय एवं खगड़िया जिले के बीड़ी मजदूरों का इलाज किया जाता है. इस अस्पताल में 35 हजार बीड़ी मजदूर निबंधित हैं जिनके इलाज के लिए (दवा खरीद पर) वर्ष में मात्र 30 रुपये मिलते है. बिहार में लगभग 10 लाख बीड़ी मजदूरों की संख्या है जिसमें लगभग 9 लाख महिलाओं की संख्या है. बेगूसराय में बीड़ी मजदूरों की संख्या 50 हजार है जिसमें 40 हजार महिलाएं हैं. बेगूसराय जिले के लडुआरा, फतेहपुर, रजौड़ा, मुज्रफरा, बारो, पबड़ा, मेहदाशाहपुर, बागर, चकहम्मीद, मक्खाचक, हसनपुरबागर, दामोदरपुर, धनकौल, किरतौल, बनद्वार, सरायनूर नगर, मंसूरचक, कारदाबाद, तेमुंहा, रशीदपुर, तेघड़ा, तकिया, बनव–रीपुर, बरौनी बरियारपुर, अमारी आदि गांवो में बीड़ी बनाया जाता है. बीड़ी मजदूर इंसान अली राइन, अब्दुल जब्बार अंसारी, कासिम अंसारी, कमरुल हुदा अंसारी, जमाल अंसारी, किशोर साह, अनिरुद्ध पासवान, मनसुख पासवान, मो. हारुन, जाकिर अंसारी, चन्द्र प्रकाश शर्मा, किरण देवी, नसीमा खातुन, पाकिजा खातुन, हमीदा खातून रौशन आरा, गुलशन आरा, संजीदा खातुन, कौशद जहाँ, महजमीं परबीन आदि कहते हैं कि बीड़ी बनाने का काम जोखिम भरा है. इससे कैंसर, टीबी, पेट, आंत, लीबर, जिगर, आँख, सांस आदि से संबंधित गंभीर बीमारी का खतरा हमेशा बना रहता है. आधे मजदूर प्राय: बीमार रहते है. इलाज ठीक से नहीं हो पाता है. कम मजदूरी मिलने से परिवार चलाने में काफी दिक्कत होती है. इसके साथ ही मंदिर, मस्जिद मदरसा निर्माण के लिए दोजख–जन्नत का भय–लालच दिखाकर फिरकासदकी के नाम पर इन गरीबों से आर्थिक सहयोग लेते है.

बीड़ी के पत्ते की बिक्री से वन विभाग प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का राजस्व राज्य सरकार को देती है. इसके साथ ही बीड़ी की बिक्री से भी राजस्व प्राप्त होता है. कुल आय की यदि पचास प्रतिशत राशि भी बीड़ी मजदूरों के आवास, स्वास्थ्य, बच्चो की शिक्षा एवं न्यूनतम मजदूरी देने पर व्यय किया जाय तो इनकी स्थिति में बेहतर सुधार संभव है. साथ ही इन मजदूरों को विभिन्न स्वरोजगार का प्रशिक्षण देकर रोजगार चलाने के लिए पूंजी दी जाय तो इनका जीवन शैली बदल जाएगर.■

feedback@chauthiduniya.com

गया (नगर) विधान सभा क्षेत्र

भाजपा की राह आसान नहीं

सुशील गौतम

[illegible]

पता चल जायेगा कि इसमें कितनी लूट हुई हैं. 25 वर्षों में सैकड़ों की संख्या में लगे चापाकलों में शायद ही कोई चालू हो. इसी प्रकार जयप्रकाश झरना, काशीनाथ मोड़ तथा समाहरणालय के निकट प्रेम कुमार ने अपनी राशि से फब्वारा लगाया. ये सभी फब्वारे कुछ दिनों के बाद ही बंद हो गये. भले इसकी राशि से विधायक जी के खास लोगों के मन का फब्वारा फूटने लगा. [illegible]

कांग्रेस और मांझी में पक रही है खिचड़ी

पृष्ठ 17 का शेष

आलाकमान का जो आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा. कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को लग रहा है कि महाविलय के बाद कांग्रेस के लिए चुनावी स्कोप काफी कम हो गया है. महागठबंधन से तालमेल की स्थिति में ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिल पाएंगी इसकी संभावना बेहद कम है. केवल टोकन टिकट लेकर चुनाव लड़ने से पार्टी कभी भी ज़मीनी स्तर पर खड़ा नहीं हो पाएगी. इस तालमेल से कुछ नेताओं को फ़ायदा हो सकता है लेकिन कांग्रेस को इससे मजबूती मिलने वाली नहीं. अगर मांझी के साथ बराबरी का भी तालमेल हो जाए तो बहुत सारे समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है और जमीन पर पार्टी का आधार खड़ा हो सकता है. अब फैसला आलाकमान को करना है कि कांग्रेस को किसी के सहारे पर चलाना है या फिर अपने पैरों पर खड़ा करने का जतन करना है. दूसरी तरफ कांग्रेस से तालमेल को लेकर मांझी खेमे में भी दो तरह की राय है. स्थापित नेताओं की राय है कि भाजपा के साथ ही सम्मानजनक तालमेल किया जाए ताकि चुनावी जंग में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े. ऐसे नेता कांग्रेस से तालमेल का रिस्क लेने को फिलहाल तैयार नहीं हैं. लेकिन अगर भाजपा ने तालमेल में सीटों की संख्या कम कर दी तो क्या होगा इसका जवाब इन नेताओं के पास नहीं है. वहीं दूसरा खेमा मानता है कि हम 143 सीटों पर और कांग्रेस 100 सीटों पर तालमेल कर चुनाव मैदान में उतरे. इस खेमे का कहना है कि ऐसे हालात में बिहार में त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी और कोई भी चुनाव जीत या हार सकता है. यही वजह है कि जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि वह चुनाव से पहले किसी भी दल से समझौता नहीं करेंगे. जीतनराम फिलहाल वेट एंड वाच के मूड में हैं. जानकार बताते हैं कि मांझी तालमेल करेंगे ज़रूर, पर वह अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं. चुनाव नजदीक आने के बाद वह ठोंक बजा कर अपने पत्ते खोलेंगे और भाजपा या फिर कांग्रेस के साथ तालमेल कर चुनावी जंग में उतरेंगे.■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड

साहिबगंज में गंगा तट पर बनेगा मल्टी मॉडल बंदरगाह

बंदरगाह बनने से अंतरराश्टीय बाजार से जुड़ेगा साहिबगंज, हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्यों से बिहार झारखंड समेत पूरे देश का सीधा संपर्क. साथ ही नेपाल आने–जाने का नया अंतरराष्ट्रीय मार्ग खुलेगा. बिहार और झारखंड बनेगा पर्यटन का नया हब. इसके अलावा विदेशी मुद्रा के आदान–प्रदान से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था, यह देश का पहला ऐसा बंदरगाह होगा जो जल, रेल एवं सड़क मार्ग से सीधा जुड़ेगा.

कुमार गौरव

भारत सरकार ने झारखंड के साहिबगंज गंगा तट पर मल्टी मॉडल बंदरगाह बनाने को लेकर प्रयास शुरू कर दिया है. भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय ने 171 करोड़ की लागत से लगभग 40 एकड़ जमीन पर देश का पहला मल्टी मॉडल सिस्टम बंदरगाह बनाने का फैसला किया है. जानकारी के अनुसार पोत परिवहन मंत्रालय का पत्र मिलने के बाद भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने बीते वर्ष जिला प्रशासन को पत्र लिखकर इसके लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध करने का आग्रह किया था. साहिबगंज में बंदरगाह निर्माण के लिए फिलहाल भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण को लगभग 40 एकड़ जमीन की आवश्यकता है. प्राधिकरण को बंदरगाह के लिए सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए जमीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा. साथ ही रेलवे के अधिकारियों को भी पत्र के माध्यम से बंदरगाह के पास रेल संबंधी योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है. ताकि साहिबगंज में बनने वाले अंतरराष्टीय बंदरगाह को रेल लाइन से भी जोड़ा जा सके. प्राधिकार सूत्रों के अनुसार साहिबगंज में गंगा के किनारे बनने वाला यह देश का पहला ऐसा बंदरगाह होगा जो जल, रेल एवं सड़क मार्ग के साथ जुड़ेगा. देश में अब तक जितने भी बंदरगाह बने हैं वह किसी समुद्र के किनारे ही बने हैं. साहिबगंज की भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहां के बंदरगाह को रेल एवं सड़क मार्ग से जोड़ना आसान हो जाएगा. एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इस समय धनबाद के गोविंदपुर से साहिबगंज के बीच एक्सप्रेस वे सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है. जिसका सीधा संपर्क इस बंदरगाह से हो जाएगा. ऐसे में झारखंड के इस साहिबगंज जिले को विश्व के नक्शे पर जगह मिलेगी. साहिबगंज के बंदरगाह बनाने के मामले को लेकर राजमहल के विधायक अनंत ओझा ने विशेष बातचीत में बताया कि बंदरगाह बनने से संथाल परगना का अपेक्षित विकास होगा. यहां पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और देश विदेश से पर्यटक आसानी से यहां पहुंच सकेंगे. बिहार झारखंड में कई प्रमुख पर्यटन केंद्र होने के बावजूद आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण हर साल लाखों विदेशी पर्यटक इस क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं.

पर्यटक विक्रमशिला व मंदारहिल आने के बाद वापस लौट जाते हैं. वैसे जलमार्ग से हर साल कुछ विदेशी पर्यटक फरक्का के रास्ते राजमहल एवं इसके आसपास के इलाके में फैले ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को देखने यहां आते हैं. इसका सीधा असर यहां के व्यापार व उद्योग पर पड़ेगा. यहां के खनिज संपदा को देश व विदेश का बाज़ार मिलेगा. अब तक यहां के खनिज को सिर्फ रेल व सड़क मार्ग से दूसरी जगह भेजा जाता है. जलमार्ग होने से यहां के खनिज दूसरे मंडियों तक आसानी से भेजा जा सकेगा. इसका सीधा लाभ यहां के व्यापारियों को मिलेगा एवं रोजगार के साधन बढ़ेंगे. श्री ओझा ने बताया कि क्षेत्र के विकास में बंदरगाह की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. गुजरात व महाराश्ट का इदाहरण प्रस्तुत करते हुए इन्होंने कहा कि इन जगहों पर बंदरगाह के होने का फायदा यहां के व्यापारियों को मिलता है और अन्य जगहों के मुकाबले यहां के लोग ज्यादा आमद कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर झारखंड में खनिज संपदा की कमी नहीं होने के बाद भी आवागमन की सुविधा के अभाव में खनिज संपदा अन्य राज्यों तक भेजना परेशानी का सबब बन जाता है.■

feedback@chauthiduniya.com

जमीन अधिग्रहण के पेंच में फंसा साहिबगंज में बंदरगाह का निर्माण

सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार जमीन अधिग्रहण मामला रैयत व सरकारी फाइलों के पेंच में फंस जाने के कारण भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अब तक जमीन हस्तांतरित नहीं किया जा सका है. इस कारण बंदरगाह निर्माण कार्य का डीपीआर बनाने का कार्य शुरू नहीं हो सका है. जबकि साहिबगंज जिला प्रशासन के द्वारा भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण को सितंबर 15 तक जमीन हस्तांतरित करना है. इसके लिए झारखंड सरकार को भू-अर्जन प्रावधान के मुताबिक मुआवजे का भुगतान करना है. इस मामले में साहिबगंज के उपायुक्त उमेश प्रसाद सिंह ने बताया कि बंदरगाह के लिए भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन प्राधिकरण की ओर से बंदरगाह निर्माण के लिए सकरीगली स्थित गंगा किनारे समदा घाट के पास जमीन का चयन किया गया है. जमीन से संबंधित जो भी अड़चनें है इसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा एवं इसकी रिपोर्ट मंगाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

अन्य ख़बरें

भोजपुरी फिल्म में खगड़िया पुत्र

गोगरी अनुमंडल कोशी क्षेत्र की धरती पर कृष्ण म्यूजिक के बैनर तले बन रही भोजपुरी फिल्म लव के सौदा की शूटिंग कोशी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जारी है. निर्माता निर्देशक शंभू साधारण ने बताया कि भोजपुरी सिनेमा जगत में इसकी कहानी एक अलग किस्म की है, जो बिहार के दर्शकों को बेहद पसंद आयेगी. वहीं इस फिल्म में स्थानीय लोक गायक राहुल दीवाना को लोग इस भोजपुरी फिल्म में पहलीबार एक विलन की भूमिका में देख पायेंगे. सनद रहे कि दिवाना वर्षो से कैसेट के क्षेत्र में कई बार बम्पर सफलता हासिल कर चुके हैं. आशा की जा रही है कि लोग फिल्मों में अभिनेता श्वेत तथा अभिनेत्री श्वेता राय के साथ ही रौशन सिंह, कृष्ण मेहता, दीपक कुमार, भारत भूषण इंडिया एवं भोजपुरी लोक गायक गीता कुमार आदि ने अपनी भूमिका निभाई है.

फलों के दाम में मिल रही सब्जियां

गोगरी अनुमंडल क्षेत्राधीन बाजारों में बिक रही हरी सब्जियों की ऊंची कीमत आम लोगों के पहुंच से दूर सी हो गई है. इस वजह से इन दिनों सब्जी खाना लगभग दूभर सा हो गया. सब्जी की बढ़ी कीमत का हाल यह है कि बाजार में सब्जी व फलों का दाम लगभग बराबर है. अगर सेब 70 से 80, नारंगी व अंगूर 50 से 60 रुपये की दर से बिक रहे हैं तो नेनुआ भी 70 रुपये किलोग्राम की दर से बिक रहा है. वहीं परवल, करेला, भिंडी 50 से 60, कद्दू 25 रुपये की दर से बिक रहे हैं. वहीं इस मौसम में गांव–देहात में आसानी व सुलभता से मिलने वाला सहजन भी 60 से 70 रुपये की दर से बिक रहा है. बाजारों में हाल यह है कि आम आदमी सब्जी की कीमत पूछने से भी कतरा रहा है. गृहणियों के अनुसार वर्तमान में सब्जी की कीमत इतनी ज्यादा है कि हरी सब्जी नाम मात्र की खा पा रहे हैं. वहीं सब्जी विक्रेता के अनुसार वर्तमान में सब्जी मंडी में ही मंहगी मिल रही है. जो की अन्य जिलों से आ रही है. बात सहजन की करें तो इस साल सहजन के फूल के समय में हुई वर्षा और ओलावृष्टि से सहजन के फूलों को क्षति हुई. जिस कारण यहां सहजन काफी कम मात्रा में हुआ है. वरना इस समय में सहजन की कीमत दस रुपये भी नहीं रहती. सब्जियों की ऐसी स्थिति कुछ दिन और रहेगी जब तक की स्थानीय खेतों से सब्जियां बाजार में आने लगेंगी.

पेंशन राशि हेतु धरना

गोगरी अनुमंडल क्षेत्राधीन प्रखंड कार्यालय प्रांगण में एक दिवसीय धरना दिया गया. धरने में भाग ले रहे पेंशनधारी व पर्चाधारी बालकृष्ण यादव, विष्णुदेव यादव, तनुकिया देवी, राशो देवी, अकल साह, महेश्वरी दास, फूलवती देवी आदि ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पेंशनधारियों को एक वर्ष से पेंशन की राशि नहीं दी गई है. दूसरी ओर मतदाता सूची में गलत उम्र दर्ज कर 40 वर्ष के सम्पन्न व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है. वहीं बैठक का नेतृत्व कर रहे भाकपा (माले)के जिला सचिव अरुण कुमार , युवा शक्ति के जिला संरक्षक सह पूर्व मुखिया अजय रंजन चौरसिया आदि ने कहा कि जब तक पेंशन के हकदार को वाजिब हक व पर्चाधारियों को जमीन पर दखल दिलाने की ओर अधिकारी सार्थक कदम नहीं उठाते हैं तबतक सरकार के मुलाजिमों को चैन की नींद सोने नहीं देगें. वहीं परबत्ता सीओ शैलेन्द्र कुमार ने घटना पर बैठे पर्चा की जमीन से बेदखल व पेंशन से वंचित लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि वेलोग पर्चाधारियों को जमीन पर दखल दिलाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. आयोजित धरना की अध्यक्षता शिरधर सहनी ने किया. इस मौके पर विवेकानंदइ निराला, उदयकांत सिंह, राज कुमारी देवी, माला देवी, इन्द्रदेव साह, बीरो राय, झकसी साह एवं प्रभूनारायण शर्मा सहित सैकड़ों पर्चाधारी व पेंशन से वंचित लोग उपस्थित थे.

नगर पंचायत उपाध्यक्ष निर्वाचित

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के गोगरी नगर पंचायत के नये उपाध्यक्ष पद पर वार्ड संख्या 12 के वार्ड पार्षद सनोज कुमार मिश्र चुने गये. अनुमंडल कार्यालय के सभागार में कड़ी व्यवस्था के बीच पर्यवेक्षक सह एडीएम एएच रहमान की मौजूदगी में उपाध्यक्ष पद के लिए कराये गये चुनाव में सनोज मिश्रा व विजय पंडित ने अपनी अपनी नामजदगी का पर्चा भरा. बाद में हुए चुनाव में 18 वार्ड पार्षदों ने मतदान में हिस्सा लिया. मतदान के बाद हुए गिनती में सनोज मिश्रा को 11 मत व विजय कुमार पंडित को 7 मत प्राप्त हुए. इसके बाद एसडीओ संतोष कुमार ने ऑब्जर्वर की उपस्थिति में नए उपाध्यक्ष को प्रमाण पत्र सौंपा तथा उन्हें पद व गोपनीय की शपथ दिलाई. मौके पर दंडाधिकारी किसलय कृष्ण, नगर पंचायत अध्यक्ष रंजीता कुमारी निषाद, वार्ड पार्षद मायाराम मंडल, अबू मोहम्मद उर्फ गुदर सेठ, अफरोज आलम, मो. यूसुफ, मो. कुबारक हुसैन, रेणू देवी, अनिता कुमारी, विन्दु शर्मा, किरण देवी, पूनम देवी, दीपक कुमार, रामकृष्ण प्रसाद, धर्मा ठाकुर, उर्फ दीपक कुमार आदि मौजूद थे. ज्ञात हो कि इसके पूर्व भी सनोज मिश्रा नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पद पर रहे थे. जानकारी हो कि वर्तमान उपाध्यक्ष संजीव कुमार सोनी के शिक्षक बनने के बाद उपाध्यक्ष पद रिक्त था, जिसके कारण उपाध्यक्ष पद का चुनाव करना पड़ा.

टूटा अनशन

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के प्रखंड परिसर में किसानों की चार सूत्रीय मांगों को लेकर गोगरी कार्यालय परिसर में आमरण अनशन पर बैठे जिला कमेटी के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार विद्यार्थी ने प्रथम दिन ही एसडीओ संतोष कुमार के आश्वासन पर आमरण अनशन टूट गया. कांग्रेस नेता अखिलेश कुमार विद्यार्थी ने अनुमंडल के विभिन्न फैक्स अध्यक्षों एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान एवं मानसी कांग्रेस अध्यक्ष बुद्धन यादव के सहयोग से आमरण अनशन पर बैठे थे. जिसमें मुख्य मांगे थी कि ओलावृष्टि एवं बारिस के कारण गेंहू की फसल क्षति हुई है. एसडीओ ने समझाने व बुझाने व मांगों को सरकार के पास भेजने की आश्वासन के बाद अनशन समाप्त कर दिया गया. इस मौके पर भगवान यादव, विनोद चौबे, फणीभूषण यादव, रघुवंश यादव, नकुल शर्मा सहित सैकड़ों लोग इपस्थित थे.■

– गीता कुमार

एक नज़र

विधायक ने किया चेक वितरित

सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में एक शिविर का आयोजन किया गया. स्थानीय जदयू विधायक गुड्डी देवी ने शिविर का उद्घाटन किया. मौके पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अनुसूचित जाति के 215 लाभुकों के बीच चेक का वितरण किया. शिविर में लाभुकों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू कराया है. लड़कियों के जन्म के बाद से सुरक्षा को लेकर कन्या सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है. वरिष्ठ जदयू नेता राजेश चौधरी ने लोगों से किसी भी सरकारी योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए गलत लोगों से संपर्क नहीं करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि अगर योजना के तहत लाभ दिलाने के नाम पर कोई पैसा का मांगे तो इसकी शिकायत विधायक व बीडीओ से करने से परहेज न करें. मौके पर महिला प्रसार पदाधिकारी मीनू कुमारी, जिला पार्षद संजीत कुमार छोटू समेत अन्य थे. *– विभा सिन्हा*

फर्जी जांच मामला

सीतामढ़ी व शिवहर जिला में व्यपक स्तर पर चलाये जा रहे फर्जी जांच घर का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. सीतामढ़ी के वरिष्ठ लोजपा नेता सवीह अहमद की 7 माह की पुत्री का फर्जी जांच का मामला सामने आने के बाद जिले में बदहाल चिकित्सा व्यवस्था को लेकर आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गयी है. लोजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में साफ तौर पर मांग की जाने लगी है कि पॉपुलर जांच घर के संचालक डॉ नरेंद्र कुमार सिंह की गिरफ्तारी नहीं की गयी तो पार्टी आंदोलन को तैयार है. आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक नगीना देवी ने कहा कि जिले में संचालित फर्जी क्लिनिक व जांच घरों की न्यायिक जांच होनी चाहिए. जिलाध्यक्ष मोहन झा ने कहा कि जांच के नाम पर गरीबों का व्यापक स्तर पर शोषण किया जा रहा है. सवीह अहमद ने कहा कि जिला में स्वास्थ्य महकमे की कमान थामने वाले सीएस स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त है. पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राम पुकार राय, नसीर अहमद उर्फ लालजी, फखरुद्दीन अली अहमद व दलित सेना के जिलाध्यक्ष हरजीतू पासवान समेत अन्य थे. *– विकास*

बागवानी संगम का आयोजन

भारत सरकार के केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने मोतिहारी के गांधी मैदान में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा आयोजित अंतर्राज्यीय बागवानी संगम सह प्रदर्शनी 2015 मेले का उद्घाटन किया. केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि चौदह करोड़ लोगो के पास जमीन है जो अपनी मिट्टी की खुशबू से आह्लादित हैं. किस खेत में कौन सी बीमारी है और कौन सी दवा दी जायेगी,इसकी जांच कर अगर खेतों में उर्वरक दिया जाए तो अच्छी फसल हो सकते है. उन्होंने बताया कि मिट्टी की जांच के लिए केन्द्र सरकार स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड दे रही है. परम्परागत कृषि विकास योजना के द्वारा किसानों को अनेक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. इसमें किसानों को जैविक उत्पादकता के लिए बीस हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा. भारत सरकार हर गांव के किसानों के लिए मिट्टी की जांच के लिए स्वायल हेल्थ कार्ड मुहैया करा रही है, जिससे खेती में फायदा हो सके. उन्होंने कहा कि एक रुपये नव्वे पैसे में हेल्थ कार्ड के द्वारा मिट्टी की जांच की जाएगी. 568 करोड़ रुपये की राशि इसके लिए स्वीकृति की गयी है. मौके पर शिवहर सांसद रमा देवी,प्रभारी जिलाधिकारी भरत दूबे, एसपी सुनील कुमार, केसरिया विधायक सचिन्द्र सिंह, नगर विधायक प्रमोद कुमार, कृष्णनन्दन पासवान, जिला कृषि पदाधिकारी शकील अख्तर अंसारी समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे.

बाल श्रमिकों को मिली राशि

बाल श्रम सभ्य समाज के माथे पर एक काला धब्बा है और जबतक इसका खात्मा नहीं हो जाता तबतक समाज की तरक्की संभव नही है. बाल श्रम को मिटाने के लिए सरकार अनेक ऐतिहासिक योजनायें चला रही है और बाल श्रमिकों को अनेक लाभ दे रही है. उक्त बाते श्रम अधीक्षक संजीव कुमार ने रक्सौल में प्रयास द्वारा आयोजित पुनर्वास की राशि वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने प्रत्येक बाल श्रमिक को अठारह–अठारह सौ रुपये दिये और कहा कि विभाग और कई योजनायें इनके लिए चलायेगा. इस अवसर पर मौजूद पटना से आये प्रयास के सुरेश कुमार ने बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए चलायी जा रही गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि प्रयास बाल श्रमिकों को विमुक्त करने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि समाज से भटके लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना तथा अभिभावकों को जागरूक करना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है. मौके पर बाल कल्याण समिति के सदस्य प्रेम कुमार दास, रक्सौल के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एसएसबी सिविल के एरिया कमांडर, लेडीज बटालियन की रूपा गर्ग आदि ने अपने–अपने विचार व्यक्त किये और कार्यक्रम को सफल बनाया. मौके पर प्रयास के डॉ. विजय शर्मा, आरती कुमारी, रौशनी आदि उपस्थित थे.

परिणय सूत्र में बंधे छह जोड़े

पूर्वी चम्पारण जिले के पहाड़पुर प्रखण्ड के सिसवा बाजार के पास माई स्थान परिसर में नवयुवक समिति के तत्वावधान में छह जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मौके पर केन्द्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह,समिति के प्रधान संरक्षक पूर्व जिप अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, हरसिद्धि विधायक कृष्णनन्दन पासवान, पूर्व विधायक महेश्वर सिंह, गोविन्दगंज विधायक मीना द्विवेदी, भाजपा नेता सुभाष सिंह कुशवाहा, स्थानीय मुखिया विश्वनाथ सिंह, लालबाबू सिंह सहित कई हस्तियों ने वर–वधुओं को आर्शीवाद दिया. हरसिद्धि क्षेत्र के घिवाढ़ार चौक से करीब दो बजे गाजे–बाजे के साथ छह दूल्हे घोड़े पर सवार हो जैसे ही मण्डप में प्रवेश किये वैसे ही देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी. वर–वधुओं में अशोक कुमार नरकटिया गंज संग प्रिती कुमारी सिसवा, अजय कुमार रामनगर बैरिया संग पूजा कुमारी पड़रिया, धर्मेन्द्र कुमार बलुआ संग रंजीता कुमारी सिसवा, बबलू कुमार गोइठाहा संग सविता कुमारी सिसवा, भुटकुन पासवान बेतिया शिवराज पुर संग नीलम कुमारी अहिरगांवा, इमेश कुमार अहिरगांवा संग रूपा कुमारी मठालोहियार शामिल है. इस सेवा समिति में प्रधान संरक्षक राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह, सचिव उमेश कुमार, सह सचिव संजय सिंह, मुकेश सिंह, विद्याभूषण सिंह, संयोजक मनोज कुशवाहा, उपाध्यक्ष शिवनाथ सिंह, प्रेस प्रभारी द्वारिका सिंह, कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता, अरविन्द सिंह, जिला पार्षद अम्बिका पासवान, आनन्द कुमार तिवारी, शम्भूनाथ चौबे, शम्भू प्रसाद गुप्ता, प्रेम कुमार गुप्ता, शैलेश कुमार, लालबाबू सिंह, गगनदेव ओझा सहित सैकड़ों प्रबुद्ध लोगों ने वर–वधुओं को आर्शीवाद दिया. *–इंतेजारुल हक*

संघर्ष से भरी एक प्रेम कहानी

उन पर अरेस्ट वारंट भी निकला हुआ था. इसी वजह से उस समय इस रिश्ते से लवली के घर वालों ने मना कर दिया. लवली बताती हैं कि उनके घर वालों का कहना था कि अगर आनंद कुछ बन जाते हैं. अपनी जिंदगी में कुछ कर जाते हैं. या यूं कहें कि मेरे लायक बन जाते हैं तब वो लोग इस रिश्ते के बारे में कुछ सोचेंगे. ये बात कुछ समय के लिए टल गई. धीरे-धीरे वक्त बीतता गया. कहीं ना कहीं मेरे मन में भी आनंद के लिए एक जगह बन गई थी. लवली कहती हैं कि आनंद को देख कर मेरे मन में एक पॉजिटिव फीलिंग आई थी. मुझे ऐसा लगा कि मुझे जैसे लड़के की अपने लिए तलाश है वो आनंद ही हैं.

राधिका

feedback@chauthiduniya.com

इस बार की प्रेम कहानी एक ऐसे जोड़े पर है, जिसने अपने अभी तक के जीवनकाल में ढेरों संघर्ष किए हैं. शादी से लेकर अभी तक का जीवनकाल उनके लिए संघर्ष भरा ही रहा है. हम बात कर रहे हैं कोसी की मिट्टी में पैदा हुए आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद की.

ये सिलसिला तब शुरू हुआ था तब लवली स्कूल में पढ़ती थीं. लवली कहती हैं कि आनंद कभी शादी नहीं करना चाहते थे. वो तो शुरू से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे. लेकिन उनके ये विचार बदले जब उन्होंने मुझे देखा. शायद आनंद को मैं पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी. लेकिन मुझे इस बात की कोई भनक नहीं थी. मैं तो अपनी पढ़ाई-लिखाई में मशगूल थी. मुझे तो इस बात का तब पता चला जब आनंद की मां उनका रिश्ता लेकर मेरे घर आई थीं. इन दोनों की शादी को लव कम अरेंज भी कहा जा सकता है.

लेकिन जब आनंद की मां उनका रिश्ता लेकर लवली के घर गई थीं तब आनंद अंडरग्राउंड चल रहे थे. उन पर अरेस्ट वारंट भी निकला हुआ था. इसी वजह से उस समय इस रिश्ते से लवली के घर वालों ने मना कर दिया. लवली बताती हैं कि उनके घर वालों का कहना था कि अगर आनंद कुछ बन जाते हैं. अपनी जिंदगी में कुछ कर जाते हैं. या यूं कहें कि मेरे लायक बन जाते हैं तब वो लोग इस रिश्ते के बारे में कुछ सोचेंगे. ये बात कुछ समय के लिए टल गई. धीरे-धीरे वक्त बीतता गया. कहीं ना कहीं मेरे मन में भी आनंद के लिए एक जगह बन गई थी. लवली कहती हैं कि आनंद को देख कर मेरे मन में एक पॉजिटिव फीलिंग आई थी. मुझे ऐसा लगा कि मुझे जैसे लड़के की अपने लिए तलाश है वो आनंद ही हैं. मुझे ऐसा भी फील हुआ कि आनंद में वो सारे गुण मौजूद हैं जो एक पुरुष में होने चाहिए.

फिर वो समय आया जब आनंद मोहन एमएलए बने. लवली आगे बताती हैं कि उनके एमएलए बनने के बाद उनकी मां का कहना था कि अब तो मेरा बेटा एमएलए बन गया है, लायक बन गया है, तो अब मेरे बेटा का रिश्ता लवली से हो सकता है. इसी सोच के साथ एक बार फिर उनकी मां मेरे घर आनंद का रिश्ता लेकर आईं. इस बार मेरे घरवालों ने भी इस रिश्ते के लिए हामी भर दी. मेरी और आनंद की शादी का सबसे बड़ी श्रेय मेरी सास को जाता है. वो ही थीं जिन्होंने हमारी भावनाएं समझीं और हम दोनों को एक करने की हर संभव कोशिश की जो आखिरकार कामयाब भी हुई.

आनंद मोहन शिवहर के पूर्व सांसद है. आनंद मोहन एक महान स्वतंत्रता सेनानी रामबहादुर सिंह के परिवार से हैं. उनके परिवार के कई लोगों ने आजादी के लड़ाई में भाग लिया. उन्होंने आपातकाल के दौरान जेपी आन्दोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. आपातकाल में उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी. उन्हें दो वर्ष तक जेल में रहना पड़ा. मैथिली को आठवीं अनुसूचि में शामिल करने के पीछे उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई. भगत सिंह और नेल्सन मंडेला आनंद मोहन के आदर्श हैं. स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर समाज वादी नेता परमेश्वर कुंवर उनके राजनीतिक गुरु थे. आंनद मोहन सिंह ने 1980 में क्रांतिकारी समाजवादी सेना का गठन किया लेकिन लोकसभा चुनाव हार गये. आनंद मोहन 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल से विजयी हुए. आनंद मोहन ने 1993 में बिहार पीपुल्स पार्टी की स्थापना की. उनकी पत्नी लवली आनंद ने 1994 में वैशाली लोकसभा सीट उपचुनाव में जीती. आंनद मोहन बिहार पीपुल्स पार्टी के नेता थे अब यह पार्टी अस्तिव में नहीं है. आनंद मोहन बिहार के गोपालगंज के डीएम जी कृष्णाया की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.

बहरहाल परिस्थिति जो भी वो आनंद मोहन और लवली आनंद का प्यार आज भी कम नहीं हुआ है. वो दोनों आज भी एक दूसरे से बेइंतेहा प्यार करते हैं. भले ही दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हैं लेकिन मन तो उनका हमेशा साथ ही रहता है. लवली बताती हैं कि मेरा जीवन बेहद ही संघर्षशील रहा है. चाहे वो शादी के पहले का जीवन हो या शादी के बाद का. आज भी मैं संघर्ष ही कर रहीं हूं पर फिर भी मेरा और आनंद का रिश्ता ठीक वैसा हीं हैं जो शादी के समय था. उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है और आज भी हम होनों एक दूसरे से बेइंतहां मोहब्बत करते हैं.■

बाबानगरी में घोषणाएं अनेक धरातल पर सब जीरो

रणजीत झा

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में माननीयों ने घोषणाओं की झड़ी लगा रखी है. जब चाहे सार्वजनिक मंचों पर लोकलुभावन मुद्दों को लेकर घोषणा करने में माननीय जरा भी देर नहीं करते हैं परंतु पिछले पांच साल में इन घोषणाओं पर नज़र डालें तब पता चलता है कि अधिकांश का धरातल पर नामोनिशान नहीं है, कुछ योजनाओं के लिए अभी जमीन ही तलाश हो रही है, कुछ का जमीन अधिग्रहण मामला पेंच में फंसा हुआ है. सबसे दिलचस्प मामला यह है कि सन 2013 में 30 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के देवघर दौरे पर कई बहुप्रतिक्षित योजनाओं का ऑनलाईन शिलान्याश किया गया था, इन योजनाओं का भी कोई अता-पता नहीं है. इनमें सबसे चर्चित था, बाबाधाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्यू कम्प्लेक्स का निर्माण जल्द ही करना. बताना आवश्यक है कि क्यू कम्प्लेक्स निर्माण में केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की आर्थिक साझेदारी तय की गई थी जिसके तहत तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2013 में ही 25 करोड़ की राशि क्यू कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी थी. इसके तुरंत बाद तत्कालीन पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय राज्य सरकार की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के तहत क्यू कम्प्लेक्स निर्माण कार्य शुभारंभ करने देवघर पहुंचे परन्तु उक्त कार्यक्रम को सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर कार्यक्रम के मात्र कुछ ही घंटों पूर्व स्थगित कर दिया गया था. जिसके कारण केन्द्रीय पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय बिना कार्य शुभारंभ किए ही वापस चले गए थे. वापस जाने से पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने देवघर परिसदन में संवाददाता सम्मेलन में बड़ा ही दुख प्रकट करते हुए कहा था कि तत्कालीन झामुमो समर्थित एनडीए सरकार एवं गोड्डा सांसद निशिकांत दूबे की अंदरूनी कलह की वजह से ही क्यू कम्प्लेक्स निर्माण कार्य का शुभारंभ नहीं हो पाया जो बाबाधाम के लिए अत्यंत ही दुखद एवं शर्मनाक घटना साबित होगी. वास्तविकता अबतक यही है कि क्यू कम्प्लेक्स निर्माण की चर्चा अब सिर्फ अखबारों में ही कभी कभार दिखती है. किसी भी माननीय में इस बहुपतिक्षित योजना को धरातल पर उतारने की शायद वर्तमान में ईमानदारी ही नहीं दीख रही है.

दूसरी बड़ी योजना है देवघर में इंटरनेशनल हवाई अड्डा निर्माण की, जो लगभग पांच साल से अधिक समय से चर्चा में है. इस योजना में कुछ कागजी कार्रवाई जैसे हवाई अड्डा के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही है, जिसमें भी कई पेंच एवं खामियां हैं, जो कार्य प्रगति में बाधक बन रहे हैं. जैसे जिला भूअर्जन कार्यालय की ओर से सन् 1932 के खतियान को आधार बनाकर जमीन मालिक को मुआवजे हेतु नोटिस भेजा जा रहा है, जो विवाद का कारण बनता जा रहा है. सन 1932 के बाद 1952 में नया खतियान बना था जिसमें जमीन के नए भू स्वामी का नाम दर्ज है, इसे नजर अंदाज कर प्रक्रिया चल रही है, जो आगे चलकर बड़ा विवाद का कारण बन सकता है. हाल ही में धनबाद जिले से खबर आई और चर्चा का विशय रही कि वर्तमान भू स्वामी को नजर अंदाज कर पुराने खतियान के आधार पर जाली कागज बनाकर मुआवजा भुगतान करके घोटाला किया गया. इसके अलावा ऐतिहासिक गुरुकुल महाविद्यालय के मूल भवन सहित जमीन के अधिग्रहण का मामला भी विवाद का कारण है. माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि किसी भी ऐतिहासिक धार्मिक, शैक्षणिक संस्थान को तबतक जमींदोज नहीं किया जा सकता है जबतक कि इसकी मूल संस्था की स्वीकृति न मिली हो. माननीय उच्च न्यायालय, रांची की ओर से हवाई अड्डा निर्माण प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा रही है, ऐसे में सवाल है कि इतने पेचों एवं विवाद के बीच काम पूरा होने में कितना अधिक समय लगेगा.

देवघर के देवीपुर में एम्स बनने की चर्चा भी जोरों पर है. बजट से पूर्व एम्स बनवाने का श्रेय लेने की चर्चा भी जोरों पर रही, जिसके तहत बयानों से अखबार पटा रहा. सरकार का बजट पेश हुआ, इसमें देवघर में एम्स की चर्चा नहीं हुई, तब जाकर श्रेय लेने वाले माननीय थोड़ा शांत हुए. एम्स उस जमीन पर बनने की चर्चा हुई, जहां पर पूर्व में देवीपुर औद्योगिक क्षेत्र बनाने की जी तोड़ कोशिश में माननीय लगे थे, जो बाद में ठंडा पड़ता दिख रहा है. बताना आवश्यक है कि देवघर स्थित जसीडीह में एकीकृत बिहार के समय से ही 602 एकड़ भूखंड पर औद्योगिक क्षेत्र स्थित है जहां दर्जनों उद्योग जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कुछ उद्योग अंतिम सांसे गिन रहे है जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है. कई माननीय आए इसे देख तुरंत संवारने की घोषणा करने में देर नहीं करते परन्तु दो दशकों से धरातल पर सब शून्य ही है. एक स्थापित औद्योगिक क्षेत्र सड़ रहा है, दूसरा नया विकसित करने की राजनीति की जा रही है जिसे शायद जनता भी समझ रही है. राज्य बनने को 15 वर्श बीत गए परन्तु संथाल परगना में एक भी इद्योग नहीं लगा, युवा रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं.■

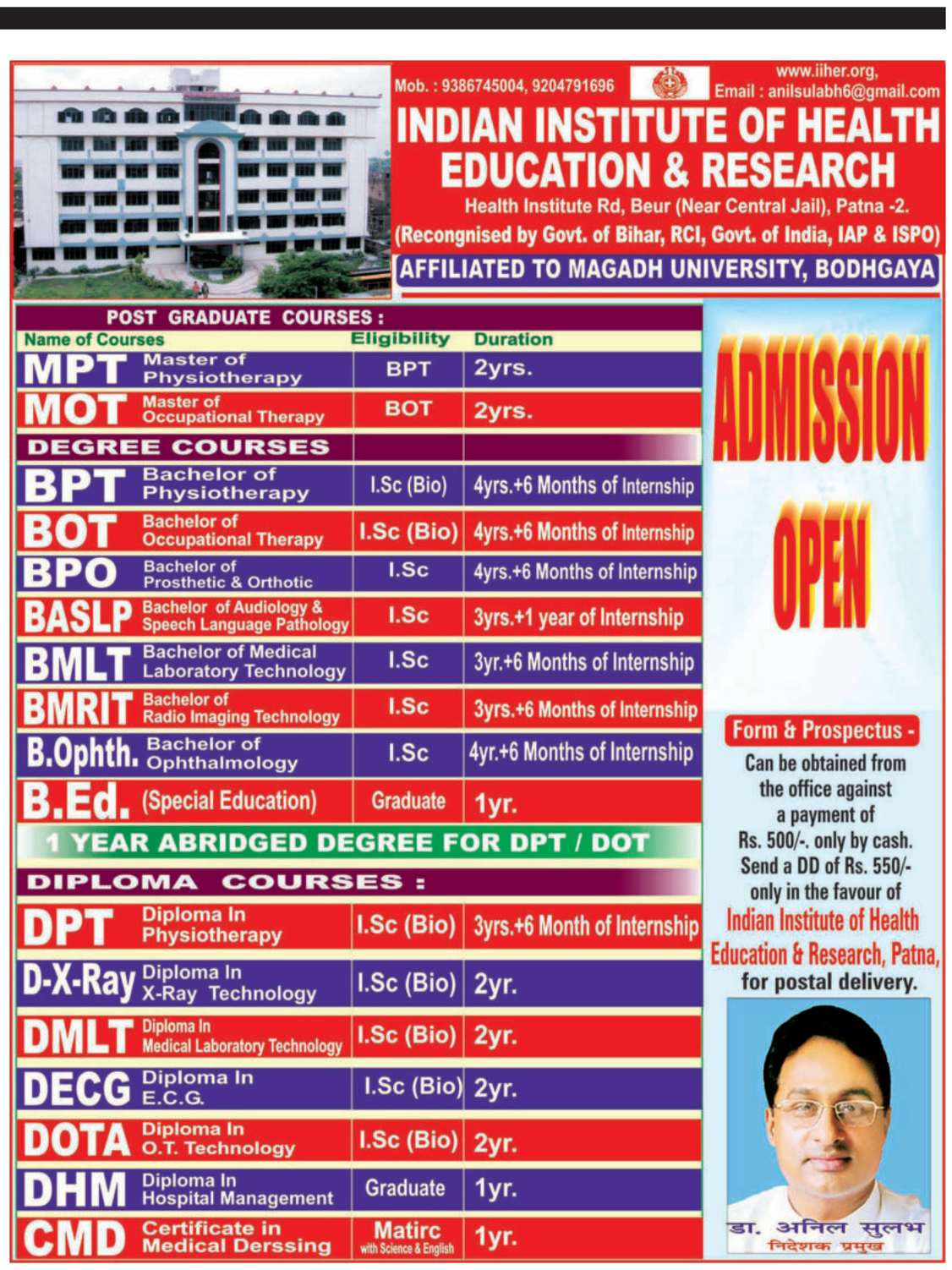

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

27 अप्रैल–03 मई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

कानून और न्याय की दुर्व्यवस्था चरम पर

अपराधी फरार जेल में निर्दोष

[उत्तर प्रदेश से 68 हजार अभियुक्तों की फरारी का मामला भी लोगों के ध्यान में तब ताजा हुआ जब सुप्रीमकोर्ट ने उनके फरार होने के बावजूद उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरार अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से मना कर रखा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी अपना वाजिब कानूनी तर्क था कि अभियुक्तों की पेशी सुनिश्चित किए बगैर आरोप-पत्र दाखिल करना उचित नहीं है. इस आदेश के कारण जांच पूरी होने के बावजूद राज्य में दो साल से फरार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल नहीं हो पा रहे थे. आप उस जांच के बारे में सोचें, जो अभियुक्तों के फरार रहने के बाद भी पूरी कर ली गई. पुलिस भी फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए माथापच्ची क्यों करे? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक-न्यायिक अराजकता का चरम यह है कि उत्तर प्रदेश में छह लाख 20 हजार 104 मामले ऐसे हैं, जिनमें आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद भी अभियुक्त अदालत में पेश नहीं हुए.]

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश में समाजवाद का राज है. वैसे तो पूरे देश में कानून और न्याय की हालत केवल शोशेबाजी तक केंद्रित होकर रह गई है. लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे भयावह है. कानून और राजनीति की खिचड़ी से प्रदेश में जो सिस्टम उत्पादित हुआ है, वह नायाब है. जिस प्रदेश में तकरीबन साठ-सत्तर हजार लोग बिना किसी न्यायिक सुनवाई के बरसों-बरस से जेलों में बंद हों, वहां की शासनिक-प्रशासनिक-न्यायिक व्यवस्था के बारे में आसानी से समझा जा सकता है. फिर इसमें हैरत क्यों जताई जाती है कि उत्तर प्रदेश से 68 हजार अभियुक्त फरार हैं! देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इस बात पर आश्चर्य जाहिर किया है कि उत्तर प्रदेश से 68 हजार से अधिक अभियुक्त फरार हैं. सुप्रीमकोर्ट ने इन फरार अभियुक्तों के खिलाफ भी अभियोग पत्र (चार्ज शीट) दाखिल करने की इजाजत दी है. लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद उन विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जो बिना किसी न्यायिक सुनवाई के कैद भोग रहे हैं. इनमें अधिकांश ऐसे कैदी हैं जो पांच और दस वर्ष से भी अधिक समय से जेल में बंद हैं. कहने के लिए वे विचाराधीन हैं, लेकिन उनपर कोई विचार नहीं किया जा रहा. उनका अपराध साबित भी हो जाए तो अधिकांश लोगों की सजा उस त्रासद अवधि से कम ही होगी, जितनी अवधि से वे जेल भोग रहे हैं. न्यायिक सुनवाई के बाद जिन विचाराधीन कैदियों को बाइज्जत रिहा किया जाएगा, उनकी जेल में कटी उम्र की इज्जत कौन सी न्यायिक व्यवस्था रखेगी? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है. बात-बहादुरी की चाहे जितनी कर ली जाए. उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का अकेला ऐसा प्रदेश है, जहां विचाराधीन कैदियों की संख्या सर्वाधिक 58,100 है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का यह आधिकारिक आंकड़ा 2013 तक का है. राष्ट्र का इतना महत्वपूर्ण महकमा इतनी स्पीड से चलता है कि उसका आंकड़ा हमेशा दो साल पीछे ही रहता है. बहरहाल, इस आंकड़े में न्यायिक-दुर्गति के हिसाब से आकलन कर लें तो संख्या साठ से सत्तर हजार पहुंच जाती है. ऐसे में अभियुक्तों की फरारी के अपने वाजिब तर्क भी हो सकते हैं.

उत्तर प्रदेश से 68 हजार अभियुक्तों की फरारी का मामला भी लोगों के ध्यान में तब ताजा हुआ जब सुप्रीमकोर्ट ने उनके फरार होने के बावजूद उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरार अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से मना कर रखा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी अपना वाजिब कानूनी तर्क था कि अभियुक्तों की पेशी सुनिश्चित किए बगैर आरोप-पत्र दाखिल करना उचित नहीं है. इस आदेश के कारण जांच पूरी होने के बावजूद राज्य में दो साल से फरार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल नहीं हो पा रहे थे. आप उस जांच के बारे में सोचें, जो अभियुक्तों के फरार रहने के बाद भी पूरी कर ली गई. पुलिस भी फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए माथापच्ची क्यों करे? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक-न्यायिक अराजकता का चरम यह है कि उत्तर प्रदेश में छह लाख 20 हजार 104 मामले ऐसे हैं, जिनमें आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद भी अभियुक्त अदालत में पेश नहीं हुए.

68 हजार फरार अपराधियों में गंभीर अपराधों में वांछित ऐसे भी शातिर अपराधी शामिल हैं, जिनके मामलों में जांच पूरी हो चुकी थी, लेकिन फरारी के चलते अदालत में आरोप-पत्र दाखिल नहीं हो सका था. सुप्रीमकोर्ट के जज दीपक मिश्रा और पीसी पंत ने 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए फरार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल करने की इजाजत दे दी. सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए पूछा कि आखिर उत्तर प्रदेश में ही ऐसा क्यों है?

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के कारण उत्तर प्रदेश में 67,816 मामलों में आरोप-पत्र नहीं दाखिल हो पाए हैं. इन सारे मामलों से जुड़े अभियुक्त फरार हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी राज्य में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की धीमी गति व अदालतों में लंबित मुकदमों की भारी संख्या पर चिंता जताते हुए 24 मई 2013 को यह आदेश दिया था कि अगर अभियुक्त अदालत में पेश न हो तो जिला अदालतों द्वारा पुलिस की ओर से दाखिल आरोप-पत्र स्वीकार नहीं किया जाए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरार अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से इसलिए मना कर दिया था, क्योंकि 6 लाख 20 हजार 104 मामले ऐसे हैं, जिनमें आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद भी अभियुक्त अदालत में पेश नहीं हुए. हाईकोर्ट ने इन वीभत्स आंकड़ों को देख कर राज्य के तत्कालीन डीजीपी और गृह विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव को आदेश दिया था कि वे इन मामलों में अभियुक्तों की संबंधित अदालतों में पेशी सुनिश्चित करें. यह भी कहा गया कि इसके लिए पुलिस को संबंधित अदालत से सम्मन या पेशी वारंट का आदेश लेने जरूरत नहीं होगी. हाईकोर्ट ने पांच फरवरी 2013 को निर्देश दिया था कि डीजीपी और प्रमुख गृह सचिव यह सुनिश्चित करें कि आरोप-पत्र दाखिल करते समय अभियुक्त अदालत में हाजिर रहे. पेशी के समय जांच अधिकारी आरोप-पत्र, एफआईआर व अन्य दस्तावेजों की प्रति तैयार रखे और उसे उसी समय मजिस्ट्रेट के जरिए अभियुक्त को सारे दस्तावेज सौंप दे. इसके लिए हाईकोर्ट ने दस्तावेजों की प्रतियां तैयार कराने के लिए सभी थानों में फोटोकॉपी मशीनें व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए थे. हाईकोर्ट का मानना था कि दस्तावेजों की प्रतियां रिसीव करने के बाद मुकदमा ठंडे बस्ते में नहीं जा पाएगा. लेकिन हाईकोर्ट के इन आदेशों की कौन सुनता है! नौकरशाही की नजर में न्यायिक सम्मान की स्थिति तो यह सामने आई कि उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने हाईकोर्ट में ही कह दिया कि इस आदेश का पालन नहीं हो सकता. गृह विभाग का कहना था कि अभियुक्त को दस्तावेजों की निशुल्क प्रति उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कानून संबंधित मजिस्ट्रेट की है, न कि जांच अधिकारी की. शासन ने यह भी रोना रोया कि फोटोकॉपी कराने के लिए महकमे के पास लोग और संसाधन नहीं हैं. इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 मई 2013 को आदेश जारी कर फरार अपराधियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल करने पर रोक लगा दी थी. नियम यह है कि अपराध की जांच पूरी कर संबंधित अदालत में अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस आरोप-पत्र दाखिल करती है. इसके बाद अदालत अभियुक्तों को पेशी के लिए सम्मन या वारंट जारी करती है. आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप-पत्र की प्रति और सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं. हाईकोर्ट ने पाया कि दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए मामला लटक जाता है और मुकदमे में देरी होती है. इसके अलावा आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद भी पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करती और अभियुक्तों की अदालत में पेशी न होने के कारण मुकदमा आगे नहीं बढ़ पाता है.

अभियुक्तों को पकड़ने और अभियोजन के पक्ष को मजबूत करने के लिए सरकार राजनीतिक घोषणाओं की तरह तमाम वायदे करती रही है, लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं किया गया. दारोगा और पुलिसकर्मियों की भर्ती के नाम पर घोटालेबाजी और जातिवादी राजनीति तो खूब होती रही, लेकिन मर्ज दूर करने पर कोई विचार नहीं हुआ. रोग बढ़ता हुआ आज नासूर बन गया है. अलग से अभियोजन निदेशालय बनाने की भी मांग उठी, लेकिन यह भी राजनीति के पेचोखम में फंसी रह गई. मामला अदालत तक गया लेकिन अदालत ने इस मामले में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी. जबकि सीआरपीसी की धारा-25 के तहत अभियोजन निदेशालय बनाए जाने का प्रावधान है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सरकार के मुंह पर तमाचा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लेकर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार के लिए लड़ने का ढोंग करने वाली सारी सामाजिक संस्थाएं और संविधान के प्रावधानों के तहत मानवाधिकार के प्रति संजीदा रहने का भाषण पढ़ने वाली सरकार के चेहरे पर 1770 की संख्या एक करारे तमाचे की तरह है. वर्ष 2013 के इस आंकड़े में और दो साल की संख्या मिला दी जाए जो तमाचे का झन्नाटा और बढ़ जाता है. चलिए 2013 के ही आंकड़े को सामने रख कर बात करें. उत्तर प्रदेश की जेलों में 1770 ऐसे लोग वर्षों से बंद हैं जो जुर्माने की रकम जमा नहीं कर पाने के कारण जेल से छूट नहीं पा रहे हैं. आप समझ ही सकते हैं कि ये ऐसे ही लोग हैं, जो जुर्माने की तुच्छ रकम भी जमा करने की औकात नहीं रखते. जेलों में बंद ऐसे 1770 मजबूर लोगों में 81 महिलाएं भी शामिल हैं. लेकिन सरकार या संस्थाएं इनके लिए आगे नहीं आती. बिहार को बदनाम तो किया जाता है, लेकिन बिहार में मात्र 13 ऐसे कैदी हैं जो जुर्माने की रकम अदा नहीं करने के कारण जेल में बंद हैं. आप उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं. ■

बिना सजा के क्यों भुगत रहे हैं जेल!

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की प्रतिष्ठा के तमाम प्रशासनिक प्रावधान लागू करने की घोषणाएं करके प्रत्येक अंतराल पर अपनी पीठ ठोकने का प्रायोजन करती रहती है. लेकिन आप हैरत करेंगे कि बिना सजा मुकर्रर हुए ही वर्षों से प्रदेश की विभिन्न जेलों में कारावास भुगत रहे 58,100 विचाराधीन कैदियों में से 2,349 महिलाएं हैं. यह आंकड़ा देखते हुए फिर ध्यान रखें कि यह संख्या वर्ष 2013 की है. दो साल में यह संख्या काफी अधिक हो गई है, लेकिन इनकी रिहाई या कानूनी तौर पर इनकी जमानत के लिए समाजवादी सरकार को सोचने की भी फुर्सत नहीं है. वैसे, जितने भी विचाराधीन कैदी जेलों में बंद हैं, उनकी जमानत के लिए त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है. लेकिन जेलों में बंद विचाराधीन कैदी वोटर नहीं हैं, इसीलिए सरकार पर क्या फर्क पड़ता है. ■

कानून की ऐसी-तैसी

वर्ष 2013 और 2014 में 66,816 फरार अभियुक्तों (क्रमशः 23,174 और 43,642) की फरारी के कारण आरोप-पत्र पेश नहीं हो पाए. अन्य कारणों से 2326 मामलों में आरोप-पत्र दाखिल नहीं हो सका. उत्तर प्रदेश में कुल दर्ज मामलों की संख्या देखें तो वर्ष 2013 में 3,64,895 मामले दर्ज हुए, जिनमें 2,24,391 मामलों में आरोप पत्र दाखिल हुए. वर्ष 2014 में कुल दर्ज मामलों की संख्या 3,91,865 थी, जिनमें 1,83,792 मामलों में आरोप पत्र दाखिल हुए. 6,20,104 मामलों में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अभियुक्त पेश ही नहीं किए गए. ■

विस्थापितों पर पुलिस ने चलाई गोलियां

प्रांजल अंशुमान

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार 14 अप्रैल को एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के राजनीतिक समारोहों के आयोजन में लगी थी तो दूसरी तरफ प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के तहत विस्थापित गरीब-गुरबों पर पुलिस गोलियां दाग रही थी. सोनभद्र के दुद्धी क्षेत्र में बांध बनाने के लिए विस्थापित किए गए लोगों पर पुलिस की फायरिंग से 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इसमें से एक की हालत चिंताजनक है. पुलिस अत्याचार के विरोध में हुई पत्थरबाजी में पुलिस के छह लोग भी जख्मी हुए हैं.

सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के तहत बांध निर्माण से विस्थापित होने वाले सैकड़ों परिवार एक महीने से आंदोलन कर रहे हैं. क्रमिक अनशन कर रहे विस्थापित परिवार 14 अप्रैल की सुबह बांध पर काम शुरू होता देख कर भड़क उठे और मजदूरों से कहा कि काम बंद करा दिया. सूचना मिलते ही वहां पुलिस फोर्स पहुंच गई और काम शुरू कराने के लिए बल प्रयोग करना शुरू कर दिया. इससे स्थिति बिगड़ती चली गई. नाराज लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने पुलिस पर लाठी-डंडे से भी हमला कर दिया. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो स्थिति और भी बिगड़ गई. भीड़ के हमले में दुद्धी कोतवाल कपिलदेव जख्मी हो गए. उन्हें सिर और हाथ में चोटें आईं. इसके बाद पुलिस ने उग्र भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग में करीब दो दर्जन लोग जख्मी हुए, जिसमें अकलू (45) की हालत चिंताजनक है. इसके अलावा कई ग्रामीण और पुलिसकर्मी पथराव-लाठीचार्ज में भी घायल हुए. घायलों को वाराणसी के अस्पतालों में भर्ती किया गया है. मुख्यालय से कई थानों की फोर्स और पीएसी के साथ एसपी शिवशंकर यादव और प्रभारी जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह के मौके पर पहुंचने के बाद भी विस्थापित वहां से नहीं हटे. वे निर्माण स्थल को घेरकर खड़े रहे और फोर्स भी कुछ दूर पर सामने डटी रही.

कनहर बांध परियोजना में सोनभद्र के 11 गांवों के और बिहार-झारखंड के नौ गांवों के करीब 15 हजार ग्रामीण विस्थापित हो जाएंगे. 1976 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था. उस समय इस परियोजना की लागत 27 करोड़ थी. 2015 में इस परियोजना की लागत बढ़कर 2200 करोड़ रुपये हो गई है. प्रशासन की ओर से कुछ विस्थापितों को मुआवजा बांटा गया, लेकिन ज्यादातर अब भी विरोध में खड़े हैं. 14 अप्रैल को काम दोबारा शुरू किए जाने के कारण हंगामा हुआ. ताजा स्थिति यह है कि कनहर बांध पर काम बंद है. उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के हजारों लोग धरना पर बैठे हैं. इस बांध से तीन राज्यों के करीब 80 गांव डूबेंगे, जिनमें अकेले छत्तीसगढ़ के ही 16 गांव हैं. बांध के डूब क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हाथी अभयारण्य भी शामिल है. छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में गीधा थोधा नामक स्थान से निकलने वाली कनहर, सोन नदी की सहायक नदी है और वर्षा ऋतु में अपने तीव्र बहाव की वजह से देश की खतरनाक नदियों में से एक हो जाती है. कनहर आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार विस्थापितों की सही संख्या और डूब क्षेत्र का सही सर्वेक्षण नहीं करा रही है. ऐसे में विस्थापितों की पहचान और उन्हें मुआवजे की रकम देने का काम कैसे शुरू कर दिया गया, यह गंभीर सवालों के घेरे में है.

बांध से कुछ फायदे भी हैं

कनहर परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि बांध की ऊंचाई पूर्व की भांति 39.90 मीटर व चौड़ाई 3.24 किमी है. इससे 0.15 मिलियन एकड़ फिट जल उपयोग कर 121 किमी मुख्य नहर एवं 190 किमी लंबे रजवाहों के माध्यम से कुल 35467 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है. इससे उत्तर प्रदेश के 108 गांवों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज-बलरामपुर के गांवों को भी लाभ मिलने की बात कही जा रही है.

उल्लेखनीय है कि सोनभद्र की कनहर परियोजना का प्रसंग केवल विस्थापन की आशंका से ही नहीं सम्बद्ध है, बल्कि यह अत्यधिक ढिलाई और आर्थिक घोटाले से भी जुड़ा है. जमीनी सच्चाई यही है कि कनहर परियोजना के एक तरफ अधर में लटका बांध-निर्माण है तो दूसरी तरफ करीब एक लाख आदिवासी ग्रामीण आबादी है, जो अपने पारम्परिक निवास से बेदखल हो रही है. यह बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की कनहर नदी पर प्रस्तावित है, लेकिन इससे बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य सीधे-सीधे प्रभावित हो रहे हैं. कनहर सोन नदी की सहायक नदी है. सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, इसका क्षेत्रफल 6788 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 3792.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जंगल से घिरा है. सोनभद्र की सीमाएं उत्तर-पूर्व में बिहार से, पूर्व में झारखंड से, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तथा चंदौली जिलों से मिलती हैं. सोनभद्र की 70 फीसदी आबादी आदिवासी है जिसमें गोंड, करवार, पन्निका, भुईयां, बड़गा, चेरों, घासिया, धरकार और धौनार जातियां आती हैं. अधिकतर ग्रामीण आदिवासी अपनी जीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं. वे जंगल से तेंदूपत्ता, शहद, सूखी लकड़ियां और जड़ी-बूटियां इकट्ठा कर उन्हें बाजार में बेचते हैं. कुछ के पास छोटी जोतें भी हैं जो ज्यादातर चावल और कभी-कभी सब्जियां पैदा करते हैं. इस इलाके में रहने वाले बहुत से आदिवासियों को रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट के अनुच्छेद-4 तथा अनुच्छेद-20 ने उनकी जमीन और वनाधिकार से वंचित कर रखा है.

सोनभद्र जिला विकास के उस मॉडल का शिकार है जिसे आजादी के बाद अपनाया गया. पूरा सोनभद्र औद्योगिक प्रदूषण और विस्थापन की मार से आक्रांत है. कनहर बांध परियोजना भी विस्थापन का एक और अध्याय जोड़ रहा है. कनहर बहुद्देशीय परियोजना का असर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, छत्तीसगढ़ के सरगुजा और झारखंड के गढ़वा जिले पर सीधे तौर पर पड़ेगा. बांध तैयार होने के बाद इसका जलक्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर का होगा और तीन राज्यों के करीब 80 गांव इसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाएंगे. इससे तकरीबन एक लाख ग्रामीण-आदिवासी आबादी हमेशा के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनों से उजड़ जाएगी.

कनहर बहुद्देशीय परियोजना को सितंबर 1976 में केंद्रीय जल आयोग की अनुमति मिली थी और इसकी प्रारंभिक अनुमानित लागत 27 करोड़ रुपये आंकी गई थी. 1979 में इसे 55 करोड़ रुपये के साथ नए सिरे से तकनीकी अनुमति मिली. छत्तीसगढ़, जो उस समय मध्यप्रदेश था, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच पानी और डूब क्षेत्र को लेकर होने वाले विवाद की अनदेखी करके परियोजना को अनुमति दी गई और अंततः उसकी लागत 69 करोड़ रुपये बताई गई. तीनों ही प्रदेशों के पर्यावरण मंत्रालयों ने इस इलाके में होने वाले भयानक नुकसान की आशंका को नजरंदाज किया और कोई भी ऐसा सर्वेक्षण नहीं कराया जो परियोजना द्वारा पर्यावरण और आबादी पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का ठीक-ठाक आकलन करता हो. शुरुआती अध्ययन के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि तकरीबन एक लाख पेड़, 2500 कच्चे घर, 200 पक्के घर, 500 कुएं, करीब 30 स्कूल और कुछ अन्य इमारतें डूब क्षेत्र में आएंगी. 2015 में आंकड़ों की यह तस्वीर और बदल गई होगी. इस बांध परियोजन के शिलान्यास के बाद एक एकड़ का 22 सौ रुपये की दर से मुआवजा दिया गया था, जो भीख से भी कम था. जमीन के बदले जमीन देने का वादा किया गया था, लेकिन जमीन किसी को भी नहीं मिली. बाहर से मजदूर बुलाए गए, स्थानीय लोगों को मजदूर के लायक भी नहीं समझा गया. 1976 में शिलान्यास के बाद काम कछुए की चाल से शुरू हुआ, लेकिन बंद अधिक रहा. कभी भी लगातार काम नहीं चला, लेकिन सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग के दस्तावेज पर काम का खर्च लगातार दिखाया जाता रहा. 1984 में काम बिल्कुल ही रुक गया. 1989 में काम फिर शुरू हुआ और 16 परिवार उजाड़ दिए गए. इसके बाद फिर दो दशक से छिटपुट काम छोड़ कर निर्माण कार्य बंद ही रहा. करोड़ों के उपकरण धूप और धूल में बर्बाद हो गए. इस रुकी हुई परियोजना का 15 जनवरी 2011 को फिर से तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने शिलान्यास कर दिया. काम फिर भी रुका ही रहा. समाजवादियों के सत्ता में आने पर सात नवम्बर 2012 को फिर से एक शिलान्यास हुआ. कनहर बांध के स्पिल-वे का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए नया शिलान्यास प्रदेश के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने किया. इस तरह कनहर परियोजना का शिलान्यास दर शिलान्यास होता रहा, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ और गांव वाले आशंकाओं में जीते रहे. बजट बनता रहा, पैसा खर्च होता रहा और लोग अर्ध विस्थापन में जीने पर मजबूर होते रहे. ■

feedback@chauthiduniya.com

समाजवाद और अम्बेडकरवाद का सहारा

वैष्णवी वंदना

समाजवादी पार्टी का लोहियावाद से काम नहीं चला तो विधानसभा चुनाव के पहले उसे अम्बेडकरवाद का सहारा लेने की सुध आई. दलितों का हाल भी मुसलमानों जैसा होने वाला है, जिन्हें राजनीतिक पार्टियों ने महज वोटों की गिनती में तब्दील कर दिया है. सारी राजनीति इन दो समुदायों की गिनती अपने पक्ष में करने में लगी हुई है. इसीलिए सपा के साथ-साथ भाजपा ने भी अम्बेडकर को साधना शुरू कर दिया है. भाजपा की रणनीति अम्बेडकर को शास्त्रीयता और राष्ट्रीयता के उनके विचार के आधार पर उन्हें क्रमशः अपने महापुरुषों की श्रृंखला में शामिल करने की है. ताकि देशभर के दलित स्थायी तौर पर भाजपा के साथ मन से रिश्ता बना पाएं. बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी दलितों को साथ रखने के प्रयासों का कोरम पूरा कर रही है. बसपा की स्थिति कांग्रेस से थोड़ी बेहतर है, क्योंकि मायावती के कारण उनकी जाति का कुछ समर्थन बसपा को प्राप्त है. उत्तर प्रदेश में खास तौर पर दलितों को अपने साथ लेने या अम्बेडकर को अपनाने की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ दिया है. तरक्की में आरक्षण के मसले पर विरोधी स्टैंड लेने के कारण समाजवादी पार्टी से दलित समुदाय थोड़ा बिदका है. इसमें भाजपा ने मौन रख कर और अपने कुछ सांसदों को आगे कर दलितों की सहानुभूति प्राप्त की है.

इसे काउंटर करने के लिए सपा सरकार ने इस बार अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए जिलों में सरकारी धन झोंक दिया. अखिलेश सरकार ने अम्बेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी. उन्होंने अम्बेडकर निर्वाण दिवस 6 दिसम्बर को भी सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया. हालांकि, सत्ता में आने पर सपा सरकार ने ही इसे रद्द कर दिया था. मायावती सरकार ने अम्बेडकर और कांशीराम दोनों के निर्वाण दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए थे. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव ने आरक्षित क्षेत्र से चुने गए सपा विधायकों के दबाव में यह फैसला लिया है. बकौल मायावती, दलित विधायकों ने अखिलेश पर दबाव बनाया था कि अम्बेडकर के नाम पर बंद की गई योजनाएं और अवकाश शुरू किए नहीं किए गए तो वे बसपा में चले जाएंगे. लेकिन केवल लोग इसे मायावती की महज सियासत बताते हैं.

लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीत पाने वाली बसपा की मुखिया ने अपने दलित जनाधार को बिखरने से बचाने की कोशिश में कांग्रेस और भाजपा समेत सभी दलों पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया. अम्बेडकर जयंती पर विभिन्न दलों द्वारा आयोजित किए जा रहे समारोहों और कार्यक्रमों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कांग्रेस, भाजपा और सपा का अम्बेडकर प्रेम राजनीति से प्रेरित है. बसपा मुखिया ने कहा कि कांग्रेस ने वर्ष 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में मुंबई से चुनाव में उतरे

अम्बेडकर के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करके और धन बल से उन्हें हरा दिया था. यदि कांग्रेस के मन में अम्बेडकर के प्रति जरा भी सम्मान होता तो वह उन्हें निर्विरोध चुनाव जितवाती. आजादी के बाद लगातार सत्ता में रही कांग्रेस सरकार ने अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया. मायावती ने दावा किया कि वर्ष 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की गठबंधन सरकार ने अम्बेडकर को बसपा के समर्थन के बदले में भारत रत्न दिया था. मायावती नेयह भी दावा किया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने उनके ही समर्थन के बदले मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी. बसपा संस्थापक कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग करती रहीं मायावती ने दलित समुदाय को आगाह करने के अंदाज में कहा कि हो सकता है कि केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपानीत राजग सरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दलित मतदाताओं को लुभाने के लिए कांशीराम को भारत रत्न सम्मान दे दे और दिल्ली में अलीपुर मार्ग पर बाबा साहब ने जिस बंगले में अंतिम सांस ली थी, उसे उनका स्मारक घोषित कर दे. मगर इससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है. मायावती ने भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए मुसलमानों से बसपा को एकजुट समर्थन की अपील करते हुए आरोप लगाया कि सपा और भाजपा अपनी खराब स्थिति को देखते हुए आपस में साठगांठ करके साम्प्रदायिक दंगे करवा सकते हैं. प्रोन्नति में आरक्षण का अधिकार खत्म कर देने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश का जिक्र करते हुए मायावती ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेसनीत संप्रग सरकार ने मामले की सही ढंग से पैरवी नहीं की थी और अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार इस कानून के तहत प्रोन्नति पाए अधिकारियों की पदावनति करने जा रही है.

इस पर भाजपा ने कहा कि खुद बसपा सुप्रीमो मायावती अम्बेडकर जयंती का राजनीतिकरण करती हैं. प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि विरोधियों को अम्बेडकर जयंती मनाने के नाम पर राजनीति न करने की सलाह देने वाली मायावती खुद गैर सियासी मंच से मुसलमानों को गुमराह न होने और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट करने की बात करती नजर आती हैं. भाजपा ने पूछा कि क्या महापुरुषों पर किसी दल विशेष का अधिकार है. भाजपा का प्रयास है कि बाबा साहब के जन्म दिवस पर उनकी नीतियों व उनके विचारों और समाजिक समरसता के लिए किए गए कार्यों से समाज को अवगत कराया जाए. इसलिए भाजपा ने डॉ. अम्बेडकर के जन्म दिवस को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया. भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर छूआछूत जैसी कुप्रथा को दूर करने के लिए लिए प्रयासरत है, जबकि मायावती अम्बेडकर को एक दायरे में बांध कर रखना चाहती हैं. ऐसे में हर कोई समझ सकता है कि अम्बेडकर के विशाल कद को कौन छोटा कर रहा है. भाजपा ने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों में अपना जनाधार खो चुकी बसपा, अम्बेडकर जयंती को लेकर सस्ती राजनीति कर रही है. लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने लगभग एकतरफा जीत दर्ज की थी. लिहाजा, उसे दलितों को वोट बैंक के रूप में रिझाने की कोई जरूरत नहीं.

भाजपा दलितों को समरसता के साथ रिश्ते में जोड़ रही है. खिचड़ी भोज का आयोजन भी इसी विचार से हुआ, जिसमें पार्टी नेताओं ने दलित समुदाय के लोगों के घरों में जाकर भोजन किया. गृहमंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने पहले मैला ढोने का काम करने वाली महिलाओं के साथ खाना खाया. खास बात यह है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को चुना. बसपा के लिए परेशानी इसी बात को लेकर है कि 14 अप्रैल का जो दिन बीते कई वर्षों से बसपा के लिए खास होता था, वह अब भाजपा के लिए विशेष बनता जा रहा है.

दलित समाज से जुड़े लोग भी इस बात से इन्कार नहीं करते कि पिछले लोकसभा चुनावों से पहले की राजनीति ने दलितों की सोच को बदला है. जमीनी स्थिति देखें तो दलितों और भाजपा के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं. दूसरी ओर बसपा का वोट बैंक 2012 विधानसभा चुनावों के बाद लगातार खिसकता जा रहा है. 2007 के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में 207 सीटों के साथ बहुमत पाने वाली पार्टी 2012 के चुनावों में 80 सीटों पर सिमट गई. जबकि 2014 के लोकसभा चुनावों में एक भी सीट न जीत पाने के बाद बसपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खतरे में पड़ चुका है. ऐसे में भाजपा की बढ़त अब बसपा के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है.

शिवपाल ने अम्बेडकर पर लिमये की पुस्तक का विमोचन किया

बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर समाजवादी नेता और इंडो-मॉरीशस सोशलिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने प्रख्यात समाजवादी चिन्तक मधु लिमये की डॉ. अम्बेडकर एक चिन्तन पुस्तक के नेपाली संस्करण का विमोचन समाजवादी पार्टी मुख्यालय स्थित सभागार में किया. पुस्तक के अनुवादक पद्म बहादुर थापा हैं, जिसका प्रकाशन पर्यावरणीय लोकतंत्र पर दक्षिण एशियाई संवाद ने किया है. इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी, समाजवादी पार्टी के महासचिव अरविन्द सिंह गोप व समाजवादी बौद्धिक व चिन्तन सभा के अध्यक्ष दीपक मिश्र भी मौजूद थे.

शिवपाल यादव ने बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व, कृतित्व और महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि बाबा साहब के कई कार्यक्रमों को समाजवादियों ने आगे बढ़ाया. अछूतोद्धार जैसे कार्यक्रम को लोकबंधु राजनारायण ने आगे बढ़ाया और उनके विचारों को सबसे अच्छी पुस्तकों में उल्लेखनीय किताबें महान समाजवादी विचारक मधु लिमये व मोहन सिंह ने लिखा है. बाबा साहब जितने बड़े समाजसुधारक थे उतने ही महान अर्थशास्त्री भी थे. लोहिया जी और बाबा साहब के आर्थिक विचारों में काफी समानताएं हैं. दोनों एक दूसरे के अच्छे सहयोगी थे. भीमराव अम्बेडकर देश में राज्य समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे. बाकी दल सिर्फ जुबान से अम्बेडकरवादी बनते हैं, समाजवादी मनसा-कर्मणा अम्बेडकर के सपनों के भारत के निर्माण में लगे हुए हैं.

दिल्ली से लौट आए अखिलेश

अम्बेडकर जयंती को लेकर सपा सरकार ने अपने कई फैसले पलट दिए. सरकार ने अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को छुट्टी की पुरानी घोषणा फिर से बहाल कर दी. 2012 के बाद सपा की सरकार बनने के बाद यह छुट्टी रद कर दी गई थी. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार 14 अप्रैल को जर्मनी के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन बाबा साहब की जयंती के लिए दिल्ली से लौट आए. मायावती के अम्बेडकर पार्क पहुंचने से पहले उन्होंने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर छुट्टी की घोषणा कर दी. इसके बाद उन्होंने अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अम्बेडकर महासभा के दफ्तर में कहा कि बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर ही गैर बराबरी को समाप्त किया जा सकता है. इसके बाद अखिलेश जर्मनी जाने के लिए फिर दिल्ली रवाना हो गए. ■

feedback@chauthiduniya.com

अखिलेश की जर्मनी यात्रा के मायने

चौथी दुनिया ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जर्मनी जाते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी जर्मनी जाने का अपना कार्यक्रम फाइनल कर दिया. जबकि मार्च महीने में ही उनके जर्मनी जाने का कार्यक्रम था, जिसे उन्होंने टाल दिया था. प्रधानमंत्री द्वारा भारतवर्ष में निवेश का रास्ता प्रशस्त कर आने के बाद अखिलेश ने उसके फायदे का कुछ अंश उत्तर प्रदेश ले आने के इरादे से जर्मनी जाना फौरन ही तय कर लिया. अखिलेश यादव ने जर्मनी के उद्यमियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है. उन्होंने वहां कहा कि प्रदेश में निवेश करने वाले उद्योगपतियों व उद्यमियों को राज्य सरकार द्वारा सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. मुख्यमंत्री ने जर्मनी के हनोवर तकनीकी एवं इंजीनियरिंग मेले में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. मुख्यमंत्री अपने साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर हनोवर मेले गए. उनके साथ प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन भी थे. उन्होंने हनोवर मेले में लगा उत्तर प्रदेश पैवेलियन भी देखा. राज्य में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास की अनेक परियोजनाओं पर रौशनी डालते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जर्मनी सहित तमाम देश के निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी कारोबारी गतिविधियों को बढ़ाने की तमाम सम्भावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश को सुगम बनाने के मकसद से अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति के साथ-साथ अन्य नीतियों को लागू किया गया है. प्रदेश में प्राकृतिक एवं दक्ष मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है. निवेशक ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और क्लीयरेन्स भी हासिल कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बाजार भी है. इसके दृष्टिगत ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए यूपी में विकास के अनेक अवसर मौजूद हैं. उन्होंने जर्मनी के ऑटोमोबाइल निर्माताओं को प्रदेश के विकास में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का सबसे लम्बा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन है, जिसके आस-पास खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र में 100-100 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित कर रही है. इसी प्रकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रदेश सरकार गम्भीरता से कार्य कर रही है. अखिलेश ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर तथा सौर ऊर्जा से जुड़ी जर्मन कम्पनियों के लिए उत्तर प्रदेश एक अच्छा गंतव्य साबित होगा. अखिलेश के साथ जर्मनी गए प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री अभिषेक मिश्रा, मुख्य सचिव आलोक रंजन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव महेश गुप्ता, विशेष सचिव कंचन वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव जीएस नवीन कुमार और मुख्य सचिव के स्टाफ अफसर एसएन श्रीवास्तव भी मौजूद थे.

मुख्यमंत्री ने जर्मनी में उर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग और निवेश को लेकर वहां के उद्योगपतियों के साथ बैठक की और लग्जरी कार बनाने वाली दुनिया की जानी मानी कंपनी बीएमडब्लू का कारखाना भी देखने गए. प्रतिनिधिमंडल ने बीएमडब्लू के मुख्य वित्तीय अधिकारी रोजर रूडन से भी मुलाकात की और कारों में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर चर्चा की. मुख्यमंत्री ने हनोवर में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जर्मन भाषा में एक विशेष वेबसाइट (WWW.UPSTEIGEND.IN) भी लॉन्च की. मुख्यमंत्री के साथ गए प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी से सोलर पावर के क्षेत्र में भी उच्चस्तरीय तकनीकि सलाह और सहायता लेने के बारे में भी बातचीत की. उत्तर प्रदेश में सोलर रूफ टॉप सिस्टम स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है. प्रदेश की ओर से वहां एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया और चुनिंदा कंपनियों के सीईओ व अन्य अधिकारियों को सूबे में निवेश के अवसरों की जानकारी दी.

हनोवर मेले में उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित भव्य पैवेलियन की काफी सराहना की गई है. इस पैवेलियन का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी किया था. मर्केल ने इस अवसर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्चरिंग की काफी सम्भावनाएं हैं. गौरतलब है कि पैवेलियन में प्रदर्शित बैनर व पोस्टर आदि जर्मन भाषा में भी लगाए गए थे. प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाना है. साथ ही, जर्मनी की संस्थाओं, औद्योगिक संस्थानों और कम्पनियों से रिश्तों को मजबूत बनाते हुए सौर व नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, क्लीन टेक्नोलाजी, शोध एवं नवोन्मेष, कौशल विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में सहयोग और निवेश को आमंत्रित करना है. उल्लेनीय है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जर्मनी के पास उच्च तकनीक उपलब्ध है और उत्तर प्रदेश भी इस क्षेत्र के विकास को लेकर बेहद गम्भीर है. राज्य सरकार छतों पर सौर संयंत्र लगाए जाने की सम्भावनाओं पर भी विचार कर रही है. हनोवर मेले में उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश के अवसर पर एक सत्र भी आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य सचिव आलोक रंजन सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. इस सत्र में सौर ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और क्लीन टेक्नोलाजी के क्षेत्र में तकनीकी हस्तान्तरण जैसे मुद्दों पर चुनिन्दा प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श हुआ. विश्व प्रसिद्ध हनोवर मेले में पूरे संसार से व्यापार, तकनीक, उद्योग, विज्ञान से जुड़ी हस्तियां और नीति निर्माता शामिल हुए, जिनकी संख्या लगभग दो लाख थी. इसमें भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित 300 कम्पनियां सम्मिलित हुईं. 21 बिलियन अमरीकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ जर्मनी भारत का 6वां सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है. दोनों देशों के कारोबारी सम्बन्ध मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, सेवा, परमाणु रियेक्टर, निर्माण आदि क्षेत्रों में हैं.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मार्च महीने में जर्मनी में ट्रैवेल ट्रेड शो में हिस्सा लेने जाना था, लेकिन उन्होंने उसे टाल दिया था. उस समय अखिलेश ने अपने गांव सैफई में रहना अधिक उपयुक्त समझा था. इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जर्मनी जाने के फौरन बाद वहां जाने का फौरन कार्यक्रम बनाए जाने पर सवाल उठ रहे हैं. मार्च में उन्होंने अपनी जगह पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह को जर्मनी भेज दिया था. उनके साथ पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव और महानिदेशक अमृत अभिजात भी जर्मनी गए थे. इससे पहले मुख्य सचिव आलोक रंजन पहले से बर्लिन में होने वाले ट्रेवेल ट्रेड शो में भाग लेने चले गए थे. ट्रेवेल शो के बारे में भी कहा गया था कि इससे यूपी को दुनिया में पर्यटन के नक्शे पर दिखाने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा. विपक्षी इस तरह की विदेश यात्राओं को सरकारी धन का अपव्यय बताते हैं.

किसान बदहाल, सीएम कर रहे हैं विदेश टूर

उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जर्मनी जाने पर गंभीर सवाल उठाए हैं. प्रदेश के सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव की जर्मनी यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने सोशल वेबसाइट पर सवाल दागे हैं कि यूपी में किसानों की फसल बर्बादी की वजह से आपदा लागू की गई है, मुआवजा बंटने में अनियमितताएं और राहत में ढिलाई पर रोज चर्चा हो रही है, ऐसे में किसानों को इस हाल में छोड़कर जर्मनी जाने का क्या यह सही वक्त था? प्रमुख सचिव का कहना है कि मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव और पूरा प्रशासनिक अमला जर्मनी गया, लेकिन यह वक्त सही नहीं था.

आईएएस अधिकारी ने प्रवासी भारतीय दिवस में अखिलेश यादव के शरीक नहीं होने पर भी आपत्ति जताई है. डॉ. सिंह ने इस बार किसानों की बेबसी को लेकर सवाल खड़े किए कि सरकार ऐसी स्थिति में क्या कर रही है. उनका कहना है कि किसान कंगाल हो गए. अनगिनत किसानों ने जान दे दी और वे कह रहे हैं कि किसानों की आत्महत्या फसल बर्बादी से नहीं हो रही है. आईएएस अफसर ने टिप्पणी की है कि अगर जर्मनी जाना इतना जरूरी था तो अहमदाबाद में प्रवासी भारतीय दिवस में वे क्यों नहीं गए थे. वहां तो यूपी ने पैसा भी खूब खर्च किया था, वह ज्यादा महत्वपूर्ण भी था. आईएएस अफसर ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के उस बयान पर भी टिप्पणी की है जिसमें उन्होंने सवाल उठाए हैं कि विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सांसद-विधायक समेत तमाम जनप्रतिनिधि कमीशन ले रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

उप चुनाव

भाजपा की हार कांग्रेस को बहुमत

रेनू शर्मा

उत्तराखंड में हुए भगवान पुर उपचुनाव में भाजपा नकार कर धर्मनगरी हरिद्वार की जनता ने एक बार फिर कांग्रेस के पाले में खड़ी दिखी. कांग्रेस की प्रत्याशी ममता राकेश ने जनता की सहानुभूति से भाजपा के प्रत्याशी राजपाल को लगभग 36 हजार, 909 मतों से करारी शिकस्त दी. चुनाव में शानदार जीत प्राप्त करने वाली कांग्रेस नेता श्रीमती ममता राकेश ने कहा कि यह जीत हमारे पति स्व. सुरेन्द्र राकेश के जनसेवा का परिणाम है. अब जनता का कर्ज हम पर है जिसे मैं आनापाई में अदा करूंगी. उन्होंने सब के प्रति आभार व्यक्त किया. इस जीत पर राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत की खुशी का ठिकाना नहीं है. उन्होंने इस मिली जीत को मिशन 2017 से जोड़ते हुए कहा कि यह जीत 2017 की रणनीति का एक हिस्सा है, कांग्रेस नेता ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा यह जीत ही भावी राजनीति की आधारशिला सिद्ध होगी. इस उप चुनाव में मिली शानदार जीत के साथ हरीश रावत सरकार ने राज्य में बहुमत का आकड़ा भी पार कर लिया. उल्लेखनीय है कि सांसद निशंक के मन के प्रत्याशी को लेकर भाजपा में विरोध उतपन्न हुआ, जो भाजपा प्रत्याशी पर भारी पड़ा. वैशाखी के सहारे 2012 में सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस ने 2015 में इस जीत के साथ ही पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है. प्रदेश में कांग्रेस का सितारगंज विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ जीत का क्रम भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र तक जारी रहा. कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिलाने में भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही. इस जीत के साथ ही 70 सदस्यीय विधानसभा मे कांग्रेस ने अपने दम पर 36 सीटों के साथ बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में लगातार चौथी जीत दर्ज की है. वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा से महज एक सीट ज्यादा लेकर सत्ता तक पहुंची कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत का आंकड़ा प्रदेश में हुए सभी विधानसभा उपचुनावों में जीत हासिल कर पाया है. विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 32 और भाजपा को 31 सीटें मिली थीं. फरवरी 2014 में बहुगुणा की विफलता के बाद हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया. हरीश के लिए उनके करीबी विधायक हरीश धामी ने धारचूला विधानसभा सीट छोड़ी थी. पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों में दो भाजपा विधायकों, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और अजय टम्टा के सांसद बन जाने से डोईवाला और सोमेश्वर विधानसभा सीटें भी रिक्त हो गयीं. गत जुलाई में इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा को पटखनी देते हुए तीनों सीटें पर अपना कब्जा कर लिया. जिनमें से दो सीटें उसने भाजपा से छीनी हैं. जबकि धारचुला सीट से मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव जीते थे. जिसके चलते विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों की संख्या 35 तक पंहुच गई थी. लेकिन अब कांग्रेस भगवानपुर सीट जीतने के बाद पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है. अब तक कांग्रेस को बसपा, उक्रांद और निर्दलीय विधायकों वाले प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चे के दम पर सदन में बहुमत था. हालांकि निर्दलीय विधायकों में से एक हरीश चंद्र दुर्गापाल ने विगत दिनों कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी. भगवानपुर में भाजपा की हार के बाद अब देखना दिलचस्प होगा की शीर्षनेतृत्व को जीत का दिलाशा देने वाली प्रदेश भाजपा क्या जवाब देती है. इस उपचुनाव में हार के बाद भाजपा नेताओं को डर सताने लगा है कि ऐसे में उनका मिशन 2017 कैसे पूरा होगा.

यह प्रश्न भाजपा हाईकमान ही नहीं बल्कि संघ के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को भी एक बार फिर से सोचना होगा. जिनके स्वयंसेवक भगवानपुर उप चुनाव में नामांकन के एक पखवाड़े पहले से ही जमे हुए थे. प्रदेश में निकाय व पंचायत चुनाव भी हुए जिसमें भी भाजपा को कोई सफलता नहीं मिल पायी. भगवानपुर में हार की सबसे बड़ी वजह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आपसी गुटबाजी ही रही है. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बार-बार हरिद्वार के प्रति प्रेम जताने वाली केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती भी भगवानपुर में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार में नहीं आईं. प्रचार में वरिष्ठ नेताओं ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और भगवानपुर को भगवान भरोसे ही छोड़ दिया. सबसे बड़ी दिक्कत कार्यकर्ताओं के सामने पैसे की तंगी रही. संगठन की ओर से एक चवन्नी की भी मदद कार्यकर्ताओं को नहीं मिली. इस उपचुनाव में केवलरमेश पोखरियाल निशंक ही इस उपचुनाव में नजर आए और उन्होंने भाजपा उम्मीदवार को जिताने का हरसंभव प्रयास किया. चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अपने हाईकमान को अंधेरे में रखे रहा कि भगवानपुर उपचुनाव में भाजपा भारी मतों से विजयी होगी. सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि बीते उप चुनावों की रणनीति भी इन्हीं चंद नेताओं तक सिमट कर रह गयी. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत का कहना है कि सरकारी मशीनरी भगवानपुर में लगी रही. इसके अलावा सहानुभूति लहर भी रही. नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट का मानना है कि भगवानपुर उपचुनाव ममता राकेश की निजी जीत है. इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

फर्जी आईएएस मामले की जांच में नया मोड़

राजकुमार शर्मा

मसूरी स्थित लालबहादुर शास्त्री अकादमी में फर्जी आईएएस अधिकारी रूबी चौधरी के मामले में नरेन्द्र मोदी मंत्री मंडल के कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान की संलिप्तता सामने के आने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है. मंत्री के माध्यम से अकादमी तक पहुंच कर अकादमी में वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी साजिश का शिकार बनाने वाली फर्जी आईएएस अधिकारी रूबी चौधरी जांच में अपने मित्रों को भी फसाने का दाव फेक कर हम तो डूबेगें ही सनम तुमको भी ले डूबेगें की कहावत को चरितार्थ कर रही है. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में फर्जी आईएएस का मामला केंद्र सरकार के गले की फांस बन सकता है. एक केंद्रीय मंत्री पर पहले से ही सवाल उठ रहे थे. इस बीच रूबी चौधरी के सिर पर एक अन्य केंद्रीय राज्यमंत्री का हाथ होने का खुलासा हो चुका है.

रूबी पहली बार सितम्बर 2014 में जिस लग्जरी कार से मसूरी स्थित अकादमी पहुंची थी, वह मेरठ की है. अकादमी के सीसीटीवी फुटेज में कार नजर भी आ रही है. बताया जा रहा है कि यह कार मेरठ-मुजफ्फरनगर क्षेत्र के रहने वाले मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान इस्तेमाल करते हैं, यह कार उनके नाम पर पंजीकृत नहीं है. कार के सन्दर्भ में बालियान ने अपनी संलिप्तता यह कह कर स्वीकार किया है कि रूबी उनके गांव की बेटी है, आईएएस बनने पर पूरे गांव में मिठाई बटी थी, कार मांगने पर रूबी को अकादमी मेरी सहमती से भेजा गया था. मंत्री जी का यह कथन दाल में काला होने के साथ ही रूबी के उच्चस्थ लोगों से गहरे सम्बन्ध होने की ओर इशारा कर रहा है. लेकिन उन पर आरोप है कि वह पुलिस अधिकारियों को रूबी चौधरी के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर लगातार धमका भी दे रहे हैं. इसी के प्रभाव का असर है कि इस मामले में सब कुछ के बावजूद जांच अधिकारी इस मामले के मुख्यसूत्रधार अकादमी के निदेशक एवं सौरभ जैन को बचाने की हर कोशिश कर रहे हैं.

लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएस) के अंदर रूबी का रुतबा काबिले गौर था. इसे अन्य अधिकारियों की तरह सलामी मिलती थी. हाल यह था कि रूबी जिस कार से गेट के अंदर प्रवेश करती थी, सुरक्षा गार्ड उसे भी सलामी ठोंकते थे. उत्तराखंड पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है. वहां प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों के रिश्तेदारों को भी अंदर आने की भी सामान्य तौर पर इजाजत नहीं थी. इस लिहाज से वहां किसी भी अन्य व्यक्ति के अंदर रहने की संभावना न के बराबर है. इसके बाद भी रूबी के अंदर मौजूद रहने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. जांच में पुलिस को पता चला कि रूबी महंगी कारों से आती थी. इसके साथ कई बार अन्य लोग भी मौजूद रहते थे. अभी तक यह पता नहीं चला कि उसके साथ आने वाले अन्य लोग कौन हैं. वह अकादमी से संबंधित हैं या बाहरी हैं. रूबी के गहन राज से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है. अब उम्मीद है कि एसआईटी के जांच के बाद ही इसमें शामिल बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और पूरी सच्चाई सामने आएगी.

एसआईटी ने अभी तक की जांच के बाद कानून की बारीकियों पर कानून के जानकारों की राय ली. इस मामले में जांच में जुटे अधिकारी अब बयानों का अध्ययन कर रहे हैं. इस मामले में मुकदमा दर्ज हुए लगभग एक महीने बीत गया है. इस दौरान पुलिस स्तर पर भी जांच शुरू हो गई. इस जांच के दौरान पुलिस टीम ने न सिर्फ आरोपी महिला को गिरफ्तार किया, बल्कि उसे पुलिस रिमांड पर भी लिया. रिमांड के दौरान रूबी ने सबूत बरामद कराये या नहीं, पुलिस का दावा सबूत बरामद करने का है. पुलिस अधिकारियों की मानें तो इस मामले में रूबी ने कई अहम सुराग उपलब्ध कराए हैं. यह सबूत मामले को आगे कोर्ट में चलाने के लिये काफी होगा. लेकिन इस जांच को लेकर कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं. इस घटना में बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डालने का आरोप पुलिस पर लग रहा है. इस मामले में सीबीआई जांच की भी आशंका है. इस लिहाज से कागजी खामी छोड़ने के बाद पुलिस अधिकारी लपेटे में आ सकते हैं.

गार्ड पर अधिकारी दबाव डाल रहे हैं

इस मामले में फंस रहे अकादमी के अधिकारी सौरभ जैन की चालाकी ही उनके लिए फांस बनती जा रही है. उसने गार्ड को लगाम लगाने के लिए अदालती नोटिस भेज कर विनाश काले विपरित बुद्धि का परिचय दिया है. एलबीएस प्रकरण की महत्वपूर्ण कड़ी सुरक्षा गार्ड देव सिंह अब खुलकर सामने आ गया है. मसूरी में उसने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अकादमी उस पर लगातार दबाव बना रही है. उसने स्वीकार किया कि रूबी चौधरी उसके कमरे में छह महीने तक रुकी थी, उसने बताया कि रूबी ने सौरभ जैन का लेटर उसे दिखाया था, जिसके आधार पर उसने रूबी को अपने कमरे में रुकने दिया. सुरक्षा गार्ड देव सिंह ने बताया कि सौरभ जैन ने उसे एक करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा है. उसमें एक लाख रुपये का शुल्क अधिवक्ता का अलग से रखा गया है. उसने ये बताया कि इस प्रकार से उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है. यदि इस मामले में उच्चस्तरीय जांच नहीं होती तो वह अपने परिवार के साथ आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएगा. अधिकारियों की भेंट चढ़ा गढ़वाली गार्ड के पक्ष में आम जनता से लेकर भाजपा नेता भी खुल कर उसके पक्ष में आ गए हैं. भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि सच्चाई सामने लाने के लिए सरकार को जांच सीबीआई को सौप देना चाहिए. ■

> जिलाधिकारी सीपी त्रिपाठी के आजमी-रवैये ने आग में घी का काम किया. वाल्मीकियों ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन और आंदोलन शुरू कर दिया और सामूहिक रूप से इस्लाम कबूल करने की घोषणा कर दी. उनका सीधा और स्पष्ट आरोप था कि नगर पालिका के एक अधिकारी ने उनसे धमकाते हुए कहा है कि अगर मुसलमान बन जाओगे तो मकान टूटने से भी बचेंगे और आजम के कहर से भी बचोगे. जबकि आजम खान के लोगों और समर्थकों ने इसे और भड़काने की कोशिश की.

इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर दलित

रामपुर में आजम के खिलाफ बोलना मना है

सूफी यायावर

उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ बड़बोले मंत्री आजम खान अब ऐसे देश की तलाश में हैं जो उन्हें शरण दे सके. पाकिस्तान की तरफ इशारा करने वाले आजम खान शरण लेने के लिए आगे भी नहीं बढ़ रहे. लेकिन उनके इलाके रामपुर में अब ऐसे ही हालात बनाए जा रहे हैं कि जो मुस्लिम होगा, वही रामपुर में रहेगा, अन्यथा उनके घर ढहा दिए जाएंगे और हाथ में सरकार है तो नगर पालिका से या नगर विकास मंत्रालय से कोई नियम निकाल कर उसे आधार बना दिया जाएगा. रामपुर के तोपखाना रोड के पास रहने वाले दलितों के घर तोड़ने का फरमान जारी हो चुका है. उस इलाके में एक मॉल बन रहा है. दलितों के घरों को गैरकानूनी बता कर उसे ध्वस्त करने के नियम-कानून निकाल लिए गए हैं. लेकिन वहां रहने वाले दलितों के 80 परिवारों के दिमाग में यह भी डाल दिया गया है कि अगर वे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें तो उनके घर बच जाएंगे. अब रामपुर में रहना है तो आजम खान के खिलाफ बोलना मना है. आप देख ही रहे होंगे कि रामपुर में किसी ने सार्वजनिक मंच से, सोशल मीडिया से या समाचार माध्यम से आजम की निंदा की तो उसे प्रताड़ित होकर सीधे जेल ही जाना पड़ता है.

रामपुर के वाल्मीकि समुदाय के 80 परिवारों का कहना है कि उन पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है. इन परिवारों का कहना है कि कुछ दिनों पहले नगर पालिका से सिब्ते नबी नाम का एक अफसर वाल्मीकि बस्ती में आया था और उसने 55 घरों पर निशान लगा दिए थे. नगर पालिका के उस अफसर का कहना था कि निशान वाले घर अतिक्रमण के दायरे में आते हैं और सड़क को चौड़ा करने के लिए उन्हें तोड़ दिया जाएगा. बस्ती वालों के मुताबिक सिब्ते नबी ने उनसे कहा था कि अगर वे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें तो उनके घर बच सकते हैं. बस्ती वालों का आरोप है कि सिब्ते नबी उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान का करीबी है. दलितों ने यह भी कहा कि उनके घर उजाड़ने की कार्रवाई और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के पीछे आजम खान का हाथ है. गांधी मॉल आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है. इसी मॉल के पास मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है. आजम खान इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं. उत्तर प्रदेश के नगर निगम और नगर पालिकाएं आजम खान के नगर विकास मंत्रालय के तहत ही आती हैं.

अपने घरों को बचाने के लिए वाल्मीकि बस्ती के लोग आमरण अनशन और धरने पर बैठ गए हैं. हालांकि दबाव में वे इस्लाम धर्म तक स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. लेकिन इस मामले के तूल पकड़ते ही आजम खान बचाव की मुद्रा में आ गए और शरण लेने के लिए कोई उपयुक्त देश तलाशने जैसे बयान जारी करने लगे. मामला उलझता जा रहा है. मौलाना फुरकान रजा ने कहा कि उन्हें पता चला कि वाल्मीकि बस्ती के लोग लालच या दबाव के चलते इस्लाम अपनाना चाहते हैं. उन्होंने शहर काजी से इस बारे में फोन पर बात की है. मौलवी ने कहा कि शहर काजी ने भी कहा है कि कभी भी लालच में आकर या दबाव देकर मजहब नहीं बदला या बदलवाया जाना चाहिए. वाल्मीकि बस्ती के मकान तोड़े जाने से लेकर बचाने तक को लेकर राजनीति तेज हो गई है. वाल्मीकि बस्ती की तरफ जाना चाह रहे भाजपा नेताओं को पुलिस वहां जाने नहीं दे रही है. नोंकझोंक और विरोध के बाद भाजपा नेताओं को वापस लौटना पड़ रहा है. भाजपा नेता भारत भूषण गुप्ता ने कहा कि दलितों की आवाज दबाकर लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दलितों के मकान किसी भी कीमत पर नहीं टूटने दिए जाएंगे. भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के जिला सचिव सरन लाल वाल्मीकि ने कहा कि रामपुर का वाल्मीकि समाज किसी भी नेता के बहकावे में न आए. सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर भी वाल्मीकि बस्ती को बचाने के लिए आयोजित धरना-प्रदर्शन में शामिल हुईं. उन्होंने कहा कि रामपुर में देश का संविधान नहीं चलता है. नूतन ठाकुर ने कहा, नगर पालिका को कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान का संरक्षण मिला हुआ है. रामपुर में लोकतंत्र को पूरी तरह दबा दिया गया है. सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी भी दिल्ली से रामपुर पहुंच गईं. उन्होंने पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से बात की. शबनम ने दावा किया है कि उन्हें डीएम ने आश्वासन दिया है कि वाल्मीकि बस्ती के घर अभी नहीं टूटेंगे. डीएम ने शबनम हाशमी को यह नहीं बताया कि वाल्मीकि बस्ती के घर कब टूटेंगे.

इन सारी सियासत के बावजूद रामपुर के उन दलितों में यह बात घर कर गई है कि इस्लाम कबूल कर लेने से आजम खान उनके घर बख्श देंगे. इसका असर यह हुआ कि जिला प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी आंदोलनकारी वाल्मीकि समाज के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की. दरअसल, रामपुर में तोपखाना रोड स्थित नवनिर्मित शॉपिंग मॉल से ही सारा झमेला जुड़ा हुआ है. मॉल के पास बनी वाल्मीकि बस्ती पर आजम खान के इशारे पर नगर पालिका मॉल की पार्किंग बनाना चाहती है. वाल्मीकि बस्ती से अतिक्रमण हटाने के लिए गिराने वाले करीब 80 घरों पर नगर पालिका द्वारा निशान लगाए जाने और इस्लाम धर्म अपनाने की सलाह देने के कारण ही मामले ने तूल पकड़ लिया है. नगर पालिका की इस कार्रवाई और अफसर के भड़काने के खिलाफ वाल्मीकियों ने जुलूस निकाला और आजम विरोधी नारे लगाए. आजम खान के शहर में आजम का विरोध समाजवादियों को नागवार गुजरा और उन्होंने वाल्मीकियों पर ही कार्रवाई की मांग करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. रामपुर के जिलाधिकारी ने भी फौरन कार्रवाई करते हुए 85 वाल्मीकियों के खिलाफ सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा ठोक दिया.

जिलाधिकारी सीपी त्रिपाठी के आजमी-रवैये ने आग में घी का काम किया. वाल्मीकियों ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन और आंदोलन शुरू कर दिया और सामूहिक रूप से इस्लाम कबूल करने की घोषणा कर दी. उनका सीधा और स्पष्ट आरोप था कि नगर पालिका के एक अधिकारी ने उनसे धमकाते हुए कहा है कि अगर मुसलमान बन जाओगे तो मकान टूटने से भी बचेंगे और आजम के कहर से भी बचोगे. जबकि आजम खान के लोगों और समर्थकों ने इसे और भड़काने की कोशिश की. आज़म खान के प्रवक्ता मुहम्मद शानू ने कह दिया कि सरकारी जमीन से अनधिकृत कब्जा हटवाया जा रहा है और इसमें धर्म या जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा रहा. आजम के इस बयान को लेकर एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल ने भी खूब पतंग उड़ाई और दलितों के व्यापक हित की अनदेखी करते हुए आजम की चापलूसी में टीवी चैनल पर राग-दरबारी गाने का कमाल दिखाया. रामपुर के दलित राजकुमार वाल्मीकि ने उक्त न्यूज चैनल को आजम का पिट्ठू बताते हुए कहा कि ये सब हमें धर्म परिवर्तन के लिए विवश कर रहे हैं. एक अन्य निवासी अविनाश तपन कहते हैं कि वे लोग आत्मदाह भी कर सकते हैं, ताकि माननीय मंत्री को उन पर दया आ जाए. रामचंद्र वाल्मीकि कहते हैं कि अब उन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है. दरअसल, रामपुर के तोपखाना इलाके में रहने वाले इन वाल्मीकि परिवारों को रामपुर म्युनिसिपल बोर्ड ने घर खाली करने का आदेश दिया था, ताकि गांधी मॉल के लिए सड़क चौड़ी की जा सके. बोर्ड का मानना है कि वाल्मीकि समुदाय के लोग सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करके रह रहे हैं, जबकि वाल्मीकियों का कहना है कि उनके मकान पूरी तरह वैध हैं और वे गृह और पानी का कर भी अदा कर रहे हैं. उनका कहना है कि खुद बोर्ड ने उनके मकानों के लिए स्वीकृति दी थी और उनके पास सभी सबूत मौजूद हैं. वाल्मीकि बस्ती के लोगों की बात पूरी तरह जायज़ है. कई दशकों से ये लोग पक्के मकान बना कर रह रहे हैं. उनके वोटर आईडी बने हुए हैं. सभी के पास सरकारी दस्तावेज़ हैं और नगर पालिका ने ही उन्हें बाकायदा मकान नंबर भी दे रखे हैं.

कांग्रेस के नगर सचिव फ़ैसल ख़ान लाला कहते हैं कि आज़म खान की मॉल में विशेष रुचि है. इस विशेष रुचि के लिए वे किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं. याद रहे कि फैसल खान लाला उस स्कूली छात्र के पक्ष में खड़े हुए थे जिसे आज़म खान ने फ़ेसबुक पर टिप्पणी के बाद जेल भिजवा दिया था. लाला आज भी उसका खामियाज़ा भुगत रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि भाजपा वाल्मीकियों को उजाड़े जाने का संसद से सड़क तक विरोध करेगी. विश्व हिन्दू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने कहा कि आजम खान रामपुर को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं. वहां यदि एक भी धर्म परिवर्तन हुआ तो रामपुर में ही आकर ईंट से ईंट बजा देंगे. साध्वी प्राची ने भी रामपुर वाल्मीकि बस्ती जाने की कोशिश की, लेकिन गांधी समाधि पर ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया. कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. साध्वी ने विरोध किया, पर उन्हें भी वहां से वापस लौट जाना पड़ा.

बहरहाल, परिदृश्य यह है कि रामपुर में अघोषित कर्फ्यू लागू है और पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी बना हुआ है. खबरें और अफवाहें घुलमिल गई हैं. लोगों का यह भी कहना है कि वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने अंबेडकर जयंती के दिन सामूहिक रूप से इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया. लेकिन आधिकारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है. इस्लाम धर्म कबूल करने की बातों के साथ-साथ यह खबर भी पहुंची कि उन्हीं दलित समुदाय के लोगों ने राष्ट्रपति को पत्र लिख कर इच्छा-मृत्यु की इजाजत देने की भी मांग की है. वाल्मीकी समाज के 80 परिवारों का आमरण अनशन खबर लिखने तक जारी था. आमरण अनशन पर बैठे लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए प्रशासन का कोई नुमाइंदा मौके पर नहीं पहुंचा था. वाल्मीकि समुदाय की महिलाओं ने भी जल्दी ही आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है. वाल्मीकि समाज के संगठनों ने रामपुर समेत मुरादाबाद व बरेली मंडल में सफाई का काम ठप्प कर देने का ऐलान कर दिया है. रामपुर में जगह-जगह कूड़े के अम्बार देखे जा सकते हैं. रामपुर में ही आजम खान का पुतला भी फूंका गया. प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एके जैन इस मामले में कोई उचित कार्रवाई की पहल करने के बजाय मीडिया को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. ■

रामपुर के वाल्मीकि समुदाय के 80 परिवारों का कहना है कि उन पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है. इन परिवारों का कहना है कि कुछ दिनों पहले नगर पालिका से सिब्ते नबी नाम का एक अफसर वाल्मीकि बस्ती में आया था और उसने 55 घरों पर निशान लगा दिए थे. नगर पालिका के उस अफसर का कहना था कि निशान वाले घर अतिक्रमण के दायरे में आते हैं और सड़क को चौड़ा करने के लिए उन्हें तोड़ दिया जाएगा.

यह कैसा धर्म परिवर्तन

रामपुर के वाल्मीकि समुदाय के लोगों पर दबाव या खौफ इस कदर था कि धर्म परिवर्तन के लिए कोई मौलाना नहीं मिला तो खुद ही टोपी पहन कर कह दिया कि वे मुसलमान हो गए. मौलाना फुरकान रजा ने कहा कि लालच या डर में इस्लाम अपनाना गुनाह है. वाल्मीकि समुदाय के लोग अपनी बस्ती को बचाने के लिए इस्लाम कबूल करना चाहते थे, इसलिए मैंने उनका आग्रह स्वीकार नहीं किया. वाल्मीकि समुदाय के लोगों के घर ढहाने पर आमादा रामपुर के जिलाधिकारी सीपी त्रिपाठी ने कहा कि इन लोगों को यहां से हटाकर कांशीराम आवास योजना में घर दिया जा रहा है. ये लोग कोर्ट से मुकदमा हार गए हैं और अब बस्ती खाली करवाई जाएगी.

आज़म खान के खिलाफ जनहित याचिका

सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आज़म खान द्वारा बिना किसी नियम, शर्त और प्रक्रिया के राज्य सरकार के अल्प संख्यक विभाग के मौलाना जौहर अली शोध संस्थान रामपुर की बेशकीमती भूमि और भवन को स्वयं की निजी संस्था मौलाना जौहर अली ट्रस्ट को मात्र 100 रुपये वार्षिक लीज पर लिए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि आज़म खान ने निजी लोगों को सरकारी भूमि दिए जाने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौरभ गांगुली, सुभाष घई और कुशाभाई ठाकरे ट्रस्ट मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों को तार-तार करते हुए बीच शहर में करीब 1500 वर्गगज जमीन और उस पर 9.83 करोड़ में बने सरकारी भवन को अपनी निजी संस्था को दिए जाने का फैसला करा लिया जो पद का सीधा दुरुपयोग है. तत्कालीन प्रमुख सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने भी इसे हितों का टकराव बताते हुए सरकारी भूमि और भवन विभागीय मंत्री की निजी संस्था को देने का विरोध किया था. इस पर बाद में उन्हें विभाग से ही हटा दिया गया और सरकारी मशीनरी पर दवाब डाल कर यह विधि-विरुद्ध फैसला कराया गया. याचिका में इस आवंटन को निरस्त करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है.

feedback@chauthiduniya.com